YouTube kanwhizztimes
@kanwhizztimes
@kanwhizztimes
www.kanwhizztimes.com

कैनविज टाइम्स
सिर्फ सच

❒ वर्ष-14 ❒ अंक-145 ❒ शुक्रवार, 27 जून 2025 ❒ नगर संस्करण ❒ लखनऊ से प्रकाशित एवं दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड में प्रसारित ❒ मूल्य- ₹ 3.00 ❒ पृष्ठ-12

वन्देमातरम कोई कविता नहीं पूरे भारत के लिए वह महामंत्र है जिसने हमें अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने और भारत के तिरंगे का मान बढ़ाने का काम किया। इस महामंत्र को गाते हुए वीर क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। केशव प्रसाद मौर्य

सत्ता के मद के आगे प्रेस, न्यायपालिका को नहीं झुकना चाहिए : होसबाले 11

पंजाब कैबिनेट ने दी औद्योगिक प्लॉट हस्तांतरण नीति को मंजूरी 12

संक्षेप

अभ्युदय कोचिंग में रिकार्ड 30 हजार युवाओं ने पंजीकरण कराया

लखनऊ। एक जुलाई से अभ्युदय कोचिंग का नया सत्र शुरू होगा। अबकी रिकार्ड 30 हजार युवाओं ने मुफ्त कोचिंग की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण कराया है। प्रदेश के 162 कोचिंग सेंटरों पर विशेषज्ञों की मदद से युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी कराई जा रही है। अभ्युदय कोचिंग से बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को सफलता मिल रही है, जिसके चलते छात्रों का तेजी से रूझान बढ़ रहा है। समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। बीते वर्ष 25 हजार युवाओं ने अभ्युदय कोचिंग में पंजीकरण कराया था। राजधानी में 11 केंद्र संचालित किए जा रहे हैं और यहां पर सबसे ज्यादा आवेदन आए हैं। 25 जिलों में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। छात्रों को सिविल सर्विसेज, नीट, जेईई मेंस व एडवांस, बैंकिंग व एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। वरिष्ठ आईएएस, आईपीएस व पीसीएस अधिकारी फैकल्टी के रूप में इन कोचिंग सेंटरों में क्लास लेकर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यही नहीं ऑनलाइन स्ट्डी मैटेरियल भी युवाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का सिलेबस और प्रश्न बैंक भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

सिंधु जल संधि पर रोक पर भारत अडिग : पाटिल

नयी दिल्ली। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने सिंधु जल संधि पर रोक लगाने के भारत के रुख को दोहराते हुए आज कहा कि यह निर्णय हमारे राष्ट्रीय हितों को पूरा करता है और इसको लेकर जो फैसला भारत सरकार ने लिया है वो सही है। श्री पाटिल ने गुरुवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से जो धमकियां आ रही हैं वे निराधार हैं और उनसे कोई फर्क भारत को नहीं पड़ता है। उनका यह भी कहना था कि दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संधि के संबंध में जो भी निर्णय होगा वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार द्वारा ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा, ''संधि की स्थिति पर कोई अपडेट नहीं है। इस संबंध में लिया गया कोई भी निर्णय केवल देश के हित में ही होगा।'' पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की हालिया टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर श्री पाटिल ने कहा ''पानी कहीं नहीं जाएगा। उनकी टिप्पणियाँ उनकी अपनी चिंताएँ हैं। हम खोखली धमकियों से नहीं डरते। हम गीदड़ भभकियों से नहीं डरते। मोदी सरकार ने पहले भी दशकों पुरानी सिंधु जल संधि के तहत अपने दायित्वों को निलंबित करके एक आतंकवादी हमले का जवाब दिया था।

शुभांशु शुक्ला का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हुई एंट्री

मंगल यात्रा

❒ लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद एक्सिओम-4 मिशन को लेकर ड्रैगन अंतरिक्ष यान अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा

❒ एक्सिओम मिशम के तहत अंतरिक्ष यात्री अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 14 दिन बिताएंगे और इस दौरान 60 प्रयोग करेंगे

एजेंसी

फ्लोरिडा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और अन्य यात्रियों को लेकर स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गया है। अंतरिक्ष यान करीब 28.5 घंटे की यात्रा के बाद 26 जून गुरुवार को भारतीय समय के अनुसार शाम करीब 4:01 बजे आईएसएस से जुड़ा। डॉकिंग अनुक्रम भारतीय समयानुसार शाम 4:15 बजे पूरा हुआ। अंतरिक्ष यान के सॉफ्ट कैप्चर के बाद हार्ड-मेटिंग तब पूरी हुई जब दोनों ऑर्बिट बॉडी 12 हुक के सेट के साथ एक दूसरे से जुड़ गई और उनके बीच संचार और पावर लिंक स्थापित किए गए। यह पहली बार है जब कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा पर गया है।

अंतरिक्ष यात्रियों के अंतरिक्ष स्टेशन पर चढ़ने से पहले हैच खोलने की प्रक्रिया में लगभग दो घंटे लगते हैं। अनुभवी अंतरिक्ष यात्री पैगी व्हिटसन मिशन कमांडर हैं और शुक्ला एक्सिओम-4 मिशन के लिए मिशन पायलट हैं। स्पेसएक्स के फाल्कन-9 रॉकेट ने बुधवार दोपहर 12:01 बजे एक्सिओम-4 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर फ्लोरिडा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से आईएसएस के लिए सफल उड़ान भरी थी। स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल की सफल डॉकिंग पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, बधाई हो...एक्सिओम-4 डॉकिंग सफल रही। शुभांशु अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के द्वार पर खड़े हैं। भीतर कदम रखने के लिए तैयार, 14 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा शुरू होने वाली है..और पूरा विश्व उत्साह और अपेक्षा के साथ देख रहा है।

भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के लिए सफल उड़ान भरने के साथ ही नया इतिहास रच दिया। तीन अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रवाना हुए शुभांशु की यह यात्रा 41 साल बाद किसी भारतीय की पहली अंतरिक्ष यात्रा है। आईएसएस की यात्रा करने वाले वह पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। उनसे पहले 1984 में राकेश शर्मा रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज के जरिये अंतरिक्ष में गए थे। शुभांशु शुक्ल इस मिशन में पायलट के तौर पर आईएसएस भेजे जा रहे हैं। यानी जिस ड्रैगन कैप्सूल के जरिए एग्जियोम-4 मिशन को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (आईएसएस) रवाना किया जाएगा, शुभांशु उसको गाइड करने (नैविगेशन) में अहम भूमिका निभाएंगे। यहां स्पेसक्राफ्ट को आईएसएस पर डॉक कराने से लेकर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाने तक की जिम्मेदारी शुभांशु के ही कंधों पर होगी। इसके अलावा अगर यह कैप्सूल किसी तरह की दिक्कत में आता है तो शुभांशु के पास ही यान का कंट्रोल और आपात फैसले लेने की जिम्मेदारी होगी। कुल मिलाकर शुभांशु इस मिशन में सेकंड-इन-कमांड की भूमिका में होंगे। पेगी व्हिट्सन के बाद वे एग्जियोम-4 का सबसे अहम केंद्र होंगे। एग्जियोम मिशन के तहत आईएसएस में कुल 14 दिन बिताएंगे।

आतंकवाद के मुद्दे पर एससीओ डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करने से भारत का इनकार

शांति-समृद्धि और आतंकवाद साथ-साथ नहीं चल सकते

एजेंसी

नई दिल्ली। चीन के किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने गए राजनाथ सिंह ने एससीओ संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। इसके पीछे उनका तर्क है कि आतंकवाद के मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान ने हमेशा सख्त रुख अपनाने के बजाय नरम रवैया अपनाया है। यह मतभेद इसलिए भी था, क्योंकि मसौदे में आतंकवाद को ठीक तरीके से परिभारित नहीं किया गया था।

किंगदाओ में एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित समूहों को दोषी ठहराया, जिसमें 26 नागरिक मारे गए। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन 'सिंदूर' शुरू करके सैन्य प्रतिक्रिया दी। उनके इस बयान ने भारत के दृढ़ आतंकवाद विरोधी रुख, एससीओ से कार्रवाई की मांग और रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले का पैटर्न भारत में लश्कर के पिछले आतंकवादी हमलों से मेल खाता है। भारतीय अधिकारियों के अनुसार इस बयान पर हस्ताक्षर करने से आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भारत की स्थिति कमजोर हो जाती। यह मतभेद इसलिए भी था, क्योंकि मसौदे में आतंकवाद को ठीक तरीके से परिभाषित नहीं किया गया था। राजनाथ सिंह का कहना था कि दस सदस्यीय समूह में पाकिस्तान, चीन और रूस भी शामिल हैं, लेकिन इन देशों ने कोई अंतिम घोषणा पत्र नहीं जारी किया। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान का सीधे नाम लिए बिना कहा कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ऐसे दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए।

❒ चीनी रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता में हॉटलाइन फिर से शुरू करने पर हुई चर्चा

गलवान घाटी के जून, 2020 में संघर्ष के बाद रक्षा मंत्री की यह पहली चीन यात्रा थी। राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों पक्षों ने भविष्य में सीमा पर तनाव से बचने के लिए भारत-चीन हॉटलाइन को फिर से शुरू करने की संभावना सहित सैन्य संचार तंत्र पर चर्चा की। हालांकि, कोई बड़ी बातचीत नहीं हुई, लेकिन इस बैठक को इस बात का संकेत माना गया कि तनाव के बावजूद बातचीत का रास्ता खुला है। एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल का समर्थन करने वाली भाषा का समर्थन करने से इनकार कर दिया। इसी तरह भारत ने ब्रिक्स मुद्रा बास्केट शुरू करने के बीजिंग के प्रयास का विरोध किया। इन कदमों के माध्यम से भारत ने संकेत दिया है कि रणनीतिक स्वायत्तता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। अपने संबोधन में सिंह ने कहा कि कुछ देश आतंकवादियों को पनाह देने के लिए सीमा पार आतंकवाद का इस्तेमाल ''नीतिगत साधन'' के रूप में कर रहे हैं। सिंह एससीओ के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुधवार को चीन के बंदरगाह शहर किंगदाओ पहुंचे थे। उन्होंने कहा, हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी से संबंधित हैं। सिंह ने कहा, ''और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ती कट्टरता, उग्रवाद और आतंकवाद है। सिंह ने कहा कि शांति-समृद्धि और आतंकवाद साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि सरकार से इतर तत्वों और आतंकवादी समूहों के हाथों में सामूहिक विनाश के हथियार सौंपने के साथ भी शांति कायम नहीं रह सकती। रक्षा मंत्री ने कहा, इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक ● शेष पेज 11 पर

हिंदी भारतीय भाषाओं की सखी, विरोधी नहीं : शाह

एजेंसी

नयी दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह ने हिंदी को भारतीय भाषाओं की सखी करार देते हुए कहा है कि देश की सभी भाषाओं को सशक्त बनाने की जरूरत है क्योंकि हमारी भाषाएं देश को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है।

श्री शाह ने गुरुवार को यहां राजभाषा विभाग के 'स्वर्ण जयंती समारोह' को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की विरोधी नहीं हो सकती। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है और हिंदी तथा भारतीय भाषाएं मिलकर ही हमारे आत्मगौरव के उत्थान के कार्यक्रम को अंतिम लक्ष्य तक ले जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसी वर्ष भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की है

और यह अनुभाग हर राज्य को इस काम के लिए सहायता करेगा कि राज्यों और भारत सरकार का प्रशासन भारतीय भाषाओं के आधार पर ही हो। देश में 12 भाषाओं में तकनीकी शिक्षा की शुरूआत हुई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने हिंदी में मेडिकल शिक्षा की शुरूआत की है, पूरा पाठ्यक्रम बनाया है और आने वाले दिनों में अन्य राज्य भी भी मेडिकल शिक्षा का पूरा पाठ्यक्रम अपनी भाषाओं में तैयार कर बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराएंगे। श्री शाह ने कहा कि कोई भी देश अपनी भाषा के बिना अपनी संस्कृति, साहित्य, इतिहास और सामाजिक संस्कार को चिरंजीव नहीं रख सकता। अपनी संस्कृति के आधार पर आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए देश का शासन उसकी अपनी भाषाओं में होना चाहिए और इस महान उद्देश्य के साथ राजभाषा विभाग की शुरूआत हुई थी। राजभाषा की 50 वर्ष की यात्रा आज एक ऐसे मुकाम पर खड़ी है जब हमें इसे आगे ले जाने का प्रयास और पूरा रास्ता तय करना है। उनका कहना था कि राजभाषा विभाग की 50 साल की इस यात्रा को स्वर्णिम अक्षरों ● शेष पेज 11 पर

वैवाहिक मामलों में मध्यस्थता की अवधारणा को लेकर गलतफहमी है : न्यायालय

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वैवाहिक मामलों में मध्यस्थता की अवधारणा के बारे में 'गलतफहमी' है और अक्सर मध्यस्थता का मतलब यह माना जाता है कि दोनों पक्षों को एक साथ रहना होगा।

न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह ने एक स्थानांतरण याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा, ''वैवाहिक मामलों में हमने पाया है कि मध्यस्थता की अवधारणा को लेकर गलतफहमी है।'' उन्होंने कहा, ''जैसे ही हम मध्यस्थता की बात करते हैं, उन्हें लगता है कि हम उन्हें साथ रहने के लिए कह रहे हैं। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वे साथ हैं या अलग। हम बस मामले का हल चाहते हैं। हम चाहेंगे ● शेष पेज 11 पर

चुनाव आयोग ने 345 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों को सूची से हटाया

एजेंसी

नयी दिल्ली। चुनाव आयोग ने ऐसे 345 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की पहचान कर उनको सूची से हटाने का काम शुरु कर दिया है जो पिछले छह वर्षों में एक भी चुनाव लड़ने की आवश्यक शर्त को पूरा करने में विफल रहे हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने मिलकर 345 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। इस दायरे में वे सभी राजनीतिक दल होंगे जो 2019 से कहीं भी सक्रिय नहीं हैं। ये सभी पंजीकृत गैर-मान्यताप्राप्त

दल देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद हैं। आयोग ने कहा है कि उसके संज्ञान में आया है कि वर्तमान में आयोग के पास 2,800 से अधिक पंजीकृत गैर मान्यताप्राप्त दल हैं जो शर्तो को पूरा नहीं करते हैं लेकिन उसने देशव्यापी अभियान चलाकर अब तक 345 ऐसे दलों की पहचान की गई है जो सूची में बने रहने के पात्र नहीं हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए ● शेष पेज 11 पर

अहमदाबाद विमान हादसा

सीवीआर-एफडीआर के डाटा की जांच पूरी, निष्कर्ष शीघ्र

एजेंसी

नयी दिल्ली। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान के कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर्स (सीवीआर) और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स (एफडीआर) का डाटा प्रयोगशाला में निकाल लिया गया है और जल्द ही इसका निष्कर्ष सामने आने की संभावना है। नागर विमानन मंत्रालय ने आज यहां एक बयान में यह जानकारी दी। भारत, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) की शिकागो संधि (1944) के हस्ताक्षरकर्ता और आईसीएओ अनुलग्नक 13 और विमान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियम, 2017 के अनुसार विमान दुर्घटनाओं की जांच करता है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) ऐसी जांच के लिए नामित प्राधिकरण है। बयान

में कहा गया है कि एयर इंडिया फ्लाइट एआई-171 से जुड़ी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बाद, एएआईबी ने तुरंत एक जांच शुरू की और निर्धारित मानदंडों के अनुरूप 13 जून को एक बहु-विशेषज्ञ दल का गठन किया। अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार गठित टीम का नेतृत्व एएआईबी के महानिदेशक द्वारा किया जाता है, और इसमें एक विमानन चिकित्सा विशेषज्ञ, एक एटीसी अधिकारी और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (एनटीएसबी) के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो ● शेष पेज 11 पर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में सीईएल-ईएसडीएस ग्रीन डेटा सेंटर का किया शिलान्यास

डाटा सेंटर और ग्रीन एनर्जी में अग्रणी भूमिका निभा रहा सीईएल: योगी

एजेंसी

गाजियाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा भारत सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को गाजियाबाद के साहिबाबाद में सीईएल-ईएसडीएस ग्रीन डेटा सेंटर का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीईएल द्वारा विकसित हो रहे नए ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर पर प्रसन्नता जताई और कहा कि यह प्रधानमंत्री के 2070 तक नेट ज़ीरो के संकल्प की ओर एक मजबूत कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि 2027 तक उत्तर प्रदेश 20,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पन्न करेगा, जिसमें सीईएल की भूमिका प्रमुख होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीईएल की यात्रा को भारत के औद्योगिक पुनरुत्थान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री मोदी के 2047 के विकसित भारत विजन का प्रमुख स्तंभ बताया और कहा कि सीईएल जैसे संस्थानों के माध्यम से ही नया भारत अपनी शक्ति, तकनीक और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है।

❒ सीईएल जैसे संस्थानों के माध्यम से ही नया भारत अपनी शक्ति, तकनीक और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा

❒ योगी ने नए ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर को पीएम मोदी के 2070 तक नेट ज़ीरो के संकल्प की ओर मजबूत कदम करार दिया

❒ 2027 तक उत्तर प्रदेश 20,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पन्न करेगा, जिसमें सीईएल की भूमिका प्रमुख होगी

❒ ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइल पाकिस्तान में टेस्टेड और दुनिया में ट्रस्टेड: मुख्यमंत्री

गाजियाबाद में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्वर्ण जयंती समारोह एवं डाटा सेंटर के शिलान्यास के अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना में हिस्सा लिया और प्रदर्शनी का भी

अवलोकन किया जहां पर उन्हें डाटा सेंटर और इसकी कार्यप्रणाली के विषय में जानकारी दी गई। उन्होंने प्रांगण में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण भी किया। कार्यक्रम में सीईएल की ओर से भारत सरकार को लगभग 21 करोड रुपए के लाभांश का चेक भी भेंट किया गया, जबकि सीईएल और मल्टी इंफ्रा के बीच 200 मेगावाट सोलर मॉड्यूलर के लिए एमओयू भी हस्तांतरित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) की 50 वर्षों की यात्रा को एक सक्सेस स्टोरी बताते हुए कहा कि यह संस्थान अब 'अमृत काल' में प्रवेश कर चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। सीईएल की स्वर्ण जयंती पर आयोजित समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ऐसा भी समय था जब अंधकार के बादल मंडरा रहे थे, सीईएल को डिसइनवेस्टमेंट की सूची में डाल दिया गया था। लेकिन आज वही सीईएल एक लाभ कमाने वाली मिनी रत्न कंपनी बन गई है और केंद्र सरकार को लाभांश का चेक सौंप चुकी है। यह परिवर्तन आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रेरणास्त्रोत है। मुख्यमंत्री ने सीईएल द्वारा रेलवे, रक्षा, अक्षय ऊर्जा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में किए गए नवाचारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि संस्था की प्रौद्योगिकी और इनोवेशन देश को मजबूती दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सीईएल द्वारा स्मार्ट क्लासरूम, सिग्नलिंग सिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी मॉड्यूल और डिफेंस उपकरणों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का पहला सोलर फोटोवोल्टिक माड्यूल सीईएल ने तैयार किया था और आज वह भारत का पहला ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर भी स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े उपकरण भी सीईएल जैसे संस्थानों के सहयोग से ही ● शेष पेज 11 पर

हरित उत्तर प्रदेश के लिए योगी सरकार ने बढ़ाया दूरदर्शी कदम

कैनविज टाइम्स संवाददाता

1 से 7 जुलाई 2025 में जन्म लेने वाले बच्चों को दिए जाएंगे पौधे

नवजात शिशुओं को ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट व पौध भी देगी योगी सरकार

नवजात के जीवन को खुशमय बनाने, हरियाली बढ़ाने, परिवार को पौध लगाने व संरक्षित करने के लिए सरकार का जोर

लखनऊ। योगी सरकार ने यूपी को हरित प्रदेश बनाने के लिए दूरदर्शी कदम बढ़ाया है। पहली से सात जुलाई 2025 तक जन्म लेने वाले बच्चों को अब ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट के साथ पौधे भी दिए जाएंगे। यह पौधे यूपी के सभी जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी व अन्य सरकारी अस्पताल में जन्मे बच्चों को प्रदान किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए वन विभाग इसे मूर्त रूप प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य नवजात के जीवन को खुशमय बनाने के साथ प्रदेश में हरियाली बढ़ाने, परिवार को पौध लगाने व संरक्षित करने के लिए प्रेरित करना है।

योगी सरकार के निर्देश पर समूचे प्रदेश में वर्षाकाल-2025 में पौधरोपण महाभियान चलेगा। इस दौरान 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सर्वाधिक पौधरोपण का लक्ष्य लखनऊ मंडल को दिया गया है। इस बार त्रिवेणी वन की स्थापना और संरक्षण पर सरकार का जोर है। इसके साथ ही महापुरुषों के नाम पर भी वन वाटिका लगाई जाएगी। सर्वाधिक पौधे शीशम व सागौन प्रजाति के लगाए जाएंगे।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक व विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी ने बताया कि पौधरोपण महाभियान-2025 में जनसमुदाय की सहभागिता पर सरकार का जोर है। नवजात को उपहार स्वरूप पौधा देना बच्चे के जीवन में समृद्धि व विकास का परिचायक है। इसी के अनुरूप पहली से सात जुलाई (वन महोत्सव) की अवधि में जन्मे नवजात शिशुओं को ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट के साथ एक पौधा भेंट के रूप में प्रदान किया जाएगा। वन महोत्सव के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर वन विभाग मूर्त रूप प्रदान करेगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक व विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी ने सभी प्रभागों के वनाधिकारी को निर्देश दिया है कि स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर संस्थागत प्रसव से जन्मे बच्चों को यह सर्टिफिकेट व पौधा दिया जाए। संस्थागत प्रसव में जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी व अन्य सरकारी अस्पतालों को शामिल किया जाए। भेंट स्वरूप सागौन, शीशम समेत इमारती प्रजाति के पौधों को प्राथमिकता दी जाए। अभिभावकों को खाली स्थानों पर पेड़ लगाने के संबंध में जानकारी दी जाए। एक से सात जुलाई तक जन्मे बच्चों को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी व अन्य सरकारी अस्पतालों में जाकर जो सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, उसे ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों के साथ ही रोपित पौधे की समुचित देखभाल व संरक्षण के लिए अभिभावकों को प्रोत्साहित करना भी है।

अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर सीएम योगी करेंगे कई योजनाओं का शुभारंभ

कैनविज टाइम्स संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने के लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रही योगी सरकार प्रदेश में एमएसएमई इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा प्रयास करने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के मौके पर शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय भव्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक कई बड़ी घोषणाएं और लोकार्पण करेंगे। रोजगार, उद्यमिता और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने वाली योजनाओं को गति देने वाले इस कार्यक्रम में युवाओं और कारीगरों को विशेष लाभ मिलेगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को बढ़ावा देने, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और पारंपरिक उद्योगों को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से आयोजित यह कार्यक्रम कई मायनों में विशिष्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर एमएसएमई क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करना है। ऐसे में, योगी सरकार इस अवसर को स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के मंच के रूप में उपयोग कर रही है।

लोकभवन सभागार में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सीएम योगी द्वारा CM-YUVA मोबाइल ऐप का बटन दबाकर शुभारंभ किया जाएगा। यह युवाओं के लिए रोजगार, परामर्श और उद्यमिता से जुड़ी सुविधाएं प्रदान करने का माध्यम बनेगा। इसी अवसर पर योजना पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी होगा, जो योजना की विशेषताओं को दर्शाएगी। बरेली और मुरादाबाद जनपदों में तैयार कॉमन फैसिलिटी सेंटर परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन भी सीएम योगी द्वारा किया जाएगा।

वहीं, अलीगढ़ के ख्यामई में अवस्थापना सुविधाओं से जुड़ी परियोजना के 5 लाभार्थियों को आवंटन पत्र प्रदान किए जाएंगे। लखनऊ के किसान बाजार में विकसित 'यूथ अड्डा' का भी सीएम योगी द्वारा लोकार्पण किया जाएगा, जो युवाओं को सीखने, संवाद करने और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने का केंद्र बनेगा। कार्यक्रम के दौरान एमएसएमई नीति, योजना और रोजगारपरक अन्य योजनाओं के अंतर्गत चयनित 15 लाभार्थियों को चेक एवं टूलकिट का वितरण किया जाएगा। इनमें से प्रत्येक योजना के 5-5 लाभार्थी शामिल होंगे। साथ ही, ग्क्ष् योजना के तहत 5 कारीगरों को टूलकिट भी वितरित की जाएंगी। राज्य के विशिष्ट उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में ह्यूमन वेलफ़ेयर एसोसिएशन और उद्योग विभाग के आयुक्त एवं निदेशक के बीच एमओयू का आदान-प्रदान किया जाएगा, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक उत्पादों को जीआई टैग दिलवाना है।

ट्रांसजेंडर्स को सीएम युवा अभियान से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी योगी सरकार

कैनविज टाइम्स संवाददाता

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल करने जा रही है। अब ट्रांसजेंडर्स को सीएम युवा अभियान से जोड़ा जाएगा, जिसके तहत उन्हें कौशल के आधार पर प्रशिक्षण और ऋण सहायता दी जाएगी। यह पहल ट्रांसजेंडर समुदाय को केवल आर्थिक रूप से मजबूत नहीं करेगी, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में भी निर्णायक भूमिका निभाएगी।

योगी सरकार की मंशा है कि समाज में लंबे समय से उपेक्षित रहे ट्रांसजेंडर समुदाय को न केवल गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर मिले, बल्कि वे सम्मान और अधिकार के साथ आत्मनिर्भर बनें। इसी उद्देश्य से समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने विभाग को प्रदेश के प्रत्येक जिले में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत हर जिले में कम से कम दो ट्रांसजेंडर्स को रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे यह प्रयास एक जनांदोलन का रूप में आगे बढ़ सके। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी सीएम युवा प्रदेश के नवयुवाओं को रोजगार और व्यवसाय से जोड़ने में मील का पत्थर साबित हो रही है। बड़ी संख्या में युवा योगी सरकार की इस अभियान का लाभ लेकर न सिर्फ खुद का व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पर प्रदान कर रहे हैं। गोरखपुर में संचालित 'गरिमा गृह' इस दिशा में एक मिसाल बनकर उभरा है। यहां रह रहे ट्रांसजेंडर्स को शिक्षा, प्रशिक्षण और रोज़गार दिलाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। समाज कल्याण विभाग के नेतृत्व में यह केंद्र न केवल एक सुरक्षित आश्रय स्थल है, बल्कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी बन रहा है। यहां अब तक आठ ट्रांसजेंडर्स को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराया गया है। 'गरिमा गृह' को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। यहां सीसीटीवी निगरानी, बायोमैट्रिक और फ़ेस अटेंडेंस जैसे आधुनिक प्रावधान किए जाएंगे ताकि संचालन पारदर्शी और सुरक्षित बना रहे। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा के अंतर्गत बैंक ऋण की सुविधा देकर ट्रांसजेंडर्स को स्टार्टअप और स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बीते दिनों राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश भर में किन्नरों के लिए 100 कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएं।

इन केंद्रों के माध्यम से इस समुदाय को शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ा जाए। इन केन्द्र के माध्यम से उत्तर प्रदेस ट्रांसजेंडर कल्याण के मॉडल के रूप में उभरेगा। योगी सरकार इन केंद्रों के माध्यम से ट्रांसजेंडर्स को शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, कुकिंग, सिलाई, कंप्यूटर, सौंदर्यकला आदि जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर स्वरोजगार से जोड़ने पर विचार कर रही है।

नीतिगत सुधारों ने यूपी को बनाया निवेशकों की पहली पसंद: चौधरी

कैनविज टाइम्स संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सम्मेलन के दौरान इन्वेस्ट यूपी के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शशांक चौधरी ने कहा कि नीतिगत सुधारों और इन्वेस्ट यूपी की सक्रिय पहल ने यूपी को निवेशकों को पहली पसंद बनाया है।

श्री चौधरी ने गुरुवार को यहां उद्योग, नीति निर्माण, उद्यमिता और एमएसएमई क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को संबोधित करते हुए बताया कि कैसे नीति सुधारों, लक्षित प्रोत्साहनों और सशक्त शासन के मेल से राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है।

उन्होने कहा उत्तर प्रदेश में बीते कुछ वर्षों में व्यापक बदलाव देखने को मिले हैं। राज्य ने 33 से अधिक क्षेत्र-विशिष्ट औद्योगिक नीतियां लागू की हैं, जो निवेशकों को आकर्षक प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करती हैं। स्पष्ट नीतिगत दृष्टिकोण, मजबूत नियामक ढांचा और समर्पित औद्योगिक बुनियादी ढांचे के साथ, यूपी आज निवेश के लिए पसंदीदा राज्य बन चुका है।ङ्क

श्री चौधरी ने कहा कि यह राज्य भारत में एमएसएमई का बड़ा आधार है, जो प्रदेश की सशक्त उद्यमिता और नवाचार संस्कृति का प्रमाण है। उन्होंने कहा ल्ल कुशल कार्यबल और विशाल उपभोक्ता आधार के कारण यूपी पारंपरिक उद्योगों के साथ-साथ स्टार्टअप्स के लिए भी आदर्श स्थल है। राज्य की जनसांख्यिकीय शक्ति पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की करीब 56 फीसदी आबादी 18 से 60 वर्ष की उत्पादक आयु वर्ग में है, जो लंबे समय तक आर्थिक विकास का आधार बनेगी। राज्य के प्रतिष्ठित शैक्षणिक और तकनीकी संस्थानों की बदौलत लगातार कुशल मानव संसाधन तैयार हो रहे हैं।

तालाब की भूमि पर हटवाया गया अतिक्रमण

कोरांव प्रयागराज, कैनविज टाइम्स संवाददाता। जिलाधिकारी के आदेश व पर्वक्षेण अधिकारी उपजिलाधिकारी कोरांव आकांक्षा सिंह के निर्देशन मे तहसीलदार कोरांव ने ग्राम खपटिहा में गाटा संख्या 28 तालाब की भूमि पर से अवैध निर्माण गिरवा दिया। कानूनगो और लेखपाल की उपस्थिति में यह कार्रवाई की गई। इससे पहले लेखपाल ने अवैध कब्जे की जानकारी दी थी और कई बार कब्जा छोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन कब्जा नहीं छोड़ा गया था। बता दे की कोरांव तहसील क्षेत्र के अधिकांश तालाबों चकमार्ग, नाली बंजर ऊसर समेत सरकारी जमीनो पर कब्जा अतिचारी किये हुए है लेकिन राजश्व कर्मी के कमी के कारण जिस अनुपात मे कार्रवाही होनी चाहिए उस अनुरूप नही हो पा रहा इसका मुख्य वजह है की जितने लेखपाल कानूनगो है उनके ऊपर कई कई राजश्व गांव की जिम्मेदारी है उसी को निपटाना मुश्किल हो रहा यदि राजश्व कर्मी कानूनगो की और तैनाती कोरांव तहसील मे उच्चाधिकारियो द्वारा कर दिया जाय तो जनता को काफी सहुलियत मिल सकता है शिकायत मे काफी कमी आ सकती है।

तहसीलदार कोरांव को सौंपा गया ज्ञापन

कोरांव (प्रयागराज), कैनविज टाइम्स संवाददाता। अखिल भारतीय यादव महासभा कोरांव ने तहसीलदार कोरांव को इटावा मामले में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में इटावा जिले के दादरपुर ग्राम में भागवत कथा वाचक और उनकी टीम के साथ ग्रामीणों द्वारा किए गए हमले के विरोध में कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में कथा वाचकों के ऊपर की गई प्राथमिकी रद्द करने, दोषियों को कड़ी सजा देने और समाज में भाईचारा कायम करने की मांग की गई है। इस अवसर पर अखिल भारतीय यादव महासभा के कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश में जनता के लिए जारी सरकारी नंबरों में लापरवाही, सीएम से संज्ञान लेने की मांग

प्रयागराज, कैनविज टाइम्स संवाददाता। उत्तर प्रदेश में आम जनता की सुविधा के लिए जनपदवार जारी किए गए सरकारी संपर्क नंबर अब जनता के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। प्रदेशभर से लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं कि अधिकतर हेल्पलाइन नंबर या तो उठाए नहीं जाते या फिर हमेशा बंद मिलते हैं। इससे आम जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जनपद स्तर पर अधिकारियों के सरकारी मोबाइल नंबर और हेल्पलाइन नंबर शासन की मंशा के अनुरूप जनता की तत्काल सहायता के लिए जारी किए गए थे, लेकिन धरातल पर स्थिति इसके ठीक उलट है। कई जिलों में न तो फोन रिसीव किए जा रहे हैं और न ही सही समय पर कोई प्रतिक्रिया मिल रही है। इस लापरवाही के चलते जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब प्रदेश के जागरूक नागरिकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि वह स्वयं इस मामले में संज्ञान लें और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जनता की मांग है कि हेल्पलाइन नंबरों की नियमित निगरानी की जाए और ऐसे सिस्टम तैयार किए जाएं जिससे हर कॉल का रिकॉर्ड रहे और जवाबदेही सुनिश्चित हो। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस गंभीर मुद्दे पर जल्द ठोस कदम उठाएंगे।

50 हजार का इनामी बदमाश प्रदीप राय गिरफ्तार

प्रयागराज, कैनविज टाइम्स संवाददाता। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। चार वर्षों से फरार चल रहा 50 हजार का इनामी बदमाश प्रदीप राय आखिरकार गिरफ्त में आ गया। वाराणसी और प्रयागराज यूनिट की संयुक्त कार्रवाई में प्रदीप राय को प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। प्रदीप राय पर गंभीर आपराधिक मामले, खासकर हत्या का मुकदमा दर्ज था। पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी, लेकिन वह हर बार चकमा देकर फरार हो जाता था। उसकी गिरफ्तारी पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। टीम ने खुफिया जानकारी के आधार पर जाल बिछाकर उसे दबोचा। फिलहाल उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रदीप राय की गिरफ्तारी को एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है, जो प्रयागराज सहित पूरे क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

अतीक के रिश्तेदार और करीबियों पर अवैध निर्माण का आरोप, दो एफआईआर दर्ज

प्रयागराज, कैनविज टाइम्स संवाददाता। अतीक अहमद से जुड़े लोगों द्वारा प्रयागराज में अवैध निर्माण कराए जाने का मामला सामने आया है। करैली थाना क्षेत्र में अतीक अहमद के रिश्तेदारों और करीबियों पर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर निर्माण कराने का आरोप है। पुलिस ने इस संबंध में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। मामला करैली थाना क्षेत्र के एनुद्दीनपुर का है, जहां पहले से गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई जमीन पर अतीक के करीबियों ने फिर से कब्जा कर अवैध निर्माण कर लिया। करैली थाना प्रभारी की ओर से 12 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं, दूसरी एफआईआर हल्का लेखपाल की शिकायत पर दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार की सीलिंग की जमीन पर भी कब्जा कर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध कब्जा हटवाने की कार्रवाई भी जल्द की जाएगी।

सोशल मीडिया की शिकायतों पर डीएम रविन्द्र कुमार माँदड़ की विशेष जनसुनवाई आज

प्रयागराज, कैनविज टाइम्स संवाददाता। जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ ने एक विशेष जनसुनवाई आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह जनसुनवाई 27 जून 2025 को सुबह 10 बजे से जिला कार्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर डीएम स्वयं नागरिकों की शिकायतें सुनेंगे और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश देंगे। यह पहल उन सोशल मीडिया शिकायतों को लेकर की गई है, जिनमें नागरिकों ने ट्विटर (एक्स), फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी समस्याएं साझा करते हुए कहा था, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, हमारा कार्य लंबित है, समस्या का समाधान नहीं हुआ आदि। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस विशेष जनसुनवाई में वे नागरिक शामिल हो सकते हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर शिकायत की हो और समस्या अब तक हल नहीं हुई हो। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपनी समस्या का लिखित विवरण, सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट/कमेंट का स्क्रीनशॉट (तारीख व समय सहित), और कार्य के लंबित रहने की अवधि के विवरण के साथ उपस्थित हों। डीएम ने भरोसा दिलाया कि हर वैध और जरूरी शिकायत पर त्वरित, निष्पक्ष व प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, जिससे शासन-प्रशासन में जनता का विश्वास और मजबूत हो सके।

चरिहारी पहाड़ पर खनन माफियाओं का कब्जा, पत्रकारों को दी जा रही जान से मारने की धमकी

प्रयागराज, कैनविज टाइम्स संवाददाता। चरिहारी पहाड़, जो बारा और शंकरगढ़ थाना क्षेत्रों के बीच स्थित है, इन दिनों खनन माफियाओं का अड्डा बन गया है। यमुनानगर क्षेत्र के इस पहाड़ी इलाके में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है और प्रशासनिक नियंत्रण लगभग नदारद है। कानून व्यवस्था की बदहाली का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब पत्रकारों को वहां रिपोर्टिंग करना भी जान पर बन आया है। सूत्रों के अनुसार, हाल ही में जब कुछ पत्रकार अवैध खनन की सच्चाई उजागर करने चरिहारी पहाड़ पहुंचे, तो माफियाओं ने न सिर्फ उनके साथ बदसलूकी की, बल्कि मोबाइल फोन छीनकर वीडियो और खबर भी डिलीट कर दी। पत्रकारों को खुलेआम धमकी दी गई कि ल्लअगर दोबारा पहाड़ पर दिखे तो झूठे मुकदमे में फंसा देंगे या जान से मार देंगे। खनन माफिया का यह दावा कि वे हर महीने ''रामचंदी पहुंचा देते हैं'', यह संकेत देता है कि स्थानीय प्रशासन या कुछ तत्वों की मिलीभगत संभव है। अब तक किसी ठोस कार्रवाई का न होना, प्रशासन की कार्यशैली और निष्क्रियता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यह घटना न केवल प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है, बल्कि कानून व्यवस्था की पोल खोलने वाला भी है।

कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल की डॉक्टर पर एफआईआर

प्रयागराज, कैनविज टाइम्स संवाददाता। कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल की एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉ. शुभ्रा घोष के खिलाफ लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। मरीज को एनेस्थीसिया देने के दौरान नर्व इंजरी होने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह मुकदमा कर्नल नंद लाल यादव द्वारा दर्ज कराया गया है, जो पीड़िता के परिजन हैं। घटना सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी। जांच में डॉक्टर शुभ्रा घोष को प्रथमदृष्टया दोषी पाया गया। रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि पीड़िता के पति प्रयागराज में अपर नगर मजिस्ट्रेट (इएख्र) के पद पर कार्यरत हैं, जिससे मामला और भी संवेदनशील बन गया है। मेडिकल लापरवाही के इस गंभीर मामले ने अस्पताल की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और मेडिकल काउंसिल से भी रिपोर्ट मांगी गई है। मामले ने शहर में चिकित्सकीय जिम्मेदारी और जवाबदेही को लेकर बहस छेड़ दी है।

मायावती ने केजीएमयू का नाम बदलकर छत्रपति शाहूजी महाराज रखने की मांग की

कैनविज टाइम्स संवाददाता

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 'राजर्षि' छत्रपति शाहूजी महाराज की जंयती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ उन्होंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) का नाम बदल कर छत्रपति शाहूजी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार द्वारा इसका नाम जबरदस्ती बदलकर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कर दिया गया था।

मायावती ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कोल्हापुर, महाराष्ट्र रियासत में दलितों को नौकरी में आरक्षण देने का क्रान्तिकारी कदम उठाकर भारत में आरक्षण के जनक के रूप में अमर हो जाने वाले राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज को आज उनकी जयंती पर शत्-शत नमन व अपार श्रद्धा-सुमन अर्पित तथा उनके समस्त अनुयाइयों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उन्होंने आगे लिखा कि ऐसे समय में जबकि जाति के आधार पर सदियों से तोड़े व पछाड़े गए देश के खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण के उनके संवैधानिक अधिकार को निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाकर उनकी अपनी बीएसपी की सरकार व बहुजनों के शासक वर्ग बनने के अभाव में उन्हें फिर से लाचार, मजबूर व गुलाम बनाने का षडयंत्र जारी है। राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज के मानवीय गुणों, न्याययुक्त सरकार व अन्यायमुक्त समाज की स्थापना में उनकी ऐतिहासिक भूमिका व उनकी स्मृतियों को सजोने व स्मरण करने का महत्व व्यापक जन व देशहित में और भी अधिक बढ़ जाता है।

बीएसपी प्रमुख ने आगे लिखा कि विशेषकर दलित व पिछड़े वर्गों में समय-समय पर जन्मे ऐसे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज के आदर-सम्मान में तथा उनकी प्रेरणादायी स्मृति को स्थाई बनाने के लिए यूपी में बीएसपी की अब तक चार बार रही मेरी सरकारों में ऐतिहासिक महत्व के अनेकों कार्य किए गए हैं। इसमें से प्रमुख हैं उनके नाम पर नया जिला, शिक्षण संस्थाओं आदि का नामकरण व भव्य स्थलों/स्मारकों आदि में उनकी प्रतिमा की स्थापना। किन्तु विशेष उल्लेखनीय है राजधानी लखनऊ में यूपी की पहली छत्रपति शाहूजी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करके उसे तुरन्त चालू करना, जिसको दलित व पिछड़े वर्ग के बहुजनों व उनके आरक्षण के हमेशा विरोधी रही समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार द्वारा उसका नाम जबरदस्ती बदलकर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। हालांकि उसी नाम से लखनऊ में मेडिकल कॉलेज काफी पहले से ही स्थापित है।

डंपर ने कुचला मां-बेटे को, मौके पर ही मौत

प्रयागराज । गुरुवार सुबह प्रयागराज के नैनी क्षेत्र स्थित लेप्रोसी चौराहे पर दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। एक तेज़ रफ्तार डंपर ने बाइक सवार मां-बेटे को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान रीवा (मध्य प्रदेश) निवासी कृष्ण बिहारी मिश्रा (55) और उनकी मां ऊषा मिश्रा (72) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक छत्तीसगढ़ में तैनात आईपीएस मयंक मिश्रा के चाचा और दादी थे। हादसे के समय दोनों बाइक से शहर की ओर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डंपर चालक लेप्रोसी चौराहे पर चल रही कथित अवैध वसूली से बचने के प्रयास में तेज़ गति से भाग रहा था, जिसके चलते उसने वाहन से नियंत्रण खो दिया और यह हादसा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। स्थानीय लोगों की मदद से डंपर को पकड़ लिया गया है। इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

महायोजना के नियमों की खुलेआम उड़ रही धज्जियां

गंगा किनारे तेजी से हो रहे अवैध निर्माण

कैनविज टाइम्स संवाददाता

दारागंज, फाफामऊ, तेलियरगंज, राजापुर, नैनी, झूंसी में बिना नक्शा पास कराए तेजी से बन रहे आवास

पीडीए की चुप्पी से जनता में नाराजगी, अवैध निर्माण रोकने की उठी सख्त कार्रवाई की मांग

प्रयागराज। शहर में प्रयागराज महायोजना के नियमों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। गंगा नदी के किनारे दारागंज, फाफामऊ, तेलियरगंज, राजापुर, नया और पूर्व क्षेत्र जैसे इलाकों में तेजी से अवैध आवासीय निर्माण किए जा रहे हैं। न तो इन निर्माणों के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण (घ्क्ष्) से नक्शा पास कराया जा रहा है, न ही किसी भी प्रकार के मानक का पालन हो रहा है। महायोजना के अनुसार गंगा नदी से 500 मीटर की परिधि में निर्माण कार्य प्रतिबंधित है, लेकिन भू-माफियाओं और स्थानीय प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत से यह काम खुलेआम जारी है।

शहर के कई इलाकों में अवैध कॉलोनियों की प्लाटिंग धड़ल्ले से की जा रही है। बिना किसी स्वीकृत लेआउट के नागरिकों को भूखंड बेचे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी में हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी साधे बैठे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अवैध निर्माण करने वालों से आर्थिक लाभ लेकर कार्रवाई टाल दी जाती है। नैनी और झूंसी जैसे इलाकों में भी बिना नक्शा पास कराए आवासीय निर्माण जोरों पर हैं। महायोजना का मुख्य उद्देश्य शहर के सुनियोजित विकास, ट्रैफिक नियंत्रण, पर्यावरण संतुलन और बुनियादी सुविधाओं का बेहतर वितरण था, लेकिन वर्तमान हालात इसके ठीक विपरीत हैं। अवैध निर्माणों से न केवल शहर की खूबसूरती खराब हो रही है, बल्कि भविष्य में यातायात, जल निकासी और जनसंख्या दबाव से गंभीर समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। गंगा नदी के किनारे हो रहे निर्माण पर्यावरण और नदी की स्वच्छता के लिए भी बड़ा खतरा बन रहे हैं। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों में घ्क्ष् की निष्क्रियता को लेकर भारी नाराजगी है। लोगों ने मांग की है कि गंगा किनारे और शहर के अन्य इलाकों में हो रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि अवैध निर्माणों को रोकने के लिए प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाए तो वे जनआंदोलन करेंगे और मामले को शासन स्तर तक पहुंचाएंगे।

रेजीडेंसी के पास चौड़ी होगी सड़क, बनेंगे फूड वेन्डिंग जोन

कैनविज टाइम्स संवाददाता

लखनऊ। एलडीए राजधानी की यातायात व्यवस्था सुधारने और सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। कैसरबाग स्थित ऐतिहासिक रेजीडेंसी के पास की सड़क को अब डेढ़ मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। साथ ही सड़क किनारे एक भव्य प्लाजा विकसित किया जाएगा, जिसमें फूड वेन्डिंग जोन और पार्किंग स्पेस की सुविधाएं होंगी। इस पूरे क्षेत्र को हेरिटेज लुक में सजाया जाएगा, जिससे हेरिटेज कॉरिडोर की खूबसूरती और आकर्षण और भी बढ़ेगा। यह निर्णय एलडीए की अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। इस बैठक में विकास और सौंदर्यीकरण से जुड़े प्रस्तावों का विस्तृत प्रजेंटेशन दिया गया, जिसे स्वीकृति मिल गई। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने जानकारी दी कि रेजीडेंसी से डालीगंज तिराहे की ओर जाने वाली सड़क के किनारे लगभग 300 मीटर की जगह फिलहाल खाली है, जहां वर्तमान में कुछ लोग अवैध रूप से ठेले लगाते हैं। इस स्थान पर सड़क को चौड़ा किया जाएगा और नियोजित ढंग से वेंडिंग जोन और पार्किंग प्लाजा विकसित किया जाएगा, जिससे न केवल यातायात सुगम होगा बल्कि क्षेत्र की व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।

बैठक में यह भी तय किया गया कि शहर के प्रमुख स्थलों जैसे डालीगंज तिराहा, ग्वारी चौराहा, जनेश्वर मिश्र पार्क, फ्रैगरेंस पार्क, कुकरैल रोटरी समेत सात स्थानों पर थीम आधारित स्कल्पचर्स लगाए जाएंगे। डालीगंज तिराहे के पास स्थित नक्षत्रशाला को ध्यान में रखते हुए वहां ''साइंस एंड स्पेस'' थीम पर आधारित शिल्प लगेगा, जबकि कुकरैल रोटरी पर ल्लरिवर लाइफङ्क विषय पर आधारित स्कल्पचर लगाया जाएगा। इसी तरह विभिन्न पार्कों में बच्चों को ध्यान में रखते हुए आकर्षक थीम पर आधारित शिल्प लगाए जाएंगे। इन कार्यों के लिए प्रसिद्धी इंजीनियर्स, कलरोथॉन, कराबी और आकृति ज्वैलक्राफ्ट जैसी दक्ष संस्थाओं को सूचीबद्ध किया गया है। सौंदर्यीकरण के अंतर्गत शहर के ग्रीन कॉरिडोर, हारमोनी पार्क, किसान बाजार, अर्जुनगंज और कमता फ्लाईओवर सहित विभिन्न स्थानों पर थीमेटिक वॉल पेंटिंग और फ्लोर आर्ट भी कराई जाएगी। इसके लिए दिशा फाउंडेशन, अद्वैता, श्रीराम इंटरप्राइजेज और एमएस ग्रुप जैसी संस्थाओं का चयन किया गया है। वर्तमान में जनेश्वर मिश्र पार्क, रिवर फ्रंट, मधुरिमा फ्लाईओवर, ग्वारी फ्लाईओवर और लोहिया पार्क के गेट नंबर-3 पर वॉल पेंटिंग का कार्य चल रहा है। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि जोन वार सर्वे कराकर शहर के अन्य उपयुक्त स्थानों को भी इस कार्य के लिए चयनित किया जाए, ताकि लखनऊ का हर कोना खूबसूरत और जीवंत नजर आए। समीक्षा बैठक के दौरान हजरतगंज में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों की भी समीक्षा की गई। डॉ. रोशन जैकब ने निर्देश दिए कि हजरतगंज क्षेत्र में सड़कों के बीच डिवाइडर पर लाइटें न लगाई जाएं, बल्कि सड़कों के किनारे पोल्स और बोलार्ड्स पर लाइटिंग की जाए, ताकि दृश्य सौंदर्य भी बढ़े और यातायात में कोई बाधा न हो। बैठक में मुख्य नगर नियोजक के.के. गौतम, प्रभारी मुख्य अभियंता नवनीत शर्मा समेत एलडीए के वरिष्ठ अधिकारी, अभियंता, आर्किटेक्ट्स और संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

नगर निगम में राजस्व निरीक्षकों की नई तैनाती

लखनऊ, कैनविज टाइम्स संवाददाता। नगर निगम लखनऊ ने प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए राजस्व निरीक्षकों और कर निरीक्षक (श्रेणी-2) की नई तैनाती की है। यह तैनातियाँ नगर आयुक्त के निर्देश पर की गईं हैं। आदेश के मुताबिक, सुबोध कुमार वर्मा को मुख्यालय से हटाकर जोन-1 में राजस्व निरीक्षक बनाया गया है। कुलदीप सिंह चौधरी को जोन-5 में, और शिप्रा सिंह को जोन-2 में तैनात किया गया है। ये दोनों भी पहले मुख्यालय से सम्बद्ध थे। इसके अलावा दो नए राजस्व निरीक्षक अंकिता सक्सेना और आकर्ष श्रीवास्तव को जोन-4 में नियुक्त किया गया है। साथ ही हरी शंकर पाण्डेय, जो पहले मुख्यालय में कर निरीक्षक (श्रेणी-2) के रूप में कार्यरत थे, अब जोन-7 में भेजे गए हैं। नगर निगम को उम्मीद है कि इन बदलावों से कामकाज में सुधार आएगा और लोगों को बेहतर सेवा मिल सकेगी।

अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कई इलाकों में चला अभियान

लखनऊ, कैनविज टाइम्स संवाददाता। नगर निगम लखनऊ ने गुरुवार को महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर शहर के कई जोनों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। यह कार्रवाई जोनल अधिकारियों, प्रवर्तन दल (296) ईटीएफ़ और पुलिस की मौजूदगी में हुई। जोन-1 में जोनल अधिकारी ओम प्रकाश सिंह के नेतृत्व में बासमंडी से हुसैनगंज तक अवैध ठेले, गुमटी व ढांचे हटाए गए। जोन-5 में गिन्दनखेड़ा (सरोजनी नगर) में नन्दकिशोर के निर्देशन में अतिक्रमणकारियों को भविष्य में अतिक्रमण न करने की चेतावनी देते हुए कई काउंटर, गुमटी, ठेले, गैस सिलेंडर लोहे की टंकी आदि जब्त की गई। वहीं जोन-6 में नक्खास चौराहे से भवानीगंज तक अभियान चलाते हुए कई ठेले, बैनर, 15 अस्थायी दुकानें, छाते, होल्डिंग व अन्य सामान हटाया गया और थाने को पुनः अतिक्रमण रोकने का पत्र भी भेजा गया है। इसके अलावा जोन-8 में वृंदावन कॉलोनी की ग्रीन बेल्ट से दो जेसीबी और चार डंपर की मदद से 10 हाइवा कबाड़ व दर्जनों झोपड़ियां हटाई गईं। टैक्स सुपरिंटेंडेंट देवी शंकर दुबे समेत अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। महापौर ने कहा कि शहर को स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

महिला को बोलेरो ने मारी टक्कर, मौके पर मौत

मोहनलालगंज, कैनविज टाइम्स संवाददाता। गुरुवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के विन्दौआ गांव की रहने वाली एक महिला की जान चली गई। घटना सुबह की है, जब शिव देवी पत्नी छत्रपाल अपने घर से टहलने के लिए निकली थीं और वापसी के दौरान रायबरेली की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे बोलेरो वाहन क्tन29इग9124 ने उन्हें सामने से जोरदार टक्कर मार दी।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बोलेरो चालक अत्यंत तेज और लापरवाही से वाहन चला रहा था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शिव देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल उन्हें ट्रॉमा सेंटर लखनऊ पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।घटना के बाद मृतका के परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है। बोलेरो और चालक की तलाश में जुट गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।स्थानीय लोगों ने हादसे को लेकर रोष जताया और प्रशासन से मांग की कि क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण हेतु कड़े कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके।

मामूली कहासुनी ने लिया खूनी झड़प का रूप, चार हिरासत में

कैनविज टाइम्स संवाददाता

ठाकुरगंज लखनऊ। बुधवार देर रात ग्रीनवे पब्लिक स्कूल तकिया मैदान के पास मामूली कहासुनी अचानक हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। लाठी-डंडों से लैस चार नशे में धुत युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, सीता विहार कॉलोनी निवासी संदीप यादव अपने मित्र सौरभ के साथ किसी काम से जा रहा था। इसी दौरान बसंत विहार के निवासी पंकज और हिमांशु से रास्ते में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सभी युवक शराब के नशे में थे और मामूली टिप्पणी ने तूल पकड़ लिया। बात इतनी बढ़ी कि चारों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले। घटना की सूचना मिलते ही ठाकुरगंज भूहर चौकी प्रभारी मुदित राय और उप निरीक्षक अखिलेश कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में किया। पुलिस ने दोनों पक्षों से दो-दो युवकों को हिरासत में लेकर कोतवाली भेज दिया। चौकी प्रभारी मुदित राय ने बताया कि मामला गंभीरता से लिया जा रहा है। सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और निष्पक्ष जांच के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, तीन घायल

❑ दोनों पक्षों की तहरीर पर मारपीट और एससी/एसटी एक्ट में कार्रवाई, पुलिस जांच में जुटी

कैनविज टाइम्स संवाददाता

निगोहां, लखनऊ। निगोहां थाना क्षेत्र के दखिना शेखपुर गांव में बुधवार रात पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में कहासुनी के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। दोनों ओर से लाठी-डंडे और लोहे की रॉडें चलीं, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा है।

घटना के संबंध में गांव निवासी दीपू ने बताया कि वह बुधवार देर रात खाना खाकर अपने घर में सो रहा था। रात लगभग 11:30 बजे गांव के विकास तिवारी उनके भाई आकाश तिवारी और साथी मनोज सिंह शराब के नशे में धुत होकर उसके घर में घुस आए। दीपू का आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते तीनों ने उसे गालियां देनी शुरू कर दी और लाठी-डंडों से पिटाई कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।दीपू ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को देख आरोपी धमकाते हुए मौके से भाग निकले। वहीं दूसरी ओर विकास तिवारी के पक्ष से मनोज कुमार ने आरोप लगाया कि वह अपने घर में खाना खा रहा था, तभी दीपू, देवानंद, रजनीश और गौरी शराब के नशे में उसके दरवाजे पर आए और बिना किसी वजह के गालियां देने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने दरवाजे को तोड़ दिया और घर के अंदर घुसकर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से मारपीट शुरू कर दी। मनोज ने यह भी बताया कि जब उसकी पत्नी बचाव में आई तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की।इस विवाद में एक पक्ष से दीपू, जबकि दूसरे पक्ष से मनोज और आकाश घायल हुए हैं। तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए निगोहां सीएचसी भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर निगोहां थाना प्रभारी अनुज कुमार तिवारी ने बताया कि दीपू की तहरीर पर एससी/एसटी एक्ट व मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि मनोज कुमार की तहरीर पर मारपीट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के आरोपों के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

उत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/टीआरडी/हजरतगंज, मंडल रेल प्रबंधक, कार्यालय लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निम्नलिखित कार्यों के लिए मुहरबंद खुली ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

ई-निविदा सूचना संख्या	टीआरडी-08-सीनि.डी.ई.ई. लखनऊ-25-2कॉल		
कार्य का नाम	105 वर्ग मिमी कॉपर जम्पर को 160 वर्ग मिमी कॉपर जम्पर में परिवर्तित करके ओएचई का वृद्धि, लखनऊ/एनआर डिवीजन में एंटी मंकी क्लाइम्बिंग डिवाइस का प्रावधान।		
अनुमानित लागत	₹ 2,12,56,021.88/-	धरोहर राशि	₹ 2,56,300.00/-
कार्य पूर्ण करने की अवधि	06 माह		
निविदा फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि व समय तथा खोलने की तिथि	दिनांक 21.07.2025 को 15:00 बजे तक तथा खुलने का समय उसी दिन 15:00 बजे के बाद		
प्रस्ताव के वैधता	निविदा खुलने की तिथि से 60 दिन		
उत्तर रेलवे की वैबसाइट	अतिरिक्त सूचना उत्तर रेलवे की वैबसाईट **www.ireps.gov.in** पर चेक की जा सकती है।		
पात्रता मापदंड	निविदाकर्ता तब तक निविदा डालने योग्य नहीं है, जब तक कि वह निम्नलिखित पात्रता मापदंड पूरा नहीं करता: **1.** निविदाकर्ता का न्यूनतम औसत वार्षिक संविदात्मक कारोबार **वी/एन** या **'वी'** जो भी कम हो होना चाहिए **जहां वी** = निविदा का विज्ञापित मूल्य करोड़ रुपये में **एन** = कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित वर्षों की संख्या जिसके लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं **2.** निविदाकर्ता पिछले सात वित्तीय वर्ष (निविदा के आमंत्रित करने के लिए एक महिने पहले के अन्तिम दिन तक): "कम से कम एक समान प्रत्येक तीन वर्ष का **30** प्रतिशत न्यूनतम विज्ञापित राशि का कार्य किया हो" या "कम से कम एक समान प्रत्येक दो कार्य का **40** प्रतिशत न्यूनतम विज्ञापित राशि का कार्य किया हो" या "कम से कम एक समान एक कार्य का **60** प्रतिशत न्यूनतम विज्ञापित राशि का कार्य किया हो"। एक समान कार्य की परिभाषा होगी: Similar work means design, supply, erection, testing & commissioning of 50 Hz, Single Phase 25 KV AC OHE **3.** निविदाकर्ता अपने आफर के साथ बिजली के ठेकेदारों के वैध लाइसेंस की प्रमाणित छायाप्रति अवश्य जमा करें।		

नोटः इस निविदा के लिए किसी भी तरह के मैनुअल प्रस्तावों की अनुमति नहीं है और किसी भी तरह के प्राप्त मैनुअल प्रस्ताव नजरअंदाज/खारिज कर दिया जाएगा। पूर्ण विवरण वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर देखा जा सकता है।

सं. टीआरडी-08-सीनि.डी.ई.ई.-लखनऊ-25-2कॉल **दिनांक: 26.06.2025**

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ **1928/2025**

मोहर्रम व कांवड़ यात्रा को लेकर नगराम पुलिस अलर्ट

कैनविज टाइम्स संवाददाता

डीजे संचालकों के साथ की बैठक, दी हिदायत

नगराम , लखनऊ। आगामी त्यौहारों मोहर्रम व श्रवण मास में होने वाले कावड़ यात्रा के शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित संचालन के उद्देश्य से नगराम पुलिस ने गुरुवार को थाना परिसर में डीजे संचालकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की , जूलूस व यात्रा के दौरान आपत्तिजनक तथा भड़काऊ गाने नहीं बजाने की हिदायत दी गई।

बैठक नगराम थाना प्रभारी विवेक चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में लगभग तीन दर्जन से अधिक डीजे संचालकों ने भाग लिया। प्रभारी ने डीजे संचालकों को शख्त दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि वह 12 फुट से अधिक ऊंचे तथा दो साउंड से अधिक साउंड का प्रयोग न करें। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए की यात्रा के दौरान आपत्तिजनक भड़काऊ या अश्लील गीतों के बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन अनिवार्य होगा। बैठक में पुलिस की ओर से सभी डीजे संचालकों को धारा 168 के तहत औपचारिक नोटिस तामील कराई गई। प्रभारी ने बताया कि कावड़ यात्रा आस्था अनुशासन और सामाजिक समरसता का प्रतीक है जिसे सभी पक्षों के सहयोग से शांति एवं सुव्यवस्था के साथ संपन्न कराया जाएगा श्रावण मास आगामी 11 जुलाई को शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगा।

पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष भिड़े, कई घायल

कैनविज टाइम्स संवाददाता

दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया

नगराम, लखनऊ। नगराम थाना क्षेत्र के करोरा गांव में बीती बुधवार की रात पुरानी रंजिश और शराब के नशे में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मामले में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए नगराम थाने में तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।

नगराम थाना क्षेत्र के करोरा गांव के रहने वाले गुड्डू ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बीते बुधवार की रात करीब 11 बजे रंजीत , विनोद, मनोज व केवल पत्नी रंजीत ने शराब के नशे में गाली-गलौज करते हुए घर पर हमला कर दिया। आरोप है कि उक्त लोगों ने गुड्डू उनकी पत्नी कमलेश और बेटे विशाल को लाठी-डंडों से पीटा, जिससे सभी को गंभीर चोटें आईं। पीड़ित पक्ष ने जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। दूसरी ओर रंजीत निवासी ने भी मारपीट की तहरीर नगराम पुलिस को दिया है। उनके अनुसार, गुड्डू , जगजीवन , गुड्डू की पत्नी व अन्य लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर घर पर आकर गाली-गलौज की। जब उन्होंने विरोध किया तो उक्त लोगों ने लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। मारपीट में रंजीत समेत उनके भाई विजय को भी गंभीर चोटें आईं। उन्होंने भी जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया। इस आधार पर पुलिस ने दूसरे पक्ष की तरफ से सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। नगराम थाना प्रभारी विवेक चौधरी का कहना है कि दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। घायलों का मेडिकल परीक्षण करवाया गया है।

उत्तर रेलवे

ई-ऑक्शन सूचना

वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, लखनऊ के द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ई-ऑक्शन से सम्बन्धित सूचना।

एडमिन यूनिट/जोन	लखनऊ-उ0रे0-मण्डल-वाणिज्य/उ0रे0
नीलामी सूची सं0/लॉट सं0	PnU-LKO-BSB-WRL-88-25-1 (Pay and Use Lounges/ Waiting/ Retiring/Cloak Rooms)
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	13.06.2025
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	28.06.2025 समय 10:00 बजे
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	28.06.2025 समय 10:30 बजे
नीलामी सूची सं0/लॉट सं0	ADVT-LKO-PYGS-OSN-530-24-1 (Advertising -On Station Premise (Non Digital)
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	13.06.2025
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	30.06.2025 समय 12:00 बजे
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	30.06.2025 समय 12:30 बजे
नीलामी सूची सं0/लॉट सं0	ADVT-LKO-LKO-OSN-556-25-1 (Advertising -On Station Premise (Non-Digital)
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	13.06.2025
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	01.07.2025 समय 10:00 बजे
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	01.07.2025 समय 10:30 बजे
नीलामी सूची सं0/लॉट सं0	ADVT-LKO-RBL-OH-559-25-1 (Advertising -Out of Home)
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	24.06.2025
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	11.07.2025 समय 12:00 बजे
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	11.07.2025 समय 12:30 बजे
नीलामी सूची सं0/लॉट सं0	ADVT-LKO-LKO-OH-557-25-1 (Advertising -Out of Home)
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	17.06.2025
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	03.07.2025 समय 10:00 बजे
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	03.07.2025 समय 10:30 बजे
नीलामी सूची सं0/लॉट सं0	ADVT-LKO-LKO-OH-558-25-1 (Advertising -Out of Home)
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	20.06.2025
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	05.07.2025 समय 10:00 बजे
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	05.07.2025 समय 10:30 बजे
नीलामी का प्रकार	Close Ended
वेबसाइट विवरण जहाँ पंजीकृत बोलीदाताओं द्वारा नीलामी का पूरा विवरण देखी जा सकती है।	E-Auction Module of www.ireps.gov.in

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ **1921/25**

आपातकाल की काली यादें आज भी जिंदा : अनीस मंसूरी

कैनविज टाइम्स संवाददाता

लखनऊ। पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने कहा है कि 25-26 जून 1975 की रात को देश के लोकतांत्रिक इतिहास में काला अध्याय कहा जाना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इमरजेंसी के दौरान जिस तरह संविधान को कुचला गया, आमजन के अधिकारों को छीन लिया गया और विपक्ष को जेलों में ठूंसा गया, वह आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जिस प्रकार जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव, राजनारायण जैसे नेताओं ने लोकतंत्र के लिए बलिदान दिया, उसे भुलाया नहीं जा सकता। विशेष रूप से श्री अखिलेश यादव द्वारा लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान देने का काम, और जेपीएनआईसी जैसे केंद्र की स्थापना, युवाओं को सही इतिहास से जोड़ने का महत्त्वपूर्ण प्रयास है। अनीस मंसूरी ने कहा कि आज जो माहौल बन रहा है, वह इमरजेंसी से कम नहीं है। संविधान की आत्मा को कुचलने, संस्थाओं को पंगु बनाने, अल्पसंख्यकों को डराने, और पसमांदा समाज को हाशिए पर रखने की साजिशें खुलकर सामने हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार लोकतंत्र की जगह तानाशाही और 'बुलडोजर नीति' को बढ़ावा दे रही है। अनीस मंसूरी ने यह भी कहा कि पसमांदा समाज को समाजवादी आंदोलन की विरासत पर गर्व है और अब फिर से लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम सबको एकजुट होकर खड़ा होना होगा। उन्होंने संविधान की रक्षा और जन-अधिकारों की बहाली के लिए एक सतत जन-जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। अंत में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश फिर एक बार लोकतंत्र की लड़ाई में अगुवाई करने जा रहा है, और समाजवादी पार्टी तथा अखिलेश यादव की नेतृत्व क्षमता इस संघर्ष को नई दिशा दे रही है।

अशोक सिंह लखनऊ नगर निगम में ही करेंगे सेवा पूर्ण

कैनविज टाइम्स संवाददाता

लखनऊ। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह का स्थानांतरण लखनऊ नगर निगम से अलीगढ़ नगर निगम कर दिया गया था। उन्होंने इसे राज्य सरकार की तबादला नीति के विरुद्ध बताते हुए हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि उनकी सेवानिवृत्ति 30 सितंबर 2026 को होनी है, और तबादला नीति के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी दो वर्षों के भीतर सेवानिवृत्त होने वाला हो, तो उसे उसकी इच्छा अनुसार उसी स्थान पर कार्य करने की अनुमति मिलनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनका भाई 80% विकलांग है और वह उस पर निर्भर है। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अशोक सिंह को निर्देश दिया कि वे एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष नया प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। अदालत ने सरकार को तीन सप्ताह में इस पर नीति के अनुसार विचार कर कारण सहित आदेश पारित करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जब तक निर्णय नहीं होता या चार सप्ताह तक (जो पहले हो), तब तक स्थानांतरण आदेश प्रभाव में नहीं रहेगा। इससे अब यह स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल अशोक सिंह लखनऊ नगर निगम में ही पदस्थ रहेंगे। यह निर्णय अशोक सिंह के लिए न केवल न्याय की जीत है, बल्कि उनके अनुभव और सेवाओं का भी सम्मान है।

कर्मचारी संघ ने दी बधाई

कोर्ट से राहत मिलने पर नगर निगम कर्मचारी संघ ने अशोक सिंह को बधाई दी है। संघ के पदाधिकारियों ने इसे न्याय की जीत बताते हुए अशोक सिंह की कार्यशैली की सराहना की। साथ ही प्रभारी अधिकारी से कर्मचारियों की लंबित मांगों जैसे पदोन्नति, समयबद्ध सेवानिवृत्ति लाभ और कर्मचारियों की सुरक्षा को शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया गया। अशोक सिंह ने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी। इसके अलावा अशोक सिंह को पुनः मुख्य कर निर्धारण अधिकारी बनाए जाने पर उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय इंजीनियर संगठन ने भी उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

APPOINTMENT

RDSJ LAW COLLEGE Requires Teaching Faculty for 3 Year Law Course.

Basic Qualification - NET qualified, Ph.D (LAW) Salary as per UGC norms.

Last date for applying - 20th July, 2025

Apply Online

Mob. 9919936091, 8601122777

Email Id :- rdsjlawcollege@gmail.com

सकरन में धंसी विकास की धरती, इंटरलॉकिंग और खड़ंजों की पोल खोलता सच

ग्राम पंचायतों में धड़ाधड़ बनवाए गए इंटरलॉकिंग रास्ते और खड़ंजे अब विकास के नहीं, धांधली के सबूत बनकर खड़े है

कैनविज टाइम्स संवाददाता

सकरन, सीतापुर । सकरन क्षेत्र अब सिर्फ मानकविहीन निर्माण, धंसी इंटरलॉकिंग और कागज़ी विकास का पर्याय बनकर रह गया है। करोड़ों की सरकारी योजनाएं ज़मीन पर गिर पड़ी हैं। कहीं तालाब में तो कहीं राहगीरों के पाँव के नीचे। ग्राम पंचायतों में धड़ाधड़ बनवाए गए इंटरलॉकिंग रास्ते और खड़ंजे अब विकास के नहीं, धांधली के सबूत बनकर खड़े हैं।

90 फीसदी पंचायतों में विकास नहीं, विनाश की गाथा

राज्य वित्त और मनरेगा के तहत बनवाए गए कार्यों में मानकों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। इन सड़कों का हाल ऐसा है कि चंद महीनों में ही या तो धंस गई हैं या टूटकर हादसों को न्योता दे रही हैं।

ओड़ा झार—जादुई प्रधान और खामोश जिम्मेदार

ग्राम पंचायत ओड़ा झार में इंटरलॉकिंग का निर्माण इतना घटिया हुआ कि वह चंद दिनों में ही बैठ गया। पंचायत सचिव सवालों के घेरे में आए, लेकिन ग्राम प्रधान की 'जादुई चुप्पी' ने सबको बेज़ुबान कर दिया।यहां तक कि जर्जर पंचायत भवन के ध्वस्तीकरण का मलबा तक हज़म कर लिया गया, लेकिन फाइल में एक भी रुपया दर्शाया नहीं गया। तालाब खुदाई में फर्जी मजदूर, फर्जी भुगतान—ओड़ा झार मानो फर्जीवाड़े का स्थायी ठिकाना बन चुका है।

देवतापुर—पीली ईंटों में दबी सच्चाई

ग्राम पंचायत देवतापुर में ठेकेदारी प्रथा के तहत पीली ईंटों से बन रहे खड़ंजे की खबरें कई बार प्रकाशित हो चुकी हैं। बावजूद इसके प्रशासन की आंखें नहीं खुलीं। फर्जी निर्माण उजागर होने के बाद भी दुरुस्तीकरण न होना भ्रष्टाचार की मिलीभगत को साबित करता है।

नसीरपुर—इंटरलॉकिंग के नाम पर छल

नसीरपुर पंचायत में जूनियर हाई स्कूल को जाने वाली इंटरलॉकिंग धंस गई, दीवारें चटक गईं। सीमेंट व मौरंग के बिना किए गए निर्माण में ईंटें खुद गवाही दे रही हैं। रोहित के घर से पंचायत भवन को जोड़ने वाले खड़ंजे में घटिया सामग्री के चलते सड़क जगह-जगह धंसी पड़ी है। एएनएम सेंटर के पास की इंटरलॉकिंग आधी तालाब में समा चुकी है।अन्य पंचायतों का भी कम बुरा हाल नहींकौवाखेड़ाः आरआर सेंटर की इंटरलॉकिंग धंसी।टेढ़वा कलाः मानकविहीन नाला और हाट बाजार निर्माण।अहिरन पुरवा (अरुवा): घटिया इंटरलॉकिंग।बेल्हौराः नाम मात्र की नाली।उल्लहाः इंटरलॉकिंग ज़मीन में समाई।सेमरा कलाः बदहाल नाली और सड़क।बारा सिंघाः वृक्षविहीन अमृत वाटिका, कागज़ी हरियाली।शाहपुरः रोड़ा-पत्थर विहीन इंटरलॉकिंग ने गुणवत्ता की चूलें हिला दीं।

प्रशासन की चुप्पी बनी सवालों की चट्टान

इन मामलों में ना सचिव संज्ञान ले रहे और ना ही खंड विकास अधिकारी के पास कोई ठोस जवाब है। ऐसा प्रतीत होता है कि सकरन क्षेत्र मानकविहीन निर्माण और फर्जी भुगतान का 'ओपन डेवलपमेंट क्राइम जोन' बन चुका है।

मनरेगा के तहत हो रहे कार्यों में लगाई जा रही फर्जी हाजरी जिम्मेदार कर रहे अनदेखा

कैनविज टाइम्स संवाददात

मछरेहटा, सीतापुर। जिले में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत कई गंभीर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। विकास खण्ड खैराबाद की ग्राम पंचायत भीमरी में फर्जी हाजिरी लगाने का कार्य किया जा रहा है ।नाम मात्र मजदूरो से कार्य करवाया जा रहा है। जबकि पोर्टल आधा सैकड़ा से ज्यादा मजदूरो की हाजरी लगाई जा रही है। ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक और पंचायत सचिव द्वारा लगाई गई फर्जी हाजरी के धन का आपस मे बंदरबांट किया जा रहा है। योगी सरकार जहाँ एक तरफ भ्रष्टाचार को खत्म करने का हर संभव प्रयास कर रही है वही दूसरी तरफ ग्राम प्रधान , पंचायत सचिव व रोजगार सेवक अपनी पूरी ताकत के साथ भ्रष्टाचार को मजबूत बनाने का कार्य कर रहे है। ब्लॉक स्तर पर बैठे अधिकारी जान बूझ कर अनजान बने हुए है।

निवेशकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें संबंधित अधिकारी: जिलाधिकारी

कैनविज टाइम्स संवाददात

सीतापुर । जिलाधिकारी अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में निवेश को प्रोत्साहित करने एवं निवेशकों को आ रही समस्याओं के त्वरित समाधान के संबंध में समीक्षा बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक के दौरान निवेशकों से संबंधित समस्याओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुये संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी ने कहा कि निवेश अनुकूल वातावरण तैयार करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जो भी निवेशक जनपद में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निवेश मित्र पोर्टल पर शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
?बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं संबंधित उद्यमियों/निवेशकों ने भाग लिया। जिलाधिकारी ने जनपद में स्थापित एवं प्रस्तावित उद्योगों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि निवेशकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। इ स अवसर पर भूमि आवंटन, विद्युत कनेक्शन, पर्यावरण अनापत्ति प्रमाणपत्र, एनओसी आदि से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। संबंधित विभागों को समस्याओं के समाधान हेतु स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान एजेण्डा प्रस्तुत करते हुये उपायुक्त उद्योग संजय सिंह ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 में जनपद सीतापुर में निवेश हेतु कुल 3462 इंटेट दाखिल करते हुये एवं 314 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गये थे। उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से जनपद में 17845 रोजगार सृजन प्रस्तावित है। बैठक के दौरान 14 निवेशकों द्वारा प्रस्तुत की गयी विभागवार समस्याओं के विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी, जिसमें 08 वन विभाग से संबंधित, 04 बैंकों से संबंधित, 01 विद्युत विभाग से संबंधित तथा 01 समस्या स्टेट मेडिकल फैकल्टी बोर्ड से संबंधित रही। समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। 05 कम्पनियों के एम0ओ0यू0 से संबंधित समस्या भी प्रस्तुत की गयी, जिसमें 02 समस्याएं स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित तथा 03 समस्याएं वन विभाग से संबंधित रहीं। जिलाधिकारी ने कहा कि इन निवेशकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें, जिससे जनपद में रोजगार के नवीन अवसर सृजित हो सके। बैठक में उपायुक्त उद्योग संजय सिंह, नगर मजिस्ट्रेट कृष्णा नंद तिवारी एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी व निवेशक उपस्थित रहे।

झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत, डॉक्टर गिरफ्तार

सीतापुर। थाना रामकोट क्षेत्र के ग्राम परागी लाल पुरवा में एक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान पुष्पा देवी पत्नी बबलू के रूप में हुई है, जो पिछले दो दिनों से बुखार से पीड़ित थीं।प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुधवार रात करीब 8:00 बजे पुष्पा देवी उम्र 28 वर्ष का उपचार खैराबाद क्षेत्र के मधवापुर चौराहे पर स्थित झोलाछाप डॉक्टर फिरदौस खान द्वारा किया जा रहा था। डॉक्टर ने मरीज को ग्लूकोज की तीन बोतलें चढ़ा दीं, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। महिला के हाथ-पैर ठंड से कांपने लगे और स्थिति गंभीर हो गई। परिजन उसे तत्काल घर ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतका के दो छोटे बच्चे हैं सूत्रों के अनुसार, मृतका ने कुछ समय पहले किसी अन्य झोलाछाप डॉक्टर से भी इलाज कराया था। घटना की सूचना मिलते ही थाना रामकोट पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर फिरदौस खान को गिरफ्तार कर लिया है।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

बाढ़ पूर्व की तैयारी के दृष्टिगत किया गया मॉक ड्रिल

कैनविज टाइम्स संवाददा

सीतापुर। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश के क्रम में 26 जून को प्रातः 09:00 बजे तहसील लहरपुर के ग्राम लखनीपुर पर0 तम्बौर, तहसील बिसवां के चहलारी घाट (घाघरा नदी) व महमूदाबाद के रामपुरमथुरा में बाढ़ आपदा पर आधारित राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज-2025 का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य संभावित बाढ़ आपदा की स्थिति में जिला स्तरीय विभागों की त्वरित प्रतिक्रिया, आपसी समन्वय और राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों का परीक्षण करना है।
अभ्यास स्थलों पर राहत शिविर, मेडिकल कैंप, इन्सीडेंट कमांड पोस्ट, स्टेजिंग एरिया की स्थापना, नाव, लाइफ जैकेट, रस्सी, वायर, मेगाफोन, वॉटर पंप, जनरेटर, मोबाइल टीम आदि की तैनाती, पशुओं के टीकाकरण, एम्बुलेंस, पीने के पानी, भोजन, अस्थायी आवास की व्यवस्था मौजूद रहीं तथा सभी संबंधित विभाग के अधिकारी अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के निर्देशन में तथा प्रभारी अधिकारी आपदा एवं अपर जिलाधिकारी वित्त नीतीश कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में सभी चिन्हित स्थलों पर मॉक एक्सरसाइज सकुशल सम्पन्न हुयी। विभागों द्वारा समय से आपदा प्रबंधन अभ्यास को गंभीरता से लेते हुये इसे पूर्ण किया गया। मॉक एक्सरसाइज की समाप्ति के उपरांत समस्त विभागों ने लोगों को आपदा प्रबंधन के बारे में बताया। राज्य और केंद्र द्वारा घोषित आपदाओं को आम जनमानस को अवगत कराया गया।

आमजन को किया गया सतर्क

मॉक एक्सरसाइज के दौरान पूर्व सूचना प्रणाली एवं कामन अलर्ट प्रोटोकॉल के तहत पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई। साथ ही पोस्टर, बैनर, मुनादी एवं पब्लिक एड्रेस सिस्टम से आम नागरिकों को जागरूक किया गया कि वे मॉक ड्रिल के दौरान अफवाहों से बचें और प्रशासन का सहयोग करें। मॉक ड्रिल का कार्यक्रम का कोऑर्डिनेशन आपदा विशेषज्ञ हीरालाल ने किया। उपजिलाधिकारी लहरपुर के नेतृत्व में ग्राम लखनीपुर स्थित मानपुर मल्लापुर घाट पर बाढ़ से बचाव की मॉकड्रिल का आयोजन भारतीय सेना से आये मा0 प्रेक्षको के प्रेक्षण में किया गया। जिसमें राजस्व विभाग, ग्राम विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, दमकल विद्युत विभाग, फूड स्पलाई विभाग, डोमगार्ड, पी0आर0डी0 लोक निर्माण विभाग पुलिस विभाग, पशु चिकित्सा आदि विभागों की टीमों द्वारा प्रतिभाग किया गया। मॉकड्रिल में मानपुर मल्लापुर घाट पर शारदा नदी में बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने तथा उनको प्राथमिक उपचार देने एवं सुरक्षित रूप से एम्बुलेंस/मेडिकल टीम तक पहुँचाने का अभ्यास किया गया तथा बाढ से पीड़ित व्यक्तियों को व उनके मवेशियों को ट्रैक्टर ट्राली व अन्य साधनों से सुरक्षित स्थान पर आश्रय स्थल पूर्व माध्यमिक विद्यालय मानपुर मल्लापुर पहुँचाया गया। यहाँ पर पहुँचने पर प्रत्येक बाढ़ पीड़ित का मेडिकल टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया तथा उपस्थित ग्रामीणो को बाढ़ से बचाव के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गई।

मॉकड्रिल : बाढ़ आई तो घबराइए मत,लखीमपुर प्रशासन तैयार है!

बाढ़ से पहले मैदान में उतरा प्रशासन, पांच तहसीलों में मॉक ड्रिल से परखी तैयारियां

सदर में खुद पहुंचे डीएम-एसपी, पलिया में एडीएम ने संभाला मोर्चा

कैनविज टाइम्स संवाददाता

लखीमपुर खीरी। नदी में पलटती नाव, गांवों में घुसता पानी, कटते रास्ते, ये कोई हकीकत नहीं, बल्कि लखीमपुर खीरी में गुरुवार को बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए आयोजित रियल मॉक ड्रिल की झलक थी। बाढ़ की संभावित आपदा से पहले गुरुवार को जिले में मॉक ड्रिल के जरिए प्रशासनिक तैयारियों की परख की गई। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी संकल्प शर्मा ने सदर तहसील के श्रीनगर गांव पहुंचकर कर्बला मैदान में चल रही मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। उन्होंने टीमों से परिचय कर उत्साह बढ़ाया और बच्चों को बिस्किट देकर मानवीय जुड़ाव का संदेश भी दिया।अधिकारियों ने चरणबद्ध प्रक्रिया की समीक्षा कर व्यवस्थाएं जांचीं। उधर, एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह पलिया में आयोजित मॉक ड्रिल में शामिल हुए, राहत-बचाव कार्यों की प्रगति का निरीक्षण कर जरूरी दिशानिर्देश दिए।

जमीन से जुड़े अभ्यास, हर स्थिति को किया गया सजीव

इस मॉक ड्रिल में नदी में नाव पलटने, बांध टूटने, गांवों में जलभराव, आग लगने और सड़क कटाव जैसी आपात स्थितियों को सजीव तरीके से दर्शाया गया। एनडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग, फायर ब्रिगेड, बाढ़ खंड, राजस्व, पुलिस सहित तमाम विभागों ने एकसाथ मिलकर अभ्यास किया। मौके पर पहुंचने से लेकर लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने और राहत कैंप में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तक, हर स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया का अभ्यास हुआ।

इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में लगातार निगरानी

कलेक्ट्रेट स्थित जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में मॉक ड्रिल के दौरान पूरे समय सक्रिय निगरानी रखी गई। शासन से प्राप्त सूचनाओं का तत्काल अनुपालन कराया गया। एसडीएम अमिता यादव की निगरानी में सेंटर का संचालन हुआ, वहीं दैवीय आपदा प्रभारी एसीआरए राम नरेश और आपदा विशेषज्ञ अंकित कुमार राज ने राहत व बचाव से जुड़ी सूचनाओं को विभागीय टीमों तक पहुंचाया।आपदा की सूचना, अलर्ट और समन्वय की हर कड़ी यहां से नियंत्रित की गई।

नदी में डूबती नाव, एनडीआरएफ ने दिखाई तत्परता

एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह की अगुवाई में बालूगंज रपटा पुल (शारदा नदी) पर नाव डूबने की मॉक सूचना पर एनडीआरएफ, मेडिकल और राहत टीमें मौके पर पहुंचीं। एक डूबते व्यक्ति को रेस्क्यू कर तत्काल एलएस एंबुलेंस से श्रीनगर मेडिकल कैंप पहुंचाया गया, जहां उपचार के बाद उसकी ''जान बचाई'' गई।*पलिया : बांध टूटा, गांव खाली, राहत कैंप में पहुंचाए लोग*पलिया में एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह और एसडीएम रत्नाकर मिश्रा की निगरानी में बांध टूटने की सूचना पर तेजी से रेस्क्यू शुरू हुआ।बाढ़ खंड ने त्वरित अनुरक्षण कार्य शुरू कर दिया और प्रभावित गांवों से लोगों को सुरक्षित राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया।

गोला में आवासीय आग, फायर ब्रिगेड की तत्परता से बची जान

गोला एसडीएम विनोद कुमार गुप्ता के नेतृत्व में आवासीय भवनों में आग लगने की मॉक ड्रिल की गई। फायर टेंडर ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, घायलों को प्राथमिक उपचार देकर राहत कैंप भेजा गया।*धौरहरा : बांध से पानी छोड़ा गया, गांववालों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया*धौरहरा एसडीएम राजेश कुमार की देखरेख में हुई मॉक ड्रिल में बांध से पानी छोड़े जाने की सूचना पर तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। गांव के लोगों को पहले से तैयार राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया जहां भोजन, दवा और ठहराव की पूरी व्यवस्था थी।*निघासनः सड़क टूटी, गांव कटे, पीडब्ल्यूडी ने फटाफट मार्ग दुरुस्त किया*निघासन एसडीएम राजीव कुमार के नेतृत्व में मुख्य मार्ग कटने की सूचना पर घ्डकने तत्परता से मरम्मत कार्य शुरू किया। इस दौरान प्रभावित गांवों के निवासियों को सुरक्षित रिलीफ कैंपों में पहुंचाया गया।

दुष्कर्म का आरोपी निसार गिरफ्तार

लखीमपुर खीरी। पुलिस अधीक्षक खीरी, संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना शारदानगर के नेतृत्व में आज दिनांक-26.06.2025 को थाना शारदानगर पुलिस द्वारा मुअसं 182/25 धारा 64(1)/351920 बीएनएस में वांछित अभियुक्त निसार पुत्र खुर्शीद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान न्यायालय भेजा जा रहा है।

ठगी करने वाले गिरोह का सरगना बाबा इंशा अली गिरफ्तार

लखीमपुर खीरी। पुलिस अधीक्षक खीरी, संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी निघासन के कुशल मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना निघासन के नेतृत्व में आज दिनांक-26.06.2025 को थाना निघासन पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 158/2025 धारा 318(4)/319(2)/308(5)/316(2)/317(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त बाबा इंशा अली पुत्र स्व0 वाजिद अली निवासी ग्राम मिर्ज़ागंज थाना निघासन जनपद खीरी को ग्राम महुआ जाने वाले पक्की सड़क से हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से 17,000 रुपये नगद बरामद हा है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।घटना का विवरण

शादी के बहने बहला फुसलाकर लड़कियों को भगा ले जाने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार

लखीमपुर खीरी। पुलिस अधीक्षक खीरी, संकल्प शर्मा द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मितौली के कुशल मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना मितौली के नेतृत्व में थाना मितौली पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 165/25 धारा 137(2)/87/64(1)/49/65(1) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट से संबंधित शादी के उद्देश्य से बहला फुसलाकर लड़कियो को भगा ले जाने वाले 03 नफर वांछित अभियुक्तों .सत्यप्रकाश कश्यप पुत्र स्व0 छोटेलाल सौरभ कश्यप पुत्र सत्यप्रकाश नीशू कश्यप पुत्र रामसेवक उर्फ लालू सर्व निवासीगण कस्बा व थाना मितौली जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुये अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

चोरों ने दो दिन मे तीन घरों पर हाथ किये साफ

मैगलगंज खीरी। मैगलगंज थाना क्षेत्र मे चोरो का आतंक लगातार जारी है।दो दिन पहले मंगलवार कि रात हल्का नंबर तीन (पकरिया चौकी) के गांव कोल्हौरा मे चोरो ने दो घरो को निशाना बनाया था,जिसके बाद बुधवार कि रात पुनः उसी हल्का के गांव बख्तियारपुर गांव निवासी मनोज के यहां चोरो ने नकदी सहित लाखो के जेवरात कि घटना को दिया अंजाम। चोरी कि जानकारी होने के बाद परिजनों ने हल्का नंबर तीन कि पुलिस व पी आर वी से चोरी होने के बारे मे जानकारी दी। हल्का तीन मे चोरो का आतंक लगातार जारी है। पुलिस गस्त पर उठ रहे सबाल, हल्का इंचार्ज अपना हल्का संभालने मे दिख रहे असमर्थ, मंगलवार कि रात चोरी हो जाने के बाद भी नहीं सक्रिय हो सके हल्का इंचार्ज व उनकी टीम जिसके चलते चोरो ने उसी क्षेत्र मे एक और बख्तियारपुर गाव मे घर को निशाना बनाते हुए हाथ साफ कर लिया। मैगलगंज पुलिस कि लचर कार्य शैली के चलते चोरो के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद हो रहे है। नवागत प्रभारी निरीक्षक मैगलगंज को थाना का चार्ज संभाले एक सप्ताह भी न हो पाया कि तब तक चोरियो का शिलशीला पुनः जारी हो गया और चोरो नवागत प्रभारी निरीक्षक व हल्का इंचार्ज प्रेमचंद्र रावत को दे दी तीन और नई चुनौती। हल्का इंचार्ज अपने क्षेत्र मे अपराध पर नियंत्रण लगाने मे असमर्थ चोरो और लुटेरों मे नहीं है पुलिस का भय।

बाल विवाह रोकथाम को लेकर खीरी की मासिक समन्वय बैठक

कैनविज टाइम्स संवाददाता

लखीमपुर खीरी। पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) महोदय की अध्यक्षता में ट्टख्व्ठ व इ.क्र्व्ठ.ठ की मासिक समीक्षा एव समन्वय गोष्ठी आहूत की गयी जिसमें श्री शिवम कुमार क्षेत्राधिकारी पुलिस लाइन खीरी ,श्री अभिमन्यु त्रिपाठी उपाधीक्षक जनपद खीरी , सी डब्ल्यूसी के अध्यक्ष एसपी सिंह, श्रमविभाग से अजय कुमार, शिक्षा विभाग से रेनू श्रीवास्तव, चाइल्ड लाइन खीरी से अंजुमन परवीन , रश्मि चतुर्वेदी प्रभारी वन स्टाफ सेंटर व रश्मि वर्मा, जिला प्रोबेशन कार्यालय नीतू निषाद, जिला बल संरक्षण इकाई से काउंसलर कय्यूम जरवानी, एम ट्रस्ट से प्रियंका वर्मा, अशोक कुमार, असहद ,बचपन बचाओ आंदोलन से राजबहादुर , इंद्र कुमार, मानव सेवा संस्थान तिकुनिया से अवधेश कुमार व बाल कल्याण अधिकारी अन्य विभागों के अधिकारीगण शामिल हुए जिसमें पूर्व में जारी किए गए कार्यवृत का अनुपालन के संबंध में चर्चा की गई। उपस्थित अन्य अधिकारी गण द्वारा महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी बाल ट्टग्घ (बाल विवाह रोकथाम हेतु) अनुसंधान एवं थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के समक्ष आ रही समस्या, एवं सुझाव पीड़ितों के अश्वासन, बाल गुमशुदा, बाल श्रम, नशा मुक्त अभियान, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैंगिक समानता, नारी शक्ति किशोर न्याय अधिनियम 2015 मे हुए नवीनतम संशोधन पोस्को को एक्ट के अभियोग पंजीकृत होने के 24 घंटे के अंदर सीडब्ल्यूसी को सूचित करना, पॉस्को के मामले में फार्म ए व बी पुलिस द्वारा भरकर संबंधित को समय से भेजा जाना बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य का पालन, जे.जे एक्ट के समेत अन्य पर चर्चा की गयी।

नेतृत्वहीन मैगलगंज: समस्याओं का अंतहीन सिलसिला

यह मैगलगंज है, यहां पद चाहिए , जिम्मेदारी नहीं!

कैनविज टाइम्स संवाददाता

मैगलगंज खीरी। मैगलगंज कस्बा आज भी उन बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है जो किसी भी सभ्य समाज की प्राथमिक आवश्यकता होती हैं। बिजली, स्वच्छ पानी, पक्की सड़कें, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा जलबहाव ये सब आज भी मैगलगंज के लिए एक सपना बने हुए हैं। सबसे बड़ा कारण संसाधनों की कमी नहीं, नेतृत्व का अभाव है। यहां पद पाने की होड़ तो खूब है, लेकिन जब जिम्मेदारी निभाने की बात आती है तो सब मौन हो जाते हैं। कुछ ने तो पद को केवल औपचारिकता और व्यक्तिगत लाभ का साधन बना लिया है। उन्हें न तो पद की गरिमा का बोध है, न ही जनता के प्रति जवाबदेही का।

नालियां या नाले – हैं भी या नहीं?

कस्बे की गलियां गंदे पानी से लबालब हैं।जो नालियां बनी थीं, उनकी कभी सफाई नहीं हुई, वे आज जाम हैं।और जो नालियां कभी बनी ही नहीं, वहां सड़क निर्माण के दौरान कार्यदायी संस्था ने बिना निकासी व्यवस्था के नालों को बंद कर दिया और चुपचाप चली गई।अब स्थिति यह है कि घर और दुकानों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है।बनी हुई सड़कों पर सीमेंट डालकर उन्हें ऊंचा कर दिया गया, लेकिन ये नहीं सोचा गया कि जब नालियां नहीं होंगी, तो बारिश का पानी जाएगा कहां?नतीजाः हर बारिश में जलभराव, बदबू और बीमारी।

बिजली की समस्या, हाई और लो का खेल

बिजली की स्थिति भी बदतर है।हर दूसरे दिन हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है।परंतु अधिकारी और जनप्रतिनिधि खामोश हैं।

कस्बे की पीड़ा,नेतृत्वविहीनता की कीमत

यह स्पष्ट है कि मैगलगंज नेतृत्वविहीन हो गया है।जनता समस्याओं के दलदल में फंसी है, और जिम्मेदार लोग कुर्सी पर विराजमान होकर तमाशा देख रहे हैं।

अब जनता खामोश नहीं रहेगी

जनता का धैर्य टूट रहा है।अब समय है कि ऐसा नेतृत्व चुना जाए जो केवल कुर्सी पर बैठने के लिए न हो, बल्कि जनहित को सर्वोपरि रखे।ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जिसे मैगलगंज की समस्याओं की पीड़ा समझ में आए, और जो वास्तव में विकास के लिए संकल्पबद्ध हो।

महिला आयोग की सदस्य ने वन स्टॉप सेंटर, महिला थाना का किया निरीक्षण

महिला आयोग सदस्य ने केक काटकर कन्या जन्मोत्सव का किया शुभारम्भ

सीएचसी महराजगंज में कन्या जन्मोत्सव व जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन

कैनविज टाइम्स संवाददाता

रायबरेली । उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य पूनम द्विवेदी ने जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान आज वन स्टाप सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सदस्य द्वारा वन स्टॉप सन्टर में आवासित पीड़िताओं से उनके कुशलक्षेम पूछा। उन्होंने उपस्थित मैनेजर आस्था ज्योति व काउंसलर श्रद्धा सिंह से विस्तृत रुप से जानकारी ली गयी। काउंसलर श्रद्धा सिंह द्वारा वन स्टाप सेन्टर में महिलाओं के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं से महिला आयोग की सदस्य को अवगत कराया गया। सदस्य द्वारा निर्देशित किया गया कि आवासित पीड़िताओं का समस्याओं का समाधान करते हुए अवगत कराये। उन्होंने इसके अतिरिक्त पीड़िताओं/महिलाओं को विधिक, चिकित्सकीय, मानसिक, दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को नियमानुसार उपलब्ध कराये जाने की सलाह के साथ भोजन के सम्बन्ध मे जानकारी ली गयी। इसके पश्चात महिला आयोग की सदस्य ने महिला थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला हेल्पडेस्क पर उपस्थित पुलिस महिला कर्मियों से जानकारी ली तथा रजिस्टरों का अवलोकन भी किया। उन्होंने उपस्थित थाना प्रभारी से कहा कि आने वाले फरियादियों की शिकायतों का निस्तारण नियमानुसार समय से किया जाना सुनिश्चित करें। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दृष्टिगत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महराजगंज में कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। जिसका शुभारम्भ महिला आयोग सदस्य ने केक कटवा कर एवं 45 नवजात बच्चियों के माता पिता को बेबी किट वितरण के साथ ही उनको बेटियों के जन्म पर बधाई व शुभकामनायें दी। उन्होंने नवजात माता पिता को कन्या सुमंगला योजना सहित अन्य योजनाओं के बारे जानकारी दी। इस मौके पर जिला प्रोबेशन अधिकारी जयपाल वर्मा, महिला थानाध्यक्ष किरन, संरक्षण अधिकारी वीरेन्द्र पाल सहित अन्य कर्मचारी गण उपस्थित रहें।

छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए समय से करें ऑनलाइन आवेदन

रायबरेली। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहन त्रिपाठी ने बताया है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में शासन द्वारा निर्गत समय सारणी के अनुसार पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9 एवं 10) योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटा तैयार करने हेतु 01 जुलाई 2025 से 05 अक्टूबर 2025 तक छात्र-छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने हेतु 02 जुलाई द्वारा 2025 से 30 अक्टूबर 2025 तक तथा शिक्षण संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्रों को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने हेतु 03 जुलाई 2025 से 06 नवंबर 2025 तक तिथि निर्धारित की गई है। मोहन त्रिपाठी ने कहा है कि जनपद के समस्त शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य/प्रधानाचार्य को सूचित किया जाता है कि निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यवाही पूर्ण किए जाने हेतु छात्र-छात्राओं को अवगत कराए और अपने स्तर से भी समय से कार्यवाही पूर्ण करें। जनपद में अल्पसंख्यक वर्ग हेतु और एनएसपी पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की मार्किंग किए जाने हेतु एनएसपी पोर्टल पर पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है। जिससे कोई भी पात्र छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित न रहे।

डलमऊ में बाढ़ आपदा पर राज्यस्तरीय मार्क एक्सरसाइज का आयोजन सम्पन्न

रायबरेली। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) अमृता सिंह के कुशल मार्गदर्शन में आज तहसील डलमऊ में बाढ़ आपदा पर राज्यस्तरीय मार्क एक्सरसाइज-2025 का आयोजन किया गया। इस आयोजन के द्वारा बाढ़ जैसी आपदाओं के समय प्रशासनिक तैयारियों एवं प्रतिक्रिया को परखना था। मॉक एक्सरसाइज में बाढ़ जैसी आपदाओं के समय प्रभावी प्रबन्धन और बचाव कार्यों का अभ्यास किया गया। तहसील प्रशासन ने अपनी तैयारियों को प्रदर्शन किया और आपदा के समय तेजी से प्रतिक्रिया देने की क्षमता का परीक्षण किया। मॉक एक्सरसाइज का उद्देश्य बाढ़ जैसी आपदाओं के समय प्रभावी प्रबंधन और बचाव कार्य को सुनिश्चित करना। प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन क्षमता का विकास करना। स्थानीय समुदाय में आपदा प्रबंधन और बचाव कार्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है । इस अवसर उपजिलाधिकारी डलमऊ अहमद फरीद खान, सी0ओ0 अरूण कुमार, तहसीलदार डलमऊ उमेश चंद्र सहित सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

विद्यालय के प्रधानाचार्य समय सारणी के अनुसार पूर्ण करें कार्यवाही

रायबरेली। जिला समाज कल्याण अधिकारी सृष्टि अवस्थी ने बताया है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में शासन द्वारा निर्गत समय सारणी के अनुसार पूर्वदशम (कक्षा 9 एवं 10) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटा तैयार करने हेतु 01 जुलाई 2025 से 05 अक्टूबर 2025 तक छात्र-छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने हेतु 02 जुलाई 2025 से 30 अक्टूबर 2025 तक तथा शिक्षण संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्रों को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने हेतु 03 जुलाई 2025 से 06 नवंबर 2025 तक तिथि निर्धारित की गई है। सृष्टि अवस्थी ने कहा है कि जनपद के समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य को सूचित किया जाता है कि निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यवाही पूर्ण किए जाने हेतु छात्रों को अवगत कराए और अपने स्तर से भी समय से कार्यवाही पूर्ण करें। जिससे कोई भी पात्र छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित न रहे।

छात्रवृति योजना का लाभ लेने के लिए समय से करें ऑनलाइन आवेदन

रायबरेली। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहन त्रिपाठी ने बताया है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में शासन द्वारा निर्गत समय सारणी के अनुसार पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9 एवं 10) योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटा तैयार करने हेतु 01 जुलाई 2025 से 05 अक्टूबर 2025 तक छात्र-छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने हेतु 02 जुलाई द्वारा 2025 से 30 अक्टूबर 2025 तक तथा शिक्षण संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्रों को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने हेतु 03 जुलाई 2025 से 06 नवंबर 2025 तक तिथि निर्धारित की गई है। मोहन त्रिपाठी ने कहा है कि जनपद के समस्त शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य/प्रधानाचार्य को सूचित किया जाता है कि निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यवाही पूर्ण किए जाने हेतु छात्र-छात्राओं को अवगत कराए और अपने स्तर से भी समय से कार्यवाही पूर्ण करें।

राजर्षी छत्रपति शाहूजी महाराज की जयंती अपना दल एस के जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न

कैनविज टाइम्स संवाददाता

उन्नाव। अपना दल एस द्वारा राजर्षी छत्रपति शाहूजी महाराज की जयंती बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र के बौद्ध पर्यटन स्थल नेवल गांव में धूमधाम से मनाई गई। मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष लखनऊ मंडल एवं कार्यवाहक जिला अध्यक्ष अमरेश पटेल जी उपस्थित रहे। सर्वप्रथम सभी कार्यकर्ताओं ने साहू जी के चित्र पर पुष्प चढ़ा कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जी ने उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि साहू जी महाराज ने 1894 से कोल्हापुर नरेश के रूप में शासन को संभाला। इन्होंने शिक्षा को अलग जगाते हुए गरीब पिछड़ों को आरक्षण एवं छात्रावास की स्थापना की और आरक्षण के जनक कहलाए तथा सभी वर्गों के लिए प्राथमिक शिक्षा मुफ्त शिक्षा अनिवार्य करने की शुरुआत की व गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। देवदासी प्रथा को समाप्त किया तथा अंतर जाति विवाह की भी पुरजोर वकालत की। वैदिक विद्यालयों की स्थापना की जिससे सभी वर्गों के छात्रों को शास्त्रों का ज्ञान एवं संस्कृत शिक्षा का प्रचार प्रसार करने में सक्षम बनाया जा सके। इन्होंने अपने 28 वर्ष के शासनकाल में सभी शोषितो वंचितों की हिफाजत की एक न्याय प्रिय शासन के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष विकास पटेल ने तथा संचालन कार्यक्रम प्रभारी जिला उपाध्यक्ष डॉ राजेश पाल ने किया। जयंती को जिला महासचिव सुधांशु कटियार व ओमकार मौर्य तथा सहकारिता मंच के जिला अध्यक्ष कौशल गुप्ता ने भी संबोधित किया। मुख्य रूप से जिला सचिव कुंवर पाल आर्य, जोन अध्यक्ष विनोद कटियार, जिला सचिव युवा मंच अमन शर्मा, आनंद अर्कवंशी, बेचेलाल दिवाकर, जिला उपाध्यक्ष सांस्कृतिक मंच बंसीलाल अर्कवंशी, महेश गुप्ता,अनिल गौतम, सतीश कटियार,जगन्नाथ प्रजापति आदि लोग उपस्थित रहे।

घरेलू कलह से परेशान युवक ने खाया जहरीला पदार्थ, इलाज के दौरान मौत

सुसाइड नोट में ससुराल पक्ष को ठहराया ज़िम्मेदार

कैनविज टाइम्स संवाददाता

उन्नाव। सदर कोतवाली क्षेत्र के हिरन नगर मोहल्ला निवासी शाह मोहम्मद (42) पुत्र सलीम अहमद की ज़हरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। गंभीर हालत में परिजन उसे कानपुर के हैलट अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। परिजनों ने मृतक की पत्नी नाजमा खातून व उसके पिता मकबूल खान के खिलाफ सदर कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।आपको बताते चलें कि शाह मोहम्मद की शादी करीब 10 साल पहले लखनऊ निवासी नाजमा खातून से हुई थी। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। परिजनों के अनुसार, बीते ढाई साल से नाजमा अपने मायके में रह रही थी और लगातार मानसिक रूप से शाह मोहम्मद को प्रताड़ित कर रही थी। इसी तनाव के चलते उसने यह खौफनाक कदम उठाया। मृतक की उन्नाव हाईवे पर ऑटो पार्ट्स की दुकान थी। लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह मानसिक रूप से परेशान भी था। मृतक ने सुसाइड नोट में लिखा ‎ह्मोहम्मद उर्फ शानू नाजमा खातून और मकबूल खान की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं। इन दोनों बाप-बेटी ने इतना प्रताड़ित किया है कि हम वक्त से पहले जान दे रहे हैं। नाजमा ने अपनी शिकायत में सारी बातें झूठ लिखी हैं। हमारा कोई ट्रांसपोर्ट का पापर्री (प्रॉपर्टी) या इल्लीगल काम नहीं है।

नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सख्त कार्यवाही करें: डीएम

जिला स्तरीय एनकार्ड समिति की बैठक सम्पन्न

कैनविज टाइम्स संवाददाता

रायबरेली। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में नशीले पदार्थों की तस्करी एवं प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री की रोकथाम के लिए जिला स्तरीय एनकोर्ड समिति की बैठक बचत भवन स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में नशीली दवाओं एवं ड्रग के दुरुपयोग को रोकने, जिले में अफीम या भांग की फसल की अवैध खेती एवं भंडार, संलिप्त लोगों का व्यपवर्तन, प्रतिबंधित दवाओं के दुरुपयोग व तस्करी मुख्य एजेंडा रहा। जिलाधिकारी ने इस संबंध में किए जाने वाले कार्यवाही की जानकारी लेते हुए अवैध तरीके से अफीम के उत्पादन होने की संभावना पर निगरानी रखने, ड्रग व नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने एवं कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संवेदनशील क्षेत्रों/अति संवेदनशील स्थानों की पहचान करने व नशीले पदार्थों के अवैध व्यवसाय को रोकने के लिए साइकोट्रोपिक दवाओं की बिक्री और खरीद पर निगरानी, मेडिकल स्टोर्स द्वारा प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवाओं की अवैध बिक्री पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों को स्कूल/कालेजों में नशा मुक्ति अभियान चलाए जाने, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभाव से विद्यार्थियों को समझाने, स्कूल/कॉलेज परिसर और आस-पास नशा विरोधी रैली व जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम (वि/रा) अमृता सिंह, जिला आबकारी अधिकारी दिनेश कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवेंद्र सिंह,जिला समाज कल्याण अधिकारी सृष्टि अवस्थी, एसीएमओ अरविंद यादव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

तहसील लालगंज में बाढ़ आपदा पूर्व तैयारी के लिये राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज सम्पन्न

कैनविज टाइम्स संवाददाता

रायबरेली। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के कुशल मार्गदर्शन में एवं उपजिलाधिकारी लालगंज मिथिलेश त्रिपाठी के नेतृत्व में तहसील लालगंज के अन्तर्गत ग्राम कोटिया एहतमाली परगना सरेनी तहसील लालगंज गंगा घाट पर बाढ़ आपदा के अन्तर्गत बाढ़ से बचाव व ग्रामीणों को जागरूक करने हेतु बाढ़ आपदा पर राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज-2025 की गयी। मॉक एक्सरसाइज के दौरान सर्वप्रथम कैम्प गंगा नदी से ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया। गंगा नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है तथा गंगा नदी में बाढ़ की स्थिति बन जाने के कारण ग्रामीणों को बाढ़ आश्रय स्थल पर ले जाया गया तथा बाढ़ में फसे प्रभावित व्यक्तियों को रेस्क्यू किया गया तथा बाढ़ के कारण कच्चा मकान गिरने से एक बच्चे के मकान के अवशेष में दबे होने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल राहत हेतु घाट पर उपस्थित पुलिस बल व राजस्व बल तथा स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बचाव कार्य प्रारम्भ किया गया तथा बच्चे को मकान के मलबे से निकाल कर उपस्थित स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा तत्काल स्टेचर के माध्यम से प्राथमिक उपचार करते हुये राहत कैम्प में लाया गया। वहां पर उपस्थित स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सर्वप्रथम बचाये गये, बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उनका ‌इ्रटड्ड इ्रक एइटक्क्लग्र्ङ्खख्रगइ्टड्ड इट्टक्ल्ड्डख्रक्ल्ड किया गया तथा उन्हे सी0पी0आर दिया गया, उसके बाद उसका प्राथमिक मुख्य उपचार किया गया, इसके उपरान्त एम्बुलेंश के माध्यम से उच्च स्वास्थ्य उपचार हेतु नजदीकी प्राथमिक सामुदायिक केन्द्र झाऊखेड़ा सरेनी ले जाया गया, वहां पर उपचार के उपरान्त स्वस्थ पाये जाने पर स्वास्थ्य लाभ हेतु उनके घर मेडिकल टीम की देख-रेख में एम्बुलेंश के माध्यम से भिजवा दिया गया। इस एक्सरसाइज के दौरान उ0प्र0. राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण लखनऊ द्वारा आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जुड़े रहे तथा उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया गया। इस मॉक एक्सरसाइज के दौरान चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग, पूर्ति निरीक्षक विभाग, अग्निशमन विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, सिंचाई विभाग व राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

समस्त थोक विक्रेताओं एवं उर्वरक कंपनी प्रतिनिधियो की समीक्षा बैठक सम्पन्न

कैनविज टाइम्स संवाददाता

उन्नाव। संयुक्त कृषि निदेशक लखनऊ मंडल लखनऊ द्वारा जनपद के समस्त थोक विक्रेताओं एवं उर्वरक कंपनी प्रतिनिधियो की समीक्षा बैठक की गई। यूरिया, डीएपी, एनपीके, कॉम्प्लेक्स एवं एमओपी की निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य दर के अंतर्गत बिक्री सुनिश्चित कराई जाये। यदि कोई उर्वरक विक्रेता अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर उर्वरक बिक्री करता हुआ पाया जाये तो उसके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत निहित प्राविधानुसार कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। आपूर्तित एवं उपलब्ध उर्वरकों का कृषकों के मध्य उनकी कृषि जोत, फसल के अनुसार एवं उनके आधार कार्ड के आधार पर वितरण सुनिश्चित की जायेगी। तथा बिक्री के उपरोक्त किसानों को कैश मेमो/बिल अवश्य दिया जाए। समस्त थोक उर्वरक विक्रेता एवं कंपनी प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि फुटकर उर्वरक विक्रेता मुख्य उर्वरक यथा यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी एव एसएसपी के साथ अन्य उर्वरक उत्पादो को भी खरीदने हेतु बाध्य करता है तो बाध्यता की पुष्टि होने पर उनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं अन्य प्राविधानो के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।समस्त थोक विक्रेता अपने सम्बन्धित समस्त खुदरा विक्रेताओ को सूचित करे कि प्रत्येक उर्वरक व्यवसायी के स्तर पर स्टॉक पंजिका, विक्रय पंजिका तथा रसीद अनिवार्य रूप से रखी जाये या ऐसे प्रारूप जो तिथिवार स्टॉक स्थिति, आरम्भिक अवशेष, दिन के दौरान प्राप्तियां, दिन के दौरान विक्रय और अन्तिम स्टॉक को स्पष्ट प्रदर्शित करता हो, का होना आवश्यक है। थोक फुटकर उर्वरक विक्रेताओं तथा उर्वरक बिक्री केन्द्रो पर उर्वरकों की उर्वरकवार बिक्री दर तथा स्टॉक का अंकन रेट तथा स्टॉक बोर्ड पर प्रतिदिन अंकित किया जाये। ऐसी नही करने वाले विक्रेता के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। बैठक का समापन करते हुए संयुक्त कृषि निदेशक लखनऊ मंडल लखनऊ ने बैठक में मौजूद समस्त कंपनी प्रतिनिधि एवं थोक विक्रेताओं को निर्देशित किया कि उर्वरकों की कालाबाजारी, अवैध भण्डारण एवं ओवर-रेटिंग व टैगिंग कदापि न हो पाये, तथा नियमों तथा निर्देशो की अवहेलना करने वाले सम्बन्धित के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

टेंट हाउस गोदाम में लगी आग सामान जलकर हुआ खाक

कैनविज टाइम्स संवाददाता

महराजगंज,रायबरेली। तहसील के इन्हौना रोड पर स्थित एक टेंट हाउस के गोदाम में आज गुरवार सुबह करीब चार बजे अचानक आग लग गई। कोतवाली महराजगंज क्षेत्र के इन्हौना रोड पर पूरे रानी वार्ड नंबर एक आजाद नगर में आग लगने की सूचना मिलते ही फायरब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई, उसने आग पर काबू पाने का भरकस प्रयत्न किया, जब एक गाड़ी से काम नहीं चला, तो दूसरी फायरब्रिगेड की गाड़ी रायबरेली शहर से फोन करके बुलाया गया, तब जाकर आग पर पूरी तरह काबू पाया गया, किन्तु तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। आपको बता दे कि, घटना महराजगंज तहसील क्षेत्र के इन्हौना रोड पर स्थित पूरे रानी वार्ड नंबर एक आजद नगर टाउन एरिया महराजगंज की है। यहा के रहने वाले धर्मेश मौर्य पिछले 35 वर्षो से दुर्गा टेंट हाउस के नाम से संचालन करते हैं। यह टेंट हाउस क्षेत्र में वीआईपी टेंट हउसों में एक था, आधुनिक सुख सुविधाओं युक्त इस टेंट हाउस की क्षेत्र में शादी विवाह व अन्य फैमिली फक्शनों के अवसर पर काफी मांग थी। गुरवार को सुबह लगभग 4 बजे टेंट हाउस के गोदाम में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिससे गोदाम में रखे रजाई, गद्दे, कुर्सियां, पर्दे और साज सज्जा के सामान सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। सुबह जब नित्य क्रिया के लिए पड़ोसी उठे तो उन्होंने देखा कि, टेंट हाउस के गोदाम में आग लगी है और वह धू-धू कर जल रहा है। उन्होंने फौरन शोर मचाना सुरु किया, और टेंट हाउस गोदाम के सामने स्थित टेंट हाउस के मालिक धर्मेश मौर्य के घर में आग लगने की घटना की जानकारी दी। पीड़ित परिवार और पड़ोसियों की मदद से पहले तो टुल्लू पंप और बाल्टियों के सहारे पानी डाल कर आग बुझाने की कशिश करी गई, किंतु जब आग पर काबू नहीं पा सके तो अग्निशमन विभाग को फोन करके आगजनी के घटना की जानकारी दी। सूचना पाकर फौरन अग्निशमन विभाग के अधिकारी गाड़ी लेकर घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, किंतु जब आज पर काबू नहीं मिल पाया तो अग्निशमन विभाग के अधिकारियों द्वारा रायबरेली शहर फोन करके वहां से दूसरी गाड़ी मंगवाई गई, तब जाकर आज पर काबू पाया गया। किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी और टेंट हाउस का लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। दुर्गा टेंट हउस के मालिक धर्मेश मौर्य के छोटे भाई ने बताया कि, उनके गोदाम में अज्ञात कारणों से लगी आग में लगभग 25 से 30 लाख रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया है। सूचना पाकर मौके पर तहसील प्रशासन भी पहुंचा, हल्का लेखपाल ने क्षति का आकलन कर उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही है।

अवैध नर्सिंग होम पर नहीं हो रही कार्रवाई,जिम्मेदार मौन

बिना रजिस्ट्रेशन व सुविधाओं के चल रहे अस्पतालों ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी है

कैनविज टाइम्स संवाददाता

गोण्डा। जिले में सैकड़ों अवैध हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर चल रहे हैं कोई अस्पताल दो कमरे में चल र हा है तो कोई किराए के मकान में इनमें ज्यादातर में झोलाछाप इलाज के नाम पर मरीजों से वसूली कर रहे हैं।शहर में संचालित अवैध अस्पतालों में प्रशिक्षित स्टाफ नर्स नहीं होती हैं और न ही ट्रेड टेक्नीशियन रखे जाते हैं। इस तरह के अस्पतालों में लापरवाही की हद तो यह है कि आयुर्वेदिक स्नात क की डिग्री पर चिकित्सक गंभीर अवस्था के मरी जों का सीजर ऑपरेशन करते हैं।ऑपरेशन टेबल पर मरीजों का केस बिगड़ने पर बाहर से प्रशिक्षित चिकित्सकों को बुलाया जाता है।वही जिले में अवै ध रूप से चलाए जा रहे नर्सिग होम व अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा नहीं कसने से मान कों को ताक पर रखकर चलाए जाने वाले अवैध अस्पतालों के संचालको के हौसले बुलंद है बिना रजिस्ट्रेशन व सुविधाओं के चल रहे अस्पतालों ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी है। मनमाने तरी के से चलाए जा रहे अस्पतालों के सवालों के घेरे में आने के साथ ही विभागीय कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे है।जिले के तहसील करनैलगंज ब्लॉक परसपुर व कर्नलगंज क्षेत्र में तकरीबन दर्जनो से अधि क अस्पताल मानक विहीन अस्प ताल है जो स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से बचें हुए हैं।

मरीजों की जान से कर रहे खिलवाड़

स्वास्थ्य विभाग के सेटिंग गेटिंग के खेल चलते इन अस्पतालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती है ये मानक विहीन अस्पताल बड़ी बीमारी बताकर अ स्पताल आये हुए मरीजों का शोषण करते है।बिना पंजीकरण के अस्पतालों का संचालन करने वाले संचालक अथवा ऐसे जगहों पर तैनात डॉक्टर ग म्भीर रूप से सामान्य बीमारी से बीमार मरीजों को भी बड़ी बीमारी बताकर लम्बा इलाज करते है और शोषण करते है।वही प्रसव के आने वाली महिला ओं को बिना जांच के ही ऑपरेशन की सलाह दे दी जाती है जिससे कई बार महिलाओं व नवजात की जान भी चली जाती है।

सैकड़ों से अधिक संचालित हो रहे अस्पताल

गोण्डा जिले में सैकड़ो सौ से अधिक अस्पताल व नर्सिग होम का संचालन किया जा रहा है जहां पर ओपीडी से लगाकर ऑपरेशन तक की सुविधा मु हैया कराई जा रही है संसाधनों के अभाव के बीच में प्रशासन की बगैर जानकारी के चल रहे है और इन अस्पतालों होने वाली मौतों का भी पता नहीं चल पाता है मनमाने तरीके से चलने वाले अस्पता लों पर होने वाली मौतों तक का पता प्रशासन या लोगों को पता तब चलता है जब परिवार के लोग मामले की शिकायत करतें है या फिर मौत के बाद हो हल्ला करते है।वही कर्नलगंज में सीएचसी के नाक के नीचे अवैध नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं।सूत्र बता रहे हैं कि अगर सीएचसी पर देखा जा ए तो नॉर्मल डिलीवरी को छोड़कर ऑपरेशन नहीं हुआ है।अधिकतर मरीजों को डरा धमका कर वहां पर तैनात आशाएं इतना डर और धमका देती है मरता क्या नहीं करता इतना डर और भय पैदा कर देती हैं कि वहां पर पहले से मौजूद अवैध नर्सिंग होम का संचालक अपने ही नर्सिंग होम में आशा ओं के सहारे भर्ती करवा जाता है।फिर शुरू होता है अवैध नर्सिंग होम के संचालक का खेल वही इस पूरे मामलें को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रश्मि वर्मा से लेने की कोशिश की गई तो उनका मोबाइल फोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बताया और जानकारी नहीं मिल पाई है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर लटक रहा ताला

कैनविज टाइम्स संवाददाता

गोण्डा। जिले की ग्राम पंचायत आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्र दुल्हापुर में मरीजों की सुविधा के लि ए स्थापित आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिखावा साबि त हो रहे हैं।यहां पर तैनात सीएचओ,एएनएम व अ न्य कर्मी ओपीडी के समय नदारद रहती हैं।ऐसे में मरीजों को सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।बृहस्पतिवार को विकासखंड मुजेहना के उपकेंद्र दुल्हापुर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर की पड़ताल की गई।जिसमें ताला लटक रहा था।उपकेंद्र के आसपास सन्नाटा पसरा था।वहां पर मौजूद गाँव के एक व्यक्ति ने मौखिक रूप से बताया किया क भी खुलता नहीं है कभी - कभी खुलता है तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता कब खुला और कब बंद हुआ है।जबकि सुबह दस खुलने का आदेश है, लेकिन पत्रकारों की टीम ने जब आयुष्मान आरोग्यउपकेंद्र की हकीकत देखी तो विकासखंड मुजेहना के ग्राम पंचायत दुल्हापुर में दस बजकर 27 मिन ट पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर ताला लटका हु आ मिला है।वही धानेपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र के गांव दुल्हापुर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित है।करीब पांच से अधिक राजस्व गांव की आबादी के लिए स्थापित यह आरोग्य मंदिर दिखा वा साबित हो रहा है।बृहस्पतिवार को को करीब दस बजकर 27 मिंनट पर आयुष्मान आरोग्य मंदि र पर टीम पहुंची तो यहां पर ताला लटक रहा था। केंद्र पर न तो सीएचओ और न ही एएनएम,आशा कोई नहीं मिला है।

घाघरा नदी पर माकड्रिल कर,सुरक्षा तैयारियों को परखा

माकड्रिल देखकर सहम गए ग्रामीण ,आपदा मोचन टीम द्वारा नदी मे डूबे व्यक्ति रेस्क्यू कर बचायी जान, तमाम अधिकारी रहे मौजूद

कैनविज टाइम्स संवाददाता

जरवल बहराइच। घाघराघाट पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव व राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से मेगा मॉक ड़िल का आयोजन कर जिला प्रशासन द्वारा अपनी तैयारियों को परखा गया, मॉक ड्रिल पटकथा के दौरान नदी मे डूबे लोगों का बचाव के लिए आपदा मोचक बल व एसएसबी के जवानों ने डूबते हुए लोगों को सुरक्षित नदी से निकाल कर, मेडिकल कैम्प मे लाया जाता है जहाँ पर मेडिकल टीम द्वारा जांच व प्राथमिक उपचार किया जाता है, माकड्रिल इतना जीवन्त था कि नदी के आस-पास मौजूद ग्रामीण इसे वास्तविक घटना समझकर रहे थे। मॉकड्रिल के दौरान पशुओं के रेस्क्यू का भी रिहर्सल किया गया। उपजिलाधिकारी कैसरगंज अखिलेश सिंह और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/कार्यक्रम पर्वेक्षक राम दयाल ने बताया कि मॉकड्रिल का उद्देश्य वास्तविक आपदा आने से पूर्व ही उन्हीं परिस्थितियों का सामना करते हुए राहत व बचाव कार्यों को सम्पन्न कराकर अपनी तैयारियों को परखना है। आपदा प्रबन्धन से जुड़े विभिन्न विभागों यथा राजस्व, नागरिक सुरक्षा, मानव एवं पशु चिकित्सा, खाद्य एवं रसद एवं शिक्षा विभाग द्वारा लगाये गये प्रदर्शनी पण्डालों का निरीक्षण कर बाढ़ के समय विभाग द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं एवं सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। घटना स्थल पर खाद्यान्न किट एवं पशुओ के लिए चारा एवं भूसा वितरण कार्य का डैमो भी प्रस्तुत किया गया।

अवैध वेंडरों पर लगाम कसने में नाकाम रेल प्रशासन, न यूनिफॉर्म, न स्वच्छ खाद्य सामग्री

अवैध वेंडर खुलेआम स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर या ट्रेनों में सामान बेचते हैवेंडर का मेडिकल कार्ड व पहचान पत्र लेकिन नहीं होता पालन

कैनविज टाइम्स संवाददाता

गोण्डा। रेलवे पर समय-समय पर स्टेशनों की जांच होती रहती है।ऐसे में गोण्डा रेलवे स्टेशन पर बिना अनुमति वेंडर सामान बेच रहे है।न ही रेल प्रशासन के अधिकारी उन्हें रोक पा रहें है और न ही ठेकेदार के प्रति कार्रवाई ही की जा रही है। ऐसे में यात्रियों को बिना जांच के खाने को परोसा जा रहा है इससे यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है।रेलवे स्टे शन पर अधिकारियों की अनदेखी के चलते ट्रेनों में अवैध वेंडर बेखौफ खाद्य सामग्री बेच रहे हैं।वहीं वैध वेंडर कई बार यूनिफॉर्म तक न हीं पहनते।जब बाहर की टीम या डीआरएम,सीनियर डीसीएम जै से अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान ही वेंडर यूनि फॉर्म,कैप व ग्लव्ज में नजर आते हैं।लेकिन इसके बाद भी स्टेशन पर अवैध वेंडरों के हौसले बुलंद हैं। खाद्य सामग्री बेचे जाने के लिए वेंडर का मेडिकल कार्ड व पहचान पत्र कार्ड भी बनाया जाता है। ले किन कई वेंडर बिना मेडिकल कार्ड के ही खाद्य सा मग्री बेच रहे हैं।

ट्रेनों में मनमाने रेट पर बेचते है सामग्री

नियमों की अनदेखी करते हुए वेंडर्स हर प्लेटफार्म में तीन से चार कर्मचारी की संख्या बढ़ाकर ट्रेनों में, प्लेटफार्म पर खाद्य सामग्री बेच रहे हैं।अवैध वेंडर रोजाना मिनरल वाटर,फल और खाद्य सामग्री की बिक्री करते हैं।इसके अलावा अवैध वेंडर बिना ला इसेंस के ट्रेनों और प्लेटफार्म पर मनमाने रेट पर सामग्री बेचते नजर आ रहे हैं।अवैध वेंडर चिप्स व बिस्किट आदि भी मनमाने दाम पर बेच रहे हैं।

कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित

कैनविज टाइम्स संवाददाता

बहराइच । बहराइच के सत्येंद्र रस्तोगी सत्या को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए बधाई दी व सम्मानित करके कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए रवाना किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चुना जाना बड़े ही सौभाग्य की बात है क्योंकि पूरे भारत से इस बार इस यात्रा पर सिर्फ कुल 750 लोंगों का ही चयन हुआ है इसमें से भी जो लोग मेडिकल टेस्ट पास कर लेते है उन्ही को आगे यात्रा की अनुमति होती है इस वजह से इसमें चयनित लोंगो पर उनके माता पिता के आशीर्वाद के साथ साथ महादेव की भी विशेष कृपा होती है । उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार यात्रा पूर्ण करने पर अपने प्रदेश की निवासी को एक लाख रुपये का अनुदान भी देगी । कैलाश मानसरोवर के यात्रियों को पहले दिल्ली जाना पड़ता था अब आप सभी की सुविधा के लिए गाजियाबाद में भव्य कैलाश मानसरोवर भवन बनकर तैयार हो गया है । सर्राफा कमेटी बहराइच शहर के अध्यक्ष सत्येंद्र रस्तोगी सत्या के कैलाश मानसरोवर यात्रा में चयनित होने पर सर्राफा कमेटी बहराइच के अध्यक्ष सुमित खन्ना, जिला महामंत्री राजेश रस्तोगी,रजनीश रस्तोगी, जिला कमेटी में प्रभारी आनंद रस्तोगी,कैलाश नाथ सोनी व वेद प्रकाश गुप्ता आदि ने खुशी जाहिर की साथ ही कहा कि यात्रा से आने पर सत्येंद्र रस्तोगी जी का भव्य स्वागत किया जाएगा इस अवसर पर मित्रजनों और परिवार में हर्ष का माहौल है।

कृषि अधिकारी ने बीज एवं खाद की दुकानों पर मारा छापा

कैनविज टाइम्स संवाददाता

उन्नाव। अजय कृष्णा संयुक्त कृषि निदेशक लखनऊ मंडल लखनऊ व शशांक जिला कृषि अधिकारी द्वारा बीज एवं खाद की दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अभिलेखों में कमी पाए जाने के कारण कुल पांच दुकानों के ऊपर कार्यवाही की गई। जिसमें मिथिलेश कुमार बीज भंडार अजगैन, राधा कृष्ण एग्री जंक्शन अजगैन, वासुदेव सीड एवं पेस्टिसाइड सोहरामऊ, शरद बीज भंडार एवं कीटनाशक केंद्र का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया ॥ तथा बुद्ध खाद भंडार जोगा सराय का लाइसेंस निरस्त किया गयाम्साथ ही जनपद के समस्त खाद एवं बीज विक्रेता के निर्देशित किया गया की अपनी दुकान पर स्टॉक रजिस्टर वितरण रजिस्टर कैश मेमो आदि रखें और संस्तुत मात्रा के हिसाब से ही ध्धप मशीन से ही उर्वरक का वितरण करना सुनिश्चित करे किसी प्रकार की अनियमित पाए जाने की स्थिति में संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएंगी

बाढ़ राहत और बचाव कार्यों के लिए मॉक ड्रिल आयोजित

कैनविज टाइम्स संवाददाता

गोण्डा। शासन के निर्देश पर जिले के तीन तहसीलों में बाढ़ पूर्व तैयारी के संबंध में मॉकड्रिल का आयो जन किया गया।जिसमें तहसील तरबगंज के अंतर्ग त बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ऐलीपरसौली के मजरा टेपरा हन पुरवा में जिलाधिकारी नेहा शर्मा की अध्यक्षता में बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल का आ योजन किया गया।इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य बाढ़ से पूर्व संभावित आपात स्थिति में प्रशासन,आपदा प्रबंधन,स्वास्थ्य,राजस्व, पुलिस,एवं अन्य विभागों की तत्परता की जानकारी ली गई।मॉकड्रिल के दौ रान जिलाधिकारी ने खुद पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यो का अवलोकन किया।उन्होंने नावों, जीवन रक्षक उपकरणों,मेडिकल टीम,पशु चिकि त्सा दल,एवं राशन वितरण,पशु चारा,दवा छिड़का व आदि व्यवस्थाओं की जानकारी ली।साथ ही, उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक संसाधन पहले से उपलब्ध रखें औ र राहत शिविरों की तैयारी पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जाए।वहीं कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी व अधिकारीगणों ने मोटर बोट के द्वारा नदियों में जा कर जल स्तर की जानकारी ली।मॉकड्रिल कार्यक्र म के दौरान स्थानीय गांव का एक व्यक्ति किसी का र्य से नदी के किनारे गया था जो पानी में डूबने ल गा,मौके पर उपस्थित एसडीआरएफ की टीम ने तु रंत डूब रहे व्यक्ति को बाहर निकाला और समय से उसको मेडिकल उपचार के लिए एम्बुलेंस के माध्य म से हास्पिटल भेज दिया।और वहां पर सही और समय से इलाज होने के कारण व्यक्ति को बचा लि या गया।जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कहा कि बाढ़ के समय लोगों को समय से सुरक्षित स्थानों पर पहुं चाना,उन्हें भोजन,चिकित्सा और आवास की सुवि धाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी विभाग आप सी समन्वय से कार्य करें ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके,मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ,पुलिस,स्वास्थ्य विभाग, पशुपाल न विभाग,जल विभाग एवं स्थानीय प्रशासन, एन सीसी के छात्र-छात्राएं एवं विभाग के अधिकारी व अन्य टीमों ने हिस्सा लिया।स्थानीय ग्रामीणों को भी मॉक ड्रिल के माध्यम से जागरूक किया गया कि आपदा के समय किस प्रकार सतर्कता बरतनी है और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करना है।जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों से बाढ़ की स्थिति में संभावित प्रभावित गांवों की सूची, रा हत सामग्री की उपलब्धता,नावों की स्थिति,और सं पर्क मार्गों की जानकारी ली।साथ ही, उन्होंने कहा कि प्रत्येक बाढ़ चौकी पर चौबीस घंटे निगरानी र खी जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पुरवा आबकारी अधिकारी की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही

कैनविज टाइम्स संवाददाता

उन्नाव। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार अवैध मदिरा की बिक्री व परिवहन की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत जिला आबकारी अधिकारी अनुराग मिश्र के कुशल नेतृत्व में निशांत सिंह आबकारी निरीक्षक पुरवा अपने हमराह व सम्बंधित गौरी, करदहा व छोटीखेड़ा थाना मौरावां में एकबारगी दबिश देते हुए कुल 42लीटर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर थाना मौरावां में आबकारी अधिनियम की सुसंगत धारा में

जिला चिकित्सालय गोरखपुर के प्रेरणा सभागार में रक्तदाता सम्मान कार्यक्रम आयोजित

पादरी बाजार ,गोरखपुर। मुख्य चिकित्साधिकारी गोरखपुर डॉ0 राजेश झा ने गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट, गोरखपुर के मुख्य ट्रस्टी दीना नाथ सिंह को अंगवस्त्र एवं सम्मान पत्र भेंट कर अखिल विश्व गायत्री परिवार गोरखपुर का सम्मान किया। इसी क्रम मुख्य ट्रस्टी दीना नाथ सिंह ने बताया कि गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट, गोरखपुर के द्वारा जन जन के हित एवं मानव प्रेम मे 2019 से अनवरत लगाये जा रहे रक्तदान शिविर एवं कोरोना जैसे विकट समय मे गायत्री परिवार ने 100 से अधिक रक्तदान कराकर मानवीय संवेदना को जागृत करने का प्रयास किया था। मुख्य ट्रस्टी दीना नाथ सिंह ने रक्तकोष विभाग का आभार करते हुए कहा कि अब आगे भी गायत्री परिवार गोरखपुर के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन नियमित रूप किया जाता रहेगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ राजेश झा के साथ डॉ प्रशान्त अस्थाना, डॉ संजय कुमार एस आई सी, डॉ बी के सुमन एम एस, डॉ प्रशांत अस्थाना ब्लड बैंक इंचार्ज, डॉ जे पी सिंह पैथोलोजिस्ट, डॉ मुकुल कुमार प्रबंधक सहित रक्तकोष विभाग की टीम उपस्थित रहे।

सिलौटा, तप्पेसिपाह व बौण्डी में सम्पन्न हुआ बाढ़ से बचाव व राहत कार्यों का मेगा मॉकड्रिल

कैनविज टाइम्स संवाददाता

बहराइच । बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव व राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित किये जाने के उद्देश्य से तहसील महसी के ग्राम बौंडी स्थित सिलौटा के रामघाट पर मुख्य राजस्व अधिकारी देवेन्द्र पाल सिंह, तहसील कैसरगंज के ग्राम तप्पेसिपाह स्थित घाघराघाट पर अति. मजिस्ट्रेट प्रथम राम दयाल तथा तहसील नानपारा के ग्राम बौण्डी में उप जिलाधिकारी मिहींपुरवा (मोतीपुर) प्रकाश सिंह के नेतृत्व में मेगा मॉक ड़िझल का आयोजन कर जिला प्रशासन द्वारा अपनी तैयारियों को परखा गया।

ग्राम सिलौटा में आयोजित मॉक ड्रिल की पटकथा के अनुसार घटना स्थल सिलौटा रामघाट पर घाघरा नदी में एक नाव पलट जाती है। नाव में सवार सभी लोग डूबने लगते हैं और खुद को बचाने के ज़ोर-ज़ोर से बचाव-बचाव की आवाज़ निकालने लगते हैं। डूबते लोगों की मदद की पुकार सुनकर पलक झपकते ही निरीक्षक दीपक मण्डल के नेतृत्व में एन.डी.आर.एफ. 11वीं बटालियन के जवान मोटरबोट पर सवार होकर नदी के बीच पहुंच गये और लाइफब्वाय को पानी में फेंककर डूबते हुए लोगों को मोटरबोट में सवार कर उन्हें सुरक्षित नदी के किनारे लेकर आये।नदी से रेस्क्यू किये गये लोगों को तत्काल स्ट्रेचर पर लेटा कर मेडिकल कैम्प में लाया गया जहां चिकित्सकों की टीम द्वारा बचाये गये लोगों की जांच व प्राथमिक उपचार कर उन्हें स्ट्रेचर के सहारे ही पास खड़ी एम्बुलेन्स पर सवार कराया। जीवनरक्षक उपकरणों से सुसज्जित एम्बुलेन्स पर मौजूद चिकित्सकों ने भी तत्काल पीड़ित व्यक्तियों को साथ लेकर चिकित्सालय की ओर रवाना हो गये। रामघाट पर मुख्य राजस्व अधिकारी/इन्सीडेन्ट कमाण्डर व प्लानिंग सेक्शन चीफ देवेन्द्र पाल सिंह के नेतृत्व में सम्पन्न माकड्रिल इतना जीवन्त था कि नदी के आस-पास मौजूद ग्रामीण इसे वास्तविक घटना समझ रहे थे। परन्तु जब उन्हें पता चला कि यह मात्र राहत व बचाव कार्य का पूर्वाभ्यास था तो चेहरे पर दिखने वाला तनाव खत्म हुआ।

मॉकड्रिल के दौरान पशुओं के रेस्क्यू का भी रिहर्सल किया गया।मॉकड्रिल स्थल पर मुख्य राजस्व अधिकारी श्री सिंह ने कहा कि मॉकड्रिल का उद्देश्य यह है कि हम वास्तविक आपदा आने से पूर्व ही उन्हीं परिस्थितियों का सामना करते हुए राहत व बचाव कार्यों को सम्पन्न कराकर अपनी तैयारियों को परख लें। उन्होंने कहा कि सभी विभागों द्वारा मॉक ड्रिल के लिए बेहतर तैयारी की गयी है। उन्हें विश्वास है कि यदि वास्तविक आपदा जैसी कोई परिस्थितियॉ उत्पन्न होती हैं तो सभी विभाग बेहतर कार्य कर सकेंगे। श्री सिंह ने मॉकड्रिल में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों, एनसीसी, पीआरडी, एनएसएस, आपदा मित्र, मेरा जुड़ा भारत, आपदा ट्रेनर्स, सुरक्षा एजेन्सियों के जवानों तथा मॉकड्रिल में सभी प्रतिभागी सहयोगियों का आभार ज्ञापित करते हुए ग्रामवासियों से अपील की कि मॉकड्रिल के दौरान बतायी गई बातों को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि आपदा के दौरान जानी व माली नुकसान को न्यून से न्यूनतम किया जा सके।मॉकड्रिल के उपरान्त मौके पर मौजूद सभी अधिकारियों ने अन्य सम्बन्धित के साथ स्टेजिंग एरिया कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय बौण्डी में आपदा प्रबन्धन से जुड़े विभिन्न विभागों यथा राजस्व, नागरिक सुरक्षा, मानव एवं पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य, खाद्य एवं रसद एवं शिक्षा विभाग द्वारा लगाये गये प्रदर्शनी पण्डालों का निरीक्षण कर बाढ़ के समय विभाग द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं एवं सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। घटना स्थल पर खाद्यान्न किट एवं पशुओ के लिए चारा एवं भूसा वितरण कार्य का डैमो भी प्रस्तुत किया गया। इसके उपरान्त उप जिलाधिकारी महसी अश्वनी पाण्डेय, पुलिस क्षेत्राधिकारी डी.के. श्रीवास्तव व अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद थे।

कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग आज से शुरू

पीलीभीत। किसान भाईयों को सूचित किया जाता है। कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू एवं अन्य योजना के हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, कस्टम हायरिंग सेंटर, फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना, कृषि ड्रोन, फसल अवशेष प्रबन्धन के प्रमुख कृषि यंत्र एवं अन्य कृषि यंत्र/कृषि रक्षा उपकरण इत्यादि पर अनुदान प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। प्रमुख कृषि यंत्र हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, कस्टम हायरिंग सेंटर, फार्म मशीनरी बैंक, किसान ड्रोन, कम्बाइन हार्वेस्टर विद सुपर एस0एम0एस0, न्युमेटिक प्लांटर, मेज सेलर, पॉपिंग मशीन, बैच ड्रायर, थ्रेसिंग फ्लोर, स्मॉल गोदाम, ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट/मिनी ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट, शुगर केन सेटलिग प्लांटर, शुगर केन पॉवर वीडर/इंटर से कम इंट्रा से वीडर (पी0टी0ओ0 ऑपरेटिड) एवं अन्य समस्त कृषि यंत्रो के आवेदन हेतु बुकिंग दिनॉक 27.06.2025 को दोपहर 12:00 बजे से दिनॉक 12.07.2025 रात्रि 12:00 बजे तक की जायेगी।

सम्मानित हुए पूर्व मंत्री

जाति धर्म के समर्थकों की दुआओं की बदौलत स्वस्थ होकर लौटा हूं : पूर्व मंत्री डॉ विनोद तिवारी

कैनविज टाइम्स संवाददाता

पूरनपुर। विधान सभा क्षेत्र ही नहीं समूचे जनपद में पूर्व मंत्री डाक्टर विनोद तिवारी सबसे अधिक ईमानदार नेता हैं और उन्होंने हमेशा सिद्धांतों की राजनीति की है। उनके भाषण पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी जैसे हैं। अपनों को पहचानने व उनका साथ देने की डाक्टर तिवारी की आदत उन्हें अन्य नेताओं से अलग करती है। दलाली, भ्रष्टाचार से दूर रहकर अफसरों को काम करने के लिए विवश करने वाले विनोद तिवारी पहले नेता हैं। अगर उन्होंने जिद कर ली तो हर काम आसान हो जाता है। पूरनपुर और पीलीभीत ही नहीं लखनऊ और दिल्ली में अपने संबंधों के जरिए डाक्टर तिवारी आज भी लोगों के काम करा रहे हैं क्योंकि देश भर में उन्होंने अपनी अलग छवि बनाई है। उनके जैसा जनप्रतिनिधि न तो जिले में हुआ और न होगा।उपरोक्त वाक्य उन विचारों के अंश हैं जो बुधवार शाम को नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता द्वारा पालिका सभागार में आयोजित डाक्टर विनोद तिवारी की शान में मौजूद लोगों ने प्रस्तुत किए। आज के नेताओ से उनकी तुलना करते हुए उन्हें महान नेता बताया गया। पूर्व मंत्री ने कहा कि उन्हें आज अपनों के बीच आकर ऊर्जा मिली है और काफी अच्छा लग रहा है। उन्होंने स्वस्थ होने में लोगों की दुआओं का योगदान बताया।

लम्बी बीमारी के इलाज उपरांत पुनः अपने क्षेत्र अपने घर पधारे कुशल राजनीतिज्ञ, वक्ता एवं व्यवहार कुशल पूर्व राज्यमंत्री डॉ.विनोद तिवारी का नगरपालिका सभागार में चेयरमैन शैलेंद्र गुप्ता, समाजसेवी संदीप खंडेलवाल व अन्य लोगों ने उनका स्वागत एवं सम्मान किया। साथ ही उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। डाक्टर तिवारी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ-साथ, ईश्वर से उनके दीर्घायु होने की कामना की गई।

इन वक्ताओं ने रखे विचार

समाजसेवी अशोक खंडेलवाल, संदीप खंडेलवाल, गन्ना समिति चेयरमैन नितिन दीक्षित, भाजपा नेता रजनीश पांडेय, हर्ष गुप्ता, डाक्टर दिनेश गुप्ता, राकेश गुप्ता, पूर्व वनाधिकारी राजाराम शर्मा, कवि पंडित राम अवतार शर्मा, निरंकार पांडे, पत्रकार नवीन अग्रवाल, सतीश मिश्र, सभासद अनुज गुप्ता, तौफीक अहमद कादरी, पूर्व सभासद भूरे भाई, अमन नागी, अर्पण तिवारी, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष संजय सक्सेना, हरीराम गौतम एडवोकेट, नितिन वर्मा सहित तमाम वक्ताओं ने विचार रखे। संचालन अनिल शुक्ला व आभार ज्ञापन राम बहादुर गुप्ता ने किया। पूर्व मंत्री डाक्टर विनोद तिवारी 26, 27 व 28 जून को अपने घर कुरैया रहेंगे और उसके बाद लखनऊ इलाज हेतु चले जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोग तीनों दिन सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक मिल सकते हैं।

माधोटांडा रेलवे क्रासिंग के पास नशे की हालत में मिला बालक

पूरनपुर, कैनविज टाइम्स संवाददाता। नई नीतियों के साथ खोली गई शराब की दुकानों को लेकर कई जगह महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया था और मामले में उच्च अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से भी शिकायत की थी। लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। अब इसके परिणाम सामने आने लगे हैं। माधोटांडा रेलवे क्रासिंग के पास एक आठ वर्षीय बालक को नशे की हालत में देखा गया। राहगीरों ने मामले की सूचना 108 एबुलेंस को दी और बालक को अस्पताल भिजवाया गया। अस्पताल में बालक का उपचार किया गया। इस घटना ने एक बार फिर से शराब की दुकानों के विरोध को हवा दे दी है। लोगों का कहना है कि शराब की दुकानें खोलने से क्षेत्र में अपराध और नशे की समस्या बढ़ रही है। प्रशासन को इस मामले में ध्यान देना चाहिए और आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि चंद रुपए की लालच में बच्चों का जीवन बर्वाद किया जा रहा है।

अवैध रूप से चल रहा मछलियों का शिकार, वीडियो वायरल

पूरनपुर, कैनविज टाइम्स संवाददाता। घुघंचाई थाना क्षेत्र के जमुनिया झाल हरदोई ब्रांच नहर में अवैध रूप से मछलियों का शिकार किया जा रहा है। जबकि हरदोई ब्रांच नहर में मछलियों के शिकार पर पाबंदी है। उसके बाद भी शिकारी मछलियों का शिकार बेधड़क होकर कर रहे हैं। जिसका वीडियो गुरुवार सुबह 11 बजे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्षेत्र में चर्चा है कि सिंचाई विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के चलते मछलियों का शिकार किया जा रहा है।

शेरपुर कला निवासी युवक निकला कोरोना पॉजिटिव स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

पूरनपुर, कैनविज टाइम्स संवाददाता। तहसील क्षेत्र के गांव शेरपुर कला निवासी एक युवक का दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है। युवक को पैरालिसिस होने पर उपचार के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने उसकी जाँचें कराईं, जिनमें कोरोना की जाँच भी शामिल थी। जांच में युवक कोरोना पॉजिटिव निकला। इस खबर से परिजनों में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग को सूचित कर दिया गया है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। युवक के संपर्क में आए लोगों की जाँच भी कराई जाएगी और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा।

सांप के डंस ने से ग्रामीण की बिगड़ी हालत

पूरनपुर, कैनविज टाइम्स संवाददाता। तहसील क्षेत्र के गांव शेरपुर कला इस्लाम नगर निवासी फिरासत पुत्र रियासत गुरुवार दोपहर लगभग 1:30 पर मवेशियों के लिए घास काटने गए थे। बताया जा रहा है की घास काटने के दौरान उनको सांप ने डंस लिया। घर पहुंच कर घटना की जानकारी उन्होंने परिजनों को दी यह सुनकर परिजनों के भी होश उड़ गए और हालात बिगड़ने पर परिजनों ने उपचार के लिए पूरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां डॉक्टर ने उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

दरोगा-सिपाही निलंबित, हेड मोहर्रिर लाइन हाजिर

सुल्तानपुर, कैनविज टाइम्स संवाददाता। नगर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस कस्टडी से बाइक गायब होने का मामला लगातार गरमाता जा रहा है। अमहट चौकी क्षेत्र में एक युवक की सड़क हादसे में मौत के बाद मृतक की बाइक रहस्यमय ढंग से थाने से गायब हो गई।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अमहट चौकी से एक उपनिरीक्षक व सिपाही अभिषेक मिश्रा को हटाते हुए रजत पांडे को नया चौकी प्रभारी नियुक्त किया है। साथ ही नगर कोतवाली के हेड मोहर्रिर संजय सोनकर को लाइन हाजिर कर दिया गया है।जानकारी के मुताबिक,10 जून को आयान हॉस्पिटल अमहट चौराहे के पास रोडवेज बस की टक्कर से हरखी दौलतपुर,बंधुआकलां निवासी धर्मेन्द्र कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने मौके से बस और बाइक (ठग्36 द्व 8492) को कब्जे में लेकर थाने भेजा था। लेकिन जब मृतक का भाई मनोज बाइक लेने पहुंचा तो उसे टरकाया गया। बाद में जब थाने में सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो पाया गया कि एक सिपाही बाइक को थाने के भीतर लाता दिखा और 12 जून को एक होमगार्ड बाइक को थाने से बाहर ले जाता नजर आया।पीड़ित मनोज गौतम की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने दरोगा और सिपाही को 25 जून को सस्पेंड कर दिया। कोतवाल नगर धीरज कुमार के अनुसार,पीड़ित की तहरीर पर अब बाइक चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर संजय सोनकर को लाइन हाजिर किया गया है।

शुकुल बाजार पुलिस ने स्मैक के साथ युवक को पकड़ा

शुकुल बाजार अमेठी, कैनविज टाइम्स संवाददाता। थाना बाजार शुकुल पुलिस ने नशा मुक्त अमेठी अभियान के तहत पैंसठ ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देश पर थाना बाजार शुकुल पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान सूर्यभान पुत्र प्रयागनारायण निवासी भटमऊ थाना बाजार शुकुल जनपद अमेठी को गिरफ्तार किया गया जिसकी तलाशी में पुलिस टीम को उसके कब्जे से पैंसठ ग्राम स्मैक बरामद हुई है।इस सम्बंध में थानाध्यक्ष अभिनेष कुमार ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा पकड़े गये युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्जकर जेल भेज दिया गया है।

बीएसए के खिलाफ शुरु हुई साजिश

सुलतानपुर। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र गुप्ता को बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ साजिश शुरु हो गई है। बीएसए के नाम पर पैसा मांगने का आडियो वायरल कर उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। बीएसए ने इस मामले में सीधे तौर पर साजिश करने वाले मई महीने में निलंबित किए गए शिक्षकों के नाम का हवाला देते हुए उनकी साजिश का नाकाम करते हुए कहाकि इन शिक्षकों के खिलाफ कोई और कार्रवाई उनकी ओर से न की जाए, इसलिए आड़ियो जारी कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। उन्होंने अपना सीयूजी नम्बर जारी करते हुए कहाकि अगर उनके नाम से कोई पैसा मांगता है तो तत्काल उन्हें सूचना दें।

बीएसए के नाम पर वसूली करने का आडियो निलंबित शिक्षकों ने बनाकर सोशल मीडिया को हथियार बनाया है। ताकि उनके खिलाफ चल रही जांच को रोक दी जाए। और बड़ी कार्रवाई न की जाए। बीएसए ने कहाकि उनके नाम से वसूली करने का आडियो जारी करने वाले निलंबित शिक्षकों को किसी भी कीमत पर बख्या नहीं जाएगा। उनकी यह हरकत शिक्षक नियमावली के विपरीत है। निलंबित शिक्षक रविकुमार सिंह और शरीफ सोशल मीडिया पर एक ऑडियो प्रसारित किया। निलंबित प्रधानाध्यापक रामलोचन ने भी उनके साथ शामिल रहे। बीएसए उपेन्द्र गुप्ता ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय कोंची विकास क्षेत्र जयसिंहपुर के प्रधानाध्यापक रामलोचन की ओर से सरकारी धन का दुरुपयोग करने की प्राप्त शिकायत पर उन्होंने नौ मई 2025 को इनके विद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय आरोपों की प्रथम दृष्टया पुष्टि होने पर प्रधानाध्यापक रामलोचन को उसी दिन निलम्बित किया गया।

दो शिक्षकों वसूली करने का का जारी किया आडियो तो हुए निलंबित

उसके बाद तीन शिक्षकों की ओर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुलतानपुर के नाम पर अनरगल वार्ता करने का आडियों 21 मई को उनके संज्ञान में आने पर 21 मई को शिक्षक रवि कुमार सिंह एवं शरीफ आलम को भी तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया। साथ ही तीनो शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक सम्पन्न

कैनविज टाइम्स संवाददाता

पीलीभीत। जिलाधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की बैठक कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में परियोजना अधिकारी नेडा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2025-26 तक कुल 1764 घरों पर सोलर रूफटॉप पावर प्लाण्ट लगाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष 1141 घरों पर सोलर रूफटॉप पावर प्लांट स्थापित किया जा चुका है तथा भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अबतक 915 उपभोक्ताओं को अनुदान अवमुक्त किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने वेण्डर्स की समस्याऐं सुनी, जिसमें मुख्य रूप से वेण्डर्स द्वारा बैंक लोनिंग में आ रही समस्याओं से संज्ञानित कराया गया, बैंक द्वारा लोनिंग में पर्याप्त सहयोग नहीं किया जा रहा है। जिसमें मुख्य रूप से पंजाब सिंघु बैंक कलीनगर एवं शाहगढ़, यूनियन बैंक पूरनपुर, इण्डियन बैंक पीलीभीत एवं बीसलपुर, बैंक ऑफ बडौदा बीसलपुर द्वारा सहयोग न करने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित लीड बैंक मैनेजर को निर्देशित किया कि समस्त बैंकों को योजनान्तर्गत ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित करें एवं समय सीमा निर्धारित करें उन्होंने कहा कि यदि किसी बैंक द्वारा इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में असहयोग करना संज्ञान में आता है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जहॉ धन की बचत होती है वहीं यह पर्यावरण हितैषी भी है। जनपद में प्रत्येक घर को इस योजना से लाभान्वित किया जाये। बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियन्ता विद्युत द्वारा योजना के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय को विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक के अन्त में परियोजना अधिकारी नेडा ने सभी आभार व्यक्त करते हुये बैठक समाप्त हुई।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, नगर मजिस्टेझ्रट, अधिशासी अभियन्ता विद्युत नोडल, अग्रणी बैंक प्रबन्धक, परियोजना अधिकारी नेडा सहित अन्य अधिकारियों के साथ यूपीनेड़ा के इम्पैनेल्डवेण्डर्स उपस्थित रहे।

एसओ से लेकर एसडीएम तक क्षेत्र के धर्मगुरुओं और प्रतिष्ठितजनों के साथ संवाद बनाएं : जिलाधिकारी

कैनविज टाइम्स संवाददाता

अमेठी। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संजय चौहान एवं पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने संयुक्त रूप से आगामी त्यौहारों मुहर्रम, श्रावणमास, कांवड़ यात्रा, नागपंचमी एवं रक्षाबंधन को स्वच्छ वातावरण एवं शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिये अधिकारियों, विभिन्न सम्प्रदाय के धर्मगुरुओं एवं जनपद के प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ संयुक्त पीस कमेटी की बैठक किया। बैठक में धर्मगुरुओं से आपस में मिलजुलकर शांति व सौहार्दपूर्ण त्यौहार मनाने, अफवाहों व झूठी खबरों पर ध्यान न देने तथा अफवाहों को फैलने से रोकने हेतु अपील की गई। बैठक में जिलाधिकारी संजय चौहान ने कहा कि आगामी त्यौहारों को लेकर सभी अधिकारी अलर्ट मोड़ पर रहे, अपने अपने क्षेत्र के धर्मगुरुओं से सतत संवाद बनाए रखें, मंदिरों व मस्जिदों का निरीक्षण कर वहां पर साफ सफाई, बिजली, पानी इत्यादि की व्यवस्था पूर्व से ही सुनिश्चित करा लें साथ ही आने जाने वाले मार्ग को भी दुरुस्त करा लें।उन्होंने डीपीआरओ को निर्देशित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं एवं सार्वजनिक जगहों एवं मंदिरों, मस्जिदों, ईदगाह के पास साफ सफाई रहे। लोक निर्माण विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा वाले रूट पर सड़कों को गड्ढा मुक्त कराया जाय। जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम व सीओ को निर्देशित करते हुये कहा कि अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहे। उन्होंने कहा कि कोई भी नई परंपरा त्यौहार में ना डाली जाय एवं कांवड़ यात्रा व ताजिया को लेकर अपनी तैयारी पूर्ण कर लें तथा जिन रूटों से पूर्व में कांवड़ यात्रा व ताजिया निकलती रही है उन रूटों से ही कावड़ यात्रा व ताजिया निकले अनावश्यक रूप से कोई नई परंपरा ना डालें इसको प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करें। उन्होंने विद्युत विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि विद्युत विभाग त्यौहारों पर पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुचारू रखें एवं जर्जर तार, लटकते तार एवं खंभों पर करंट न उतरे यह भी देख लिया जाए एवं नगर पालिका पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था रखें। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित करते हुये कहा कि अपने अपने क्षेत्र में आगामी त्यौहारों को लेकर भ्रमणशील रहें और उन्होंने कहा कि आगामी त्यौहारों को लेकर अपनी तैयारी पूर्ण कर लें एवं किसी भी दशा में त्यौहारों में नई परंपरा ना डालने दें। उन्होंने कहा कि ज्यादा भीड़भाड़ वाले स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत सीसीटीवी कैमरा लगाये जाय।पुलिस प्रशासन अपने अलर्ट मोड़ पर रहे। आगामी त्यौहारों को लेकर अपनी निगरानी बनाये रखें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर सतर्क दृष्टि बनाये रखें तथा अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें। बैठक के दौरान जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने समस्त जनपद वासियों को आगामी त्योहारों की बधाई देते हुए त्योहारों को स्वच्छ वातावरण एवं शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की है।

ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक पोस्ट पर कार्यवाही को लेकर सौंपा ज्ञापन

कैनविज टाइम्स संवाददाता

सुल्तानपुर। कटका क्लब ने सोशल मीडिया पर निरंतर उत्तर प्रदेश में चल रही ब्राह्मण समाज के ऊपर आपत्तिजनक शब्दों के खिलाफ मुख्यमंत्री के नाम सिटी मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार को ज्ञापन सौंपा कर कार्यवाही कि मांग की। इस मौके पर संस्था अध्यक्ष सौरभ मिश्र विनम्र ने बताया कि जनपद इटावा के अंदर में बीते दिनों श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक के साथ हुई अभद्रता के लिए हम सभी और हम अमाजनमानस विरोध कर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर बीते दिनों से ब्राह्मण समाज के ऊपर आपत्तिजनक शब्दों का प्रोग्राम किया जा रहा है। जिसका संस्था विरोध करती हैं और कड़ी कार्यवाही कि मांग करती हैं। इस मौके पर एडवोकेट वेदांग त्रिपाठी ने बताया कि ब्राह्मण समाज के बीच अपनी जाति छुपाकर जाना, वहां के महिलाओं के साथ अभद्रता करना जो बेहद दुख है लेकिन सुल्तानपुर में ही नहीं उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। जिससे ब्राह्मण समाज में काफी रोष है। इसी संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। इस मौके पर एडवोकेट विमल कुमार दुबे, आई. टी. सेल प्रभारी बृजेन्द्र मिश्र, विनय त्रिपाठी, प्रज्वल मिश्र, रितिक द्विवेदी आदि लोग उपस्थित रहे।

व्यापारियों ने थामा लघु उद्योग व्यापार मंडल का दामन

कैनविज टाइम्स संवाददाता

सुलतानपुर। शहर के नामी-गिरामी हस्तियों ने नीति आयोग भारत सरकार द्वारा पंजीकृत संस्था आरपीएस-एमएएफ से सम्बद्ध उसकी एक ईकाई लघु उद्योग व्यापार मंडल के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर की जिसके उपरांत राष्ट्रीय अध्यक्ष डी पी गुप्ता ने संगठन का विस्तार करते हुए राजेश कुमार सोनी को मंडल संयोजक अयोध्या मंडल व गजानंद मोदनवाल को सुल्तानपुर जिला संयोजक मनोनीत किया। इसी के साथ शहर के प्रसिद्ध समाजसेवी व्यापारी सरदार गगनदीप सिंह को जिला सचिव का दायित्व सौंपा। सभी नवमनोनीत पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे सब लघु उद्योग व्यापार मंडल में शामिल होकर उत्साहित हैं । संगठन ने उनको जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, उसे वे भलीभांति निभाते हुए लघु उद्योग व्यापार मंडल का पूरे जिले में विस्तार करेंगे।

इस अवसर पर नीलिमा सेठ, सर्वेशा सांई राज, अरविन्द चौरसिया, रमेश कुमार मोदनवाल, सुरेश कुमार सोनी, प्रदीप मिश्रा, राजदेव यादव, अंजनी जायसवाल, शिवशंकर चौधरी, संगमलाल मोदनवाल, सरदार जसविंदर सिंह, जीत बहादुर मोदनवाल, ओमप्रकाश गुप्ता, आशीष बरनवाल एडवोकेट, डी डी निषाद एडवोकेट, दीपक आर्य, अंकित कसौंधन, विशाल अग्रहरी, शोभित मोदनवाल, रामप्रसाद अतुल, विकास मोदनवाल, शिवम राज आदि ने हर्ष व्यक्त किया।

प्रतिबंधित पेड़ों की अवैध कटान धड़ल्ले से जारी

कैनविज टाइम्स संवाददाता

तिलोई अमेठी। प्रदेश सरकार के वृक्षारोपण अभियान कीसरकारी नुमाइंदों द्वारा कैसे धज्जियां उड़ाई जाती है अगर इसकी जमीनी हकीकत जांचनी और परखनी हो तो वन रेंज तिलोई के थाना इन्हौना क्षेत्र में आइये। यहां पर बेखौफ लकड़ी कारोबारियों द्वारा स्थानीय पुलिस और वन कर्मियों की सांठगांठ से दिनदहाड़े प्रतिबंधित पेड़ों पर आरा चलाकर हरियाली का कत्ल डंके की चोट पर किया जा रहा है और कागज के चंद टुकड़ों के चक्कर में पुलिस के साथ ही वनकर्मी मूकदर्शक बने रहते हैं। थाना इन्हौना क्षेत्र में इन दिनों लकड़ी कारोबारियों की बल्ले बल्ले हैं और नियमित प्रतिबंधित पेड़ों की अवैध कटान का मामला सामने आता है लेकिन स्थानीय पुलिस और वनकर्मी मूकदर्शक बनकर अवैध कटान को डकार जाते हैं। थाना क्षेत्र के गांव राजापुर, आजादपुर, कोटवा और गोपालपुर के बाद बुधवार की रात्रि में गांव जमलापुर मजरे आजादपुर में बेखौफ

पुलिस और वन विभाग की सांठगांठ से दिनदहाड़े चल रहा लकड़ी कारोबारियों का हरियाली पर आरा

लकड़ी कारोबारियों द्वारा पुलिस और वन विभाग से साठगांठ कर फ़लदार प्रतिबंध वृक्ष का कत्ल करते हुये आम के एक विशाल पेड़ को आरा चलाते हुये धराशाही कर दिया गया और सुबह होते ही ट्रैक्टर ट्राली से लकड़ी को भी ठिकाने लगा दिया गया है। बताया जा रहा है इस अवैध कटान में पुलिस और वन विभाग का अहम योगदान रहता है जो पेड़ काटने से लेकर लकड़ी उठान तक की व्यवस्था पर अपनी नजर गड़ाये रखते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा जब अवैध कटान की शिकायत पुलिस और वन विभाग से की जाती है तो वह लकड़ी कारोबारियों के ही मददगार बन जाते हैं। पुलिस की करतूतों से इस कारोबार में लिप्त लोगों के हौसले बुलंद हैं। सूबे के मुख्यमंत्री से लेकर अन्य

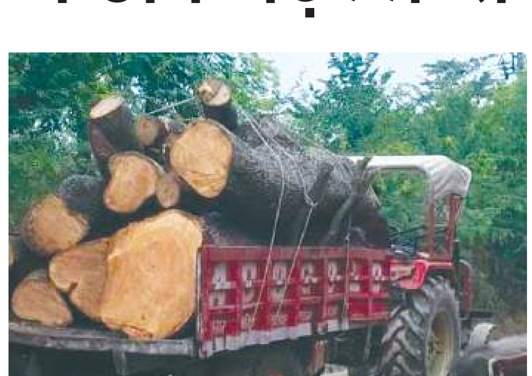

जनप्रतिनिधियों के साथ ही जिलाधिकारी द्वारा वृक्षारोपण का पाठ पढ़ाया जाता है और आम जनमानस को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिये प्रेरित किया जाता है लेकिन वन रेंज तिलोई के वनक्षेत्राधिकारी और थाना इन्हौना के थानाध्यक्ष अपने इलाके में हरियाली का कत्ल कराने में एक अच्छी ख्याति हासिल कर चुके हैं जिससे सरकार के मंसूबों पर काली छाया के बादल मंडरा रहे हैं और सरकारी नुमाइंदे इसी अवैध कटान के चक्कर में मलाई काट रहे हैं। सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि इन्हौना क्षेत्र में प्रतिबंधित पेड़ों की अवैध कटान का मामला तहसील से लेकर जिला तक के अधिकारियों के भी संज्ञान में जाता है फिर वह मौनधारण किये हुये है। एक लकड़ी कारोबारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कटान प्रारम्भ होने से पूर्व ही पुलिस और वन विभाग के पास एक निर्धारित रकम जमा कर दी जाती है जो कि कटान से लेकर उठान तक हम सबका सहयोग करते हैं।क्षेत्रीय नागरिकों ने वन रेंज तिलोई क्षेत्र में अवैध कटान पर अंकुश लगाने के साथ ही संलिप्त कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही किये जाने की मांग जिलाधिकारी से की है।

सरकारी राशन में मिट्टी और नमक की मिलावट पर डीएम ने की छापेमारी

कैनविज टाइम्स संवाददाता

अमेठी। जिलाधिकारी संजय चौहान ने सरकारी खाद्यान्न में मिट्टी और नमक मिलने की शिकायत पर आज विकास खण्ड जगदीशपुर की ग्राम पंचायत जलालपुर तिवारी में अन्नपूर्णा भवन सरकारी सस्ते राशन की दुकान पर जाकर खाद्यान्न और उनके बोरे की जांच की।निरीक्षण के दौरान प्रथम दृष्टया खाद्यान्न में नमक व मिट्टी के ढेले की मिलावट पाई गई जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी और जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी को मिलावटी खाद्यान्न बदलवाकर उसके स्थान पर स्वच्छ खाद्यान्न देने के निर्देश दिये साथ ही इस प्रकरण की अग्रेतर जांच गहनता से कराने हेतु अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में जिला पूर्ति अधिकारी, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी एवं संबंधित उपजिलाधिकारी की संयुक्त टीम बनाकर वृहद जांच के निर्देश दिये साथ ही प्राथमिक जांच में पाये गये तथ्यों के आधार पर गड़बड़ी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराकर कठोरतम कार्यवाही करने का निर्देश दिया।इससे पूर्व ग्राम दरपीपुर में सरकारी राशन की दुकान में खाद्यान्न में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई थी तथा आज जलालपुर तिवारी में खाद्यान्न में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के उपरांत जिलाधिकारी द्वारा मौके पर जाकर खाद्यान्न का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने जिला खाद एवं विपणन अधिकारी से राशन की आपूर्ति के संबंध में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जिन बोरियों में इस तरह का खाद्यान्न निकले उसे तत्काल बदला जाए। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया कि इस तरह की शिकायत कहीं से भी आए तो तत्काल वहां पहुंचकर उन खाद्यान्न की बोरियों को बदलकर उसके स्थान पर दूसरी स्वच्छ बोरियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित ग्रामीणों से इससे पहले इस तरह के खाद्यान्न मिलने की जानकारी ली जिस पर ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि इससे पहले कभी भी खाद्यान्न में इस तरह की शिकायत नहीं आई है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी एवं जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी को निर्देश दिये कि जहां जहां इस प्रकार की शिकायतें आई हैं वहां की जांच कर शाम तक रिपोर्ट उपलब्ध कराएं, उन्होंने कहा कि इस कार्य में लिप्त लोगों को बख्शा नहीं जायेगा दोषी पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

बेटियां संवेदनशील

देशकाल-परिस्थितियों और बदलती जरूरतों के अनुरूप वैश्विक स्तर पर एक सूक्ष्म, लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव दृष्टिगोचर हो रहा है। यह बदलाव लिंग प्राथमिकताओं को लेकर वैश्विक दृष्टिकोण में आ रहे परिवर्तन का है। जैसा कि हाल ही में 'द इकनॉमिस्ट' द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि लड़कों के प्रति सदियों पुराना झुकाव अब कम हो रहा है। दुनियाभर में, अतिरिक्त पुरुष जन्म की संख्या-जो वर्ष 2000 में 1.7 मिलियन तक अधिक थी, साल 2025 तक लगभग दो लाख तक गिर गई है। निस्संदेह, यह प्रजनन विकल्पों में एक अप्रत्याशित बदलावों का संकेत है। यहां तक कि दक्षिण कोरिया और चीन में, लिंग अनुपात सामान्य या यहां तक कि बेटी की पसंद के संकेत दिखाने लगा है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस बदलाव की असल वजह क्या है३ दरअसल, माता-पिता में यह धारणा बलवती होती जा रही है कि बेटियां उनकी ढलती उम्र में धीरे-धीरे अधिक विश्वसनीय देखभाल करने वाली साबित हो सकती हैं। उन्हें परिवार से गहरे तक जुड़े रहने की अधिक संभावना के रूप में देखा जाने लगा है। आज बेटियों को बेटों के मुकाबले बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शनकर्ता के रूप में देखा जा सकता है। तेजी से कामकाजी दुनिया का हिस्सा बनने के कारण वह आर्थिक रूप से स्वावलंबी होती जा रही है। बल्कि कई देशों में तो महिलाओं की बैचलर डिग्री की संख्या तक पुरुषों की तुलना में अधिक है। पश्चिमी देशों में गोद लेने और आईवीएफ के डेटा दिखाते हैं कि बेटियों को चुनने की दिशा में स्पष्ट झुकाव है। दरअसल, पश्चिमी देशों के एकल परिवारों में बेटे अपनी गृहस्थी बसाकर मां-बाप को उनके भाग्य पर छोड़ जाते हैं। ऐसा माना जाने लगा है कि बेटियां बेटों के मुकाबले में ज्यादा संवेदनशील होती हैं और जीवन के अंतिम पड़ाव में मां-बाप को सुरक्षा कवच प्रदान कर सकती हैं। जिसके चलते लोग बेटों के मुकाबले बेटियों को अपनी प्राथमिकता बनाने को तरजीह देने लगे हैं। वहीं भारत में परिस्थितियां एक जटिल तसवीर प्रस्तुत करती हैं। यूं तो सदियों से भारत का समाज पुत्र मोह की ग्रंथि से ग्रस्त रहा है। हालांकि, अब आधिकारिक आंकड़े बता रहे हैं कि देश में शिशु लिंग अनुपात दर में सुधार हुआ है। लेकिन लिंग चयन के लिये किए जाने वाले गर्भपात पर शासन व प्रशासन की कानूनी सख्ती और जागरूकता अभियानों के बावजूद परंपरागत रूप से समाज में गहरी जड़ें जमाने वाला बेटा मोह अब भी प्राथमिकता बना हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5(2019-21) का सर्वे चिंता बढ़ाने वाला है। सर्वे के अनुसार, लगभग 15 फीसदी भारतीय माता-पिता अभी भी बेटियों की तुलना में बेटों की आकांक्षा रखते हैं। यही वजह है कि हरियाणा,पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विषम शिशु लिंगानुपात चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अलावा, भारत में बेटी वरीयता, जहां यह मौजूद है, अक्सर सशर्त होती है। लड़कियों को भावनात्मक लगाव या घरेलू स्थिरता के लिये तो महत्व दिया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि पोषण, शिक्षा या विरासत तक उन्हें समान पहुंच दी जाए। भारतीय समाज में दहेज जैसी सांस्कृतिक प्रथाएं आज भी बेटी के माता-पिता की बड़ी चिंता बनी रहती हैं। परंपरावादी समाज में यह धारणा बलवती रही है कि बेटियां दूसरे परिवार की हैं। यही वजह है कि ग्रामीण और शहरी गरीब समुदायों में लड़कियां हाशिये पर रख जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत को लिंग समानता के वैश्विक आंदोलन की किसी भी तरह अनदेखी नहीं करनी चाहिए। साथ ही केंद्र व राज्य सरकारों के नीतिगत हस्तक्षेप को जन्म सांख्यिकी से परे जाना चाहिए। नीति-नियंताओं को बालिका शिक्षा को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ ही समान संपत्ति अधिकार लागू करने, दहेज प्रथा की कुरीति को समाप्त करने की दिशा में सख्त कदम उठाने चाहिए। तभी भारतीय समाज में लिंगभेद की मानसिकता खत्म होगी और लैंगिक समानता की दिशा में मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही देश में तेजी से बढ़ती बुजुर्गों की आबादी के लिये सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए।

प्रकृति एवं जीवन रक्षा के लिये नदियों का संरक्षण जरूरी

भारत नदियों का एक अनोखा देश है जहां नदियों को पूजनीय माना जाता है। गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु (सिंधु), और कावेरी जैसी नदियों को देवी-देवताओं के रूप में पूजा जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासन में बनाया गया जल शक्ति मंत्रालय, नदी घाटियों में आर्द्रभूमि के पुनरुद्धार और संरक्षण और नदी प्रदूषण के खतरनाक स्तर से निपटने पर ध्यान केंद्रित करता है। देश के समक्ष वाटर विजन 2047 प्रस्तुत किया गया है यानी आजादी के सौ वर्ष पूरे होने तक देश को प्रत्येक वह कार्य करना है, जो देश को पानी के मामलों में सबल बना सके। इसमें हमारी नदियां भी शामिल हैं। हमें अपनी नदियों को 2047 तक निर्मल व अविरल बनाने के संकल्पित लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना होगा। भारत की नदियों की दिन-ब-दिन बिगड़ती हालत एवं बढ़ते प्रदूषण पर पिछले चार दशकों से लगभग हर सरकार कोरी राजनीति कर रही है, प्रदूषणमुक्त नदियों का कोई ईमानदार प्रयास होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। नदियां हमारे जीवन की जीवन रेखा है, गति है, ताकत है। ये पानी, बिजली, परिवहन, मछली और मनोरंजन के लिए स्रोत हैं। नदियां पर्यावरण के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। नदियों के किनारे बसे शहरों की वजह से ये आर्थिक रूप से भी अहम हैं, इनसे ताज़ा पीने का पानी मिलता है, बिजली बनती है, खेती के लिए ज़रूरी उपजाऊ मिट्टी मिलती है। नदियों से जल परिवहन होता है। नदियां मरेंगी तो समाज मर जाएगा।

भारत में कई नदियां सूखने या प्रदूषित होने के कारण मरने के कगार पर हैं। इन नदियों की हालत इतनी खराब हो गई है कि कुछ तो नालों में बदल गई हैं और उनका नदी होना भी मुश्किल है। नदियों के सूखने और प्रदूषित होने के कारणों में मुख्य हैं, अत्यधिक पानी का दोहन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। नदियां जीवन का आधार है, लेकिन तेजी से बढ़ते प्रदूषण, तथाकथित भौतिकवादी सोच एवं नदियों के प्रति उपेक्षा एवं दोहन के कारण कई नदियां अब 'मृत' होने की कगार पर है। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां भी दुनिया की प्रदूषित नदियों में शामिल हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर नदी प्रबंधन, नदी प्रदूषण और नदी संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना नितांत आवश्यक है। नदियां के अत्यधिक ख़तरे में होने से मानव जीवन, पर्यावरण एवं प्रकृति भी संकट में है। जरूरत है मानसूनी जल को नदियों से जोड़ने एवं संरक्षित करने की। देश में सर्वत्र नदियों का अस्तित्व खतरे में है। विशेषतः उत्तर प्रदेश में नदियों की संख्या लगभग 1,000 है, जिनका 55 हजार किलोमीटर का नेटवर्क है। उनमें से 30 हजार किलोमीटर क्षेत्र में जल घटा है या सूखा है। प्रदेश की 100 छोटी और सहायक नदियां सूख चुकी हैं। बिहार की 50 से अधिक नदियां संकट में हैं। इनमें 32 बड़ी नदियां सूख चुकी हैं, जबकि 18 में पानी थोड़ा बचा है। यमुना नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है और यह अत्यधिक प्रदूषण और पानी के अत्यधिक दोहन के कारण मरने के कगार पर है। साहिबी नदी, जो कभी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी थी। ओडिशा में कई नदियां सूख रही हैं और प्रदूषित हो रही हैं, जिससे वहां के पर्यावरण और लोगों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हैरानी की बात है कि गंगा, सोन और अघवारा जैसी बड़ी नदियों में भी पानी कम है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा-हल्द्वानी की लाइफलाइन कोसी और गौला नदियों का जलस्तर कम हो रहा है। महानदी बचाओ आंदोलन और ओडिशा नदी सुरक्षा समिति द्वारा आयोजित ओडिशा नदी सुरक्षा सम्मेलन में राज्य की नदियों की बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। सरकार से एक समग्र नदी नीति बनाने एवं ओडिशा एवं अन्य प्रांतों की नदियों की स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की पुरजोर मांग उठी। पर्यावरणविद् राजेन्द्र सिंह ने कहा, ल्लओडिशा की कई नदियां मरने के कगार पर हैं। अगर नदियों का स्वास्थ्य नहीं सुधरा, तो मानव का स्वास्थ्य भी नहीं बचेगा।' बात केवल ओडिशा की ही नहीं है, बल्कि सभी प्रांतों में सिंचाई, औद्योगिक उपयोग और घरेलू जरूरतों के लिए नदियों से अत्यधिक पानी निकाला जा रहा है, जिससे नदियों में पानी की कमी हो गई है। औद्योगिक कचरा, सीवेज और कृषि अपवाह नदियों में प्रवाहित हो रहा है, जिससे पानी प्रदूषित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के तरीकों में बदलाव आया है, जिससे कुछ क्षेत्रों में सूखे की स्थिति बढ़ गई है और नदियों में पानी का प्रवाह कम हो गया है। नदियों से रेत का अवैध खनन भी नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है और नदियों के बहाव को बदल रहा है। जंगलों की कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है, जिससे नदियों में गाद जमा हो रही है और उनकी गहराई कम हो रही है। भारत नदियों का एक अनोखा देश है जहां नदियों को पूजनीय माना जाता है। गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु (सिंधु), और कावेरी जैसी नदियों को देवी-देवताओं के रूप में पूजा जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासन में बनाया गया जल शक्ति मंत्रालय, नदी घाटियों में आर्द्रभूमि के पुनरुद्धार और संरक्षण और नदी प्रदूषण के खतरनाक स्तर से निपटने पर ध्यान केंद्रित करता है। देश के समक्ष वाटर विजन 2047 प्रस्तुत किया गया है यानी आजादी के सौ वर्ष पूरे होने तक देश को प्रत्येक वह कार्य करना है, जो देश को पानी के मामलों में सबल बना सके। इसमें हमारी नदियां भी शामिल हैं। हमें अपनी नदियों को 2047 तक निर्मल व अविरल बनाने के संकल्पित लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना होगा। भारत की नदियों की दिन-ब-दिन बिगड़ती हालत एवं बढ़ते प्रदूषण पर पिछले चार दशकों से लगभग हर सरकार कोरी राजनीति कर रही है, प्रदूषणमुक्त नदियों का कोई ईमानदार प्रयास होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। नदियां हमारे जीवन की जीवन रेखा है, गति है, ताकत है। ये पानी, बिजली, परिवहन, मछली और मनोरंजन के लिए स्रोत हैं। नदियां पर्यावरण के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हैं। नदियों के किनारे बसे शहरों की वजह से ये आर्थिक रूप से भी अहम हैं, इनसे ताज़ा पीने का पानी मिलता है, बिजली बनती है, खेती के लिए ज़रूरी उपजाऊ मिट्टी मिलती है। नदियों से जल परिवहन होता है। नदियां मरेंगी तो समाज मर जाएगा। नदियों पर खतरे के तीन बड़े कारण हैं और इन्हें पुनर्जीवन के लिए सरकारी एवं सामाजिक स्तर पर गंभीरता से प्रयास करने की जरूरत है। देश में जनसंख्या का दबाव बढ़ने के साथ ही जमीनों की कीमतें बढ़ीं, इसके साथ ही नदी किनारे भूमि पर अतिक्रमण, सिंचाई के लिए भूजल शोषण और नगरों के गंदों नालों से बढ़ता प्रदूषण नदियों के लिए गंभीर खतरा बन गए और छोटी बड़ी तमाम नदियां सूख रही है। कई नदियां बेमौत मर गईं। केंद्र व प्रदेश की सरकार को सबसे पहले नदियों की जमीन का सीमांकन व चिह्नांकन कराने के साथ ही राजस्व नक्शे में नोटिफिकेशन करना चाहिए। तभी कुछ सुधार की संभावना है। नदियां मानव अस्तित्व का मूलभूत आधार है और देश एवं दुनिया की धमनियां हैं, इन धमनियों में यदि प्रदूषित जल पहुंचेगा तो?शरीर बीमार होगा, लिहाजा हमें नदी रूपी इन धमनियों में शुद्ध जल के?बहाव को सुनिश्चित करना होगा। नदियों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किये जाने की जरूरत है। देश में नदी जल एवं नदियों के लिए कानून बने हुए है, आवश्यक हो गया है कि उस पर पुनर्विचार कर देश के व्यापक हित में विवेक से निर्णय लिया जाना चाहिए। हमारे राजनीतिज्ञ, जिन्हें सिर्फ वोट की प्यास है और वे अपनी इस स्वार्थ की प्यास को इस पानी से बुझाना चाहते हैं। नदियों को विवाद बना दिया है, आवश्यकता है तुच्छ स्वार्थ से ऊपर उठकर व्यापक मानवीय हित के परिप्रेक्ष्य में देखा जाये। यह किसी से छिपा नहीं है कि हमारे देश में गर्मी और लू के दिन जहां बढ़ रहे हैं, वहीं बरसात के दिन घटते जा रहे हैं। अब जलवायु परिवर्तन की मार देश के दूरस्थ अंचल तक दिख रही है। ऐसे में मानसूनी वर्षा के जल को यदि सलीके से नहीं सहेजा गया तो देश की सामाजिक-आर्थिक-प्राकृतिक स्थिति पर जल-संकट का बड़ा घातक प्रभाव होगा। नदियों के लिए ताजा पानी उपलब्ध कराने, जैव विविधता को बढ़ावा देने से लेकर जलवायु को नियंत्रित करने और सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने तक स्वस्थ, निर्मल एवं पवित्र मुक्त बहने वाली नदियां को संरक्षित करना जरूरी है। तालाब संरक्षण की बात तो सभी करते हैं, लेकिन आज जरूरी है कि छोटी नदियों की भी सुध ली जाए। आज गंदे पानी को नदी जल से अलग रखने के विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इस गंदे पानी को उपचारित करके उसे कृषि कार्यों व उद्योगों में उपयोग में लाया जा सकता है। हमारी जिन नदियों ने नालों का रूप धारण कर लिया है, उन्हें पुनः नदी बनाने की जरूरत है, नदियों के प्रति मित्रवत व्यवहार रखना तथा उनकी चिंता करना जरूरी है। हम नदियों की रक्षा में अग्रणी समुदायों और नागरिक समाज के आंदोलनों को मजबूत करना होगा। मजबूत डेटा और साक्ष्य उत्पन्न करने के लिए खोजी अनुसंधान को बल देना होगा। विनाशकारी परियोजनाओं का पर्दाफाश करने और उनका विरोध करने के अभियानों को स्वतंत्र और निडर बनाये। अगर इस ग्रह पर कोई जादू है तो वह पानी में है। यह हमें अपनी अर्थव्यवस्था के एक हिस्से के रूप में व्यापार और वाणिज्य के लिए सस्ता और कुशल अंतर्देशीय परिवहन भी प्रदान करता है। यह पृथ्वी पर सबसे विविध और लुप्तप्राय वन्यजीवों में से कुछ का घर भी है। **– ललित गर्ग**

जातिवाद और तुष्टीकरण की विकृत राजनीति का खतरनाक खेल

मृत्युंजय दीक्षित

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026 के पंचायत चुनावों और 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर राजनैतिक सरगर्मियां तीव्र हो रही हैं। इन सरगर्मियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश के प्रमुख विरोधी दल समाजवादी पार्टी के साथ साथ अन्य विरोधी दल भी इन आगामी चुनावों में पहले की ही तरह जातिवाद और तुष्टीकरण को ही अपना प्रमुख हथियार बनाएंगे । सपा नेता अखिलेश यादव ने जिस प्रकार पीडीए के नाम पर हिन्दू समाज को जाति -जाति में विभाजित करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने अर्थात वर्ष 2027 में सपा सरकार बनाने की योजना बनाई है वह वास्तव में प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त करने का एक खतरनाक खेल है। विगत दिनों प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जो इस खतरनाक खेल की आहट दे रही हैं। समाजवादी अखिलेश यादव द्वारा तथाकथित पीडीए की राजनीति को संबल देने के लिए जो बयानबाजी की जा रही है तथा उनकी पार्टी और समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर जैसी टिप्पणियां की जा रही हैं उनसे प्रदेश में शांति भंग होने की आशंका बढ़ रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव इटावा में कथावाचक के साथ घटी घटना पर आक्रामक होकर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं वहीं नैमिष में एक अन्य कथावाचक के साथ घटीअप्रिय घटना पर मौन हैं। यह तो अच्छा हुआ कि पुलिस प्रशासन ने इटावा के कथावाचक के साथ मारपीट की घटना से सम्बंधित चार संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना की निष्पक्ष जांच आरंभ हो गई है। इटावा की घटना को लेकर अनावश्यक रूप से ब्राह्मण समाज के विरुद्ध सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं वो सामाजिक वैमस्यता बढ़ाने वाली हैं। स्मरणीय है कि सत्ता की भूख में आज पीडीए की बात करने वाले सपा मुखिया की सरकार बनते ही 2012 में सबसे पहले सीतापुर में बड़ी संख्या में दलित समाज के घरों को जला दिया गया था। इटावा की घटना की जांच चल रही है किंतु अखिलेश यादव जांच रिपोर्ट को प्रभावित करने के लिए गलत बयानी कर रहे हैं। हिंदू समाज में किसी भी जाति का, कोई भी व्यक्ति जिसे धर्मग्रंथों का ज्ञान है तथा जनमानस को अच्छी बातें बताने की क्षमता रखता है वह कथावाचक कर सकता है। अधिकांश कथा वाचक गैर ब्राह्मण ही हैं। कथावाचक की जाति पर कभी चर्चा नहीं होती। यदि कोई कथावाचक अपनी जाति व धर्म को छुपाकर यह कृत्य करता है तो चिंता की बात है। कोई कथा कहना चाहता है तो उसे अपना सही नाम बताने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए । नाम छुपाने के साथ साथ एक से अधिक आधार कार्ड रखना एक आपराधिक कृत्य है कोई कथावाचक ऐसा क्यों करेगा ? इस पूरी घटना में सपा की प्रतिक्रिया से लगता है कि संभव है कि इटावा की घटना सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत करवाई गई हो और एक समय बसपा का नारा रहे ल्लतिलक, तराजू और तलवार इनको मारो जूते चारल्ल को अब सपा ने अपना लिया है। सपा ने पीडीए का दिल जीतने के लिए ब्राह्मण समाज का अपमान किया है। इस बीच सपा ने राज्यसभा चुनावों के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले तीन विधायकों ऊंचाहार से मनोज कुमार पांडेय, गोसाईगंज से अभय सिंह और गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। सपा की ओर से एक्स पर लिख गया कि सांप्रदायिक व पीडीए विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण तीनों विधायकों को निकाला गया है।वहीं इन विधायकों का कहना है कि भगवान राम और रामचरित मानस के अपमान का विरोध करने के कारण इन सभी को निष्कासित किया गया है। विधायक मनोज पांडेय ने कहा कि मैंने सपा नेताओं द्वारा हिंदू देवी- देवताओं को गाली दिए जाने तथा रामायण की प्रतियां जलाने का विरोध किया था। विधायक मनोज पांडेय अयोध्या में रामलला के दर्शन भी कर आये हैं। सभी विधायकों ने कहा कि सपा में हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। समाजवादी पार्टी ने अब लोहिया की विचारधारा को त्याग चुकी है। अखिलेश यादव आजकल कोई भी विषय हो पीडीए को बीच में घसीट लाते हैं। हाल ही में सोने -चांदी के बढ़ रहे दामों पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि सोने -चांदी के दाम चरम सीमा पर है जिस कारण गरीब पीडीए समाज की बिटिया की सगाई में सोना कैसे खरीदा जाएगा जबकि वह अच्छी तरह से जानते हैं कि सोने चांदी की कीमतों पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है अपितु यह अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर होता है।

सेहत मंत्र

मुंह-फ़ेफड़े के कैंसर से लेकर हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाता हैं तंबाकू का सेवन

तंबाकू के मुंह के रोग-ओरल कैंसर और धूम्रपान को फ़ेफड़ों के कैंसर का मुख्य कारण माना जाता है। लेकिन इसका जोखिम यहीं तक सीमित नहीं रहता है। लेकिन तंबाकू और धूम्रपान आपके संपूर्ण शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं गड़बड़ लाइफस्टाइल और खान-पान से संबंधित दिक्कतों के कारण गंभीर और क्रॉनिक बीमारियां होती हैं। लेकिन जिस आदत की वजह से स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, वह तंबाकू और धूम्रपान की आदत है। तंबाकू स्वास्थ्य के लिए गंभीर नुकसानदायक हो सकता है। यह शरीर के हर अंग को नुकसान पहुंचाता है। वहीं कई अध्ययन से यह पता चलता है कि तंबाकू का सेवन असमय मृत्यु का कारण है। वहीं देश की एक बड़ी आबादी खासकर युवा इसका शिकार हो रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट की मानें, तो आमतौर पर तंबाकू और धूम्रपान के कारण हार्ट अटैक और मस्तिष्क संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको तंबाकू की वजह से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बताने जा रहे हैं। धूम्रपान के रूप में तंबाकू फ़ेफड़ों और श्वसन तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इससे फ़ेफड़ों के कैंसर होने की संभावना 15 गुना तक बढ़ जाती है। वहीं जो लोग धूम्रपान करते हैं, उनमें सीओपीडी रोग होने का खतरा अधिक रहता है। यह फ़ेफड़ों की एक गंभीर बीमारी है, इसमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 90% फ़ेफड़ों के कैंसर के मामलों के लिए धूम्रपान की आदत को मुख्य कारक माना जाता है। खैनी, बीड़ी और गुटखा जैसी चीजें मुंह की बीमारियों से लेकर ओरल कैंसर के खतरे को कई गुना तक बढ़ा देती है। जो लोग तंबाकू चबाते हैं, उनके मुंह में कैंसर होने का खतरा हो सकता है। तंबाकू में मौजूद तत्व निकोटीन मसूड़ों और दांतों को कमजोर करता है। वहीं इससे पायरिया का खतरा भी बढ़ा सकता है। भारत में मुंह का कैंसर सबसे आम कैंसर में से एक है।

धर्म मंत्र

सृष्टि का सृजन और समय पर उसका संहार दोनों भगवान रुद्र के ही कार्य हैं

शैवगाम के अनुसार भगवान रुद्र के आठवें स्वरूप का नाम हर है। भगवान हर को सर्पभूषण कहा गया है। इसका अभिप्राय यह है कि मंगल और अमंगल सब कुछ ईश्वर शरीर में है। समय पर सृष्टि का सृजन और समय पर उसका संहार दोनों भगवान रुद्र के ही कार्य हैं। भगवान हर अपनी शरण में आने वाले भक्तों को आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तपों से मुक्त कर देते हैं। इसलिए भगवान रुद्र का हर नाम भी सार्थक है। इनका पिनाक अपने भक्तों को अभय करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। जब भगवान शंकर के पुत्र स्कन्द ने तारकासुर को मार डाला, तब उसके तीनों पुत्रों को महान संताप हुआ। उन्होंने मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर हजारों वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्माजी को प्रसन्न किया। ब्रह्माजी ने उन तीनों के वर मांगने पर उनके लिए स्वर्ण, चांदी और लौह के अजेय नगर का निर्माण करने के लिए मय दानव को आदेश दिया। इस प्रकार मय ने अपने तपो बल से तारकाक्ष के लिए स्वर्णमय, कमलाक्ष के लिए रजतमय और विद्युन्माली के लिए लौहमय? तीन प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार कर दिये। इन पुरों का भगवान हर के अतिरिक्त कोई भेदन नहीं कर सकता था। ब्रह्माजी के वरदान एवं शिवभक्ति के प्रभाव से तीनों असुर अजेय होकर देवताओं के लिए संतापकारी हो गये। इंद्रादि देवता उनके अत्याचार से पीड़ित होकर भटकने लगे।

पर्यटन

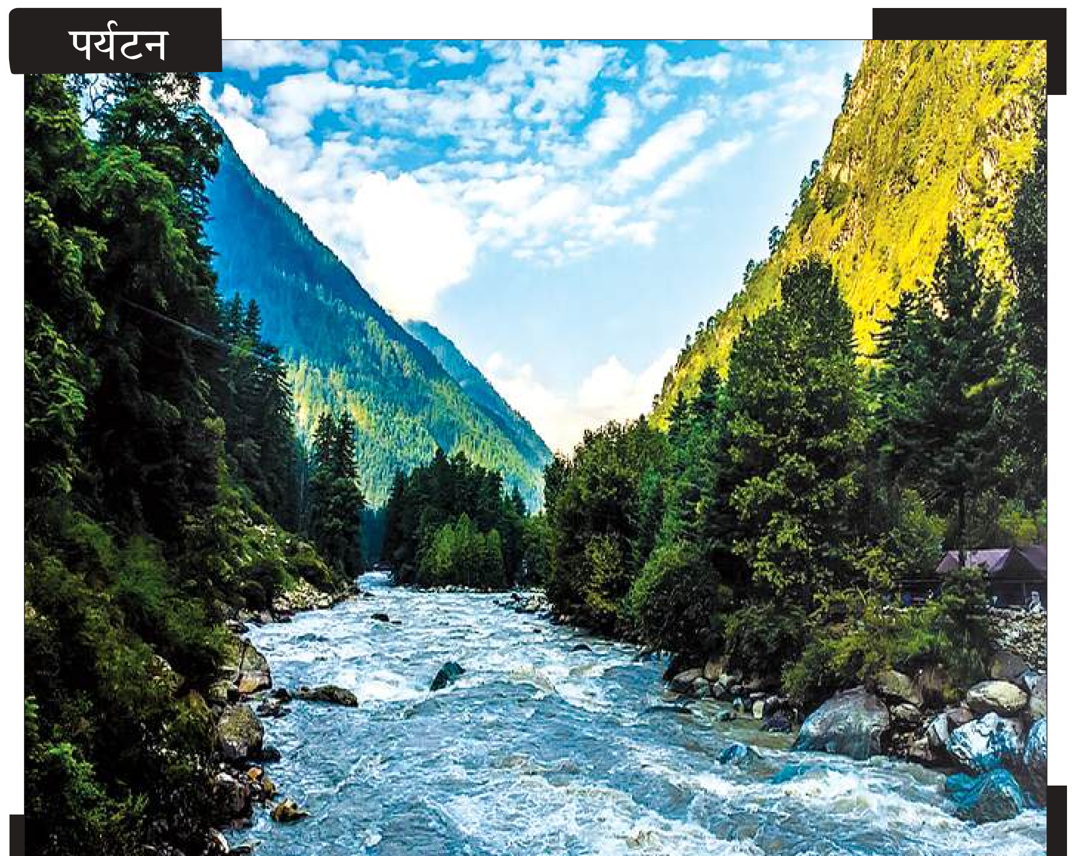

प्रकृति, शांति और रोमांच का संगम है पार्वती घाटी में बसा कसोल

हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में बसा कसोल एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जो खासकर युवाओं, ट्रेकिंग प्रेमियों और विदेशी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। समुद्र तल से लगभग 1,580 मीटर की ऊँचाई पर स्थित कसोल को ल्लभारत का मिनी इज़राइलङ्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में इज़राइली पर्यटक आते हैं और यहाँ की संस्कृति में उनका प्रभाव देखा जा सकता है। कसोल एक शांत और सुरम्य गाँव है, जो पार्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ का वातावरण बेहद शांत, स्वच्छ और ठंडा होता है। ऊँचे पहाड़, घने देवदार के जंगल, कलकल बहती पार्वती नदी और रंग-बिरंगे कैफ़े इस स्थान को बेहद आकर्षक बनाते हैं। यह तेज बहाव वाली नदी कसोल की जान मानी जाती है। इसके किनारे टहलना, चट्टानों पर बैठकर मन को शांति देना और फोटोग्राफी करना पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। कसोल से थोड़ी दूरी पर स्थित ये गाँव अपने प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। मणिकरण में गर्म पानी के झरने और गुरुद्वारा प्रमुख आकर्षण हैं, जबकि तोश ट्रेकिंग प्रेमियों का पसंदीदा गाँव है। कसोल से लगभग 30 मिनट की पैदल दूरी पर स्थित यह छोटा गाँव ट्रेकिंग और कैम्पिंग के लिए आदर्श है। यहाँ आप स्थानीय संस्कृति को करीब से जान सकते हैं। कसोल में कई इज़राइली कैफ़े और रेस्तराँ हैं जहाँ आप फलाफल, शाकशूका, हुम्मस आदि विदेशी व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं।

कैसे पहुँचे कसोल- हवाई मार्गः निकटतम हवाई अड्डा भुंतर (कुल्लू) है, जो कसोल से लगभग 31 किमी दूर है। रेल मार्गः निकटतम रेलवे स्टेशन जोगिंदरनगर है, लेकिन सड़क मार्ग से पहुँचना अधिक सुविधाजनक है। सड़क मार्गः दिल्ली, चंडीगढ़ और मनाली से कसोल तक नियमित बस और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं। कसोल एक ऐसा गंतव्य है जहाँ आप भीड़भाड़ से दूर प्रकृति के साथ एक गहरा रिश्ता बना सकते हैं।

सरयू तट पर मॉक ड्रिल, राहत-बचाव तैयारियों को परखा

कैनविज टाइम्स संवाददाता

बाराबंकी। जिले के संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में गुरुवार को प्रशासन ने सरयू नदी के तट पर मॉक ड्रिल कर राहत-बचाव की तैयारियों को परखा। साथ ही ग्रामीणों को बाढ़ से निपटने और सावधानी बरतने का प्रशिक्षण भी दिया गया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि बाढ़ के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। रामनगर तहसील के पांडेयपुर बाढ़ शरणालय के पास चल रही माक ड्रिल के दौरान अनाउंसमेंट कर बताया गया कि हेतमापुर के पास अचानक सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पानी के तेज बहाव में दो युवक बह गए हैं। घटना की सूचना पर तत्काल पीएसी की फ्लड कंपनी के साथ एसडीएम विवेकशील व तहसीलदार विपुल सिंह मौके पर पहुंच गए। फ्लड कंपनी के जवानों ने स्टीमर से रेस्क्यू कर बहते हुए युवकों को बचाया। इसके बाद उन्हें किनारे लाया गया, जहां पहले से सतर्क स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एंबुलेंस की मदद से दोनों युवकों को बेहोशी की हालत में चिकित्सा शिविर में ले गए, जहां डॉ. प्रदीप यादव की देखरेख में स्वास्थ्य टीम ने उनका प्राथमिक उपचार किया गया। इस प्रदर्शन को देखने के लिए नदी के किनारे काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी रही। बाढ़ शरणालय के सामने फॉयर ब्रिगेड की टीम ने रिहर्सल किया। इस दौरान आग लगने की सूचना पर सायरन बजाते हुए मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग बुझाने के साथ ही आग से झुलसे एक युवक को इलाज के लिए स्ट्रेचर पर लेकर भागते दिखे। दमकल की टीम ने आग बुझाकर हालातों पर काबू पाया। एसडीएम रामनगर, विवेकशील यादव ने बताया कि मॉक ड्रिल में उन तैयारी को परखा गया कि यदि आपात स्थिति में लोग बाढ़ के पानी में फंस जाते हैं तो उन्हें कैसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उन्हें राहत पहुंचाई जा सकती है। सूरतगंज सीएचसी अधीक्षक डॉ. राजर्षि त्रिपाठी ने लोगों को जलजमाव के कारण होने वाली बीमारियों से बचाव के तरीके बताए। जिला आपदा प्रबंधन की टीम ने बाढ़ से बचाव में उपयोग के लिए लाइफ सेविंग जैकेट, मोटर बोट व नाव आदि के संचालन की भी जानकारी दी गई। इस मौके पर सीओ जगत कनौजिया, नायब तहसीलदार विजय प्रताप, बीडीओ देवेंद्र प्रताप सिंह, बीईओ संजय रॉय, डॉ प्रणव श्रीवास्तव, पशु चिकित्साधिकारी सुजीत सचान के साथ-साथ राजस्व विभाग, नाविकों व गोताखोरों की पूरी टीम शामिल रही।

नियम कानून ताक पर दुकानों से हो रही शराब की बिक्री

निन्दूरा बाराबंकी, कैनविज टाइम्स संवाददाता। पुलिस व आबकारी अधिकारियों की साठगांठ एवं अनदेखी के चलते ग्रामीण क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित दुकानों पर शराब की बिक्री बेरोकटोक हो रही है। किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। विकास खण्ड निन्दूरा क्षेत्र में सुबह होते ही शराब के ठेकों से किसी भी समय शराब खरीदी जा सकती है। शराब के ठेकों से सुबह होते ही शराब की बिक्री सेल्समेन शुरू कर देते हैं। बृहस्पतिवार को कस्बा टिकैतगंज स्थित देसी शराब की दुकान पर प्रातः सात बजे से ही शराब की अवैध बिक्री शुरू हो गई थी। सेल्समैन ने दुकान का शटर खोला और निडर हो शराब की बिक्री शुरू कर दी। लखनऊ महमूदाबाद मार्ग पर शराब के दुकानदारो को आबकारी अधिकारियों का खौफ नहीं है।कहने में कोई गुरेज नहीं कि बिना संरक्षण के सुबह सात बजे से शराब की बिक्री होना संभव ही नहीं है। कस्बा टिकैतगंज में संचालित देशी शराब के ठेके पर शराब की बिक्री का कोई समय नहीं है। जबकि विभाग और प्रशासन की ओर से शराब को बेचने का समय सुबह दस बजे से लेकर रात के दस बजे तक निर्धारित किया गया है। रात दस बजे के बाद सेल्समेन के द्वारा शटर तो गिरा दिए जाते हैं ,लेकिन बिक्री जारी रहती है। यह किसी एक ठेके की घटना नहीं है बल्कि निन्दूरा क्षेत्र में संचालित कई ठेकों का लगभग यही हाल है, लेकिन शराब ठेकेदार नियम को ताक पर रखकर बिक्री में जुटे है। बृहस्पतिवार को कस्बा टिकैतगंज स्थित पुलिस पिकेट से मात्र 200 मीटर की दूरी पर सुबह से ही शराब बिक्री की जा रही थी। लोगों के द्वारा पुलिस को शराब की अवैध बिक्री की जानकारी दी जाती है तो पुलिस अनजान बन जाती है। ग्रामीणों की माने तो कस्बा टिकैतगंज के नाम से संचालित शराब की दुकानें लखनऊ महमूदाबाद मार्ग के किनारे बिसई ग्राम पंचायत में संचालित की जा रही है, जबकि जिस जगह के नाम से दुकानें होती है उन्ही जगह पर संचालित करना चाहिए। कंडुआ चौराहा स्थित महाकालेश्वर मंदिर से अंग्रेजी शराब और बियर की दुकान लगभग 100 मीटर की दूरी है ,लेकिन दुकानदार बिना भय के बिक्री में लगे हुए है जोकि नियम विरुद्ध है।

व्यापारी नेता का निधन, शोक की लहर

जैदपुर बाराबंकी, कैनविज टाइम्स संवाददाता। नगर के मोहल्ला समेढी निवासी प्रतिष्ठित समाजसेवी व्यापारी अजमत अली उर्फ बब्बू का बुधवार देर रात लखनऊ में इलाज के दौरान निधन हुआ। जिन्हें पूरब ओर कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया।स्वर्गीय बब्बू का सामाजिक क्षेत्र में गहरा प्रभाव था। और वह अपने मृदु व्यवहार व सेवा भाव के लिए आम जनमानस में अत्यंत लोकप्रिय थे। बब्बू शेख वर्षों से सामाजिक व व्यापारिक क्षेत्र में सक्रिय थे। उन्होंने हमेशा गरीबों जरूरतमंदों और वंचित वर्ग के मदद के लिए आगे बढ़कर कार्य किया। नगर के गणमान्य ,पत्रकार व अधिवक्ता तथा जनप्रतिनिधिभी कब्रिस्तान पहुंचे। निवर्तमान चेयर प्रति निधि रियाज अहमद चेयरमैन प्रतिनिधि दाऊद अंसारी व्यापारी नेता मो. सालिम पूर्व अध्यक्ष जियाउर रहमानपत्रकार वसीम खान अबू उमैर अंसारी सभासद मो. कासिम अबू दरदा .मास्टर मो. अहमद परवेज खान चांद खान सहित कई सैकड़ा लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार को ढाढस बधाया।

चक्की के पट्टे में लिपटकर युवक की मौत

निंदूरा बाराबंकी, कैनविज टाइम्स संवाददाता। कुर्सी थाना क्षेत्र के मीननगर निवासी कैलाश गौतम का 15 वर्षीय पुत्र शिवा गौतम रौनाहार निवासी मनोज यादव की आटा चक्की कारखाने में मजदूरी करता था। शिवा गुरुवार सुबह काम करने कारखाने पहुंचा था।चक्की चलाते समय किशोर की शर्ट का एक भाग पट्टे की चपेट में आया जिससे किशोर की दर्दनाक मौत हुई।मौके पर मौजूद ग्राहकों ने इंजन बंद कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।उधर घटना के बाद कारखाने का मालिक मौके से फरार हो गया।कुर्सी थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि बताया कि किशोर कारखाने पर पहले नौकरी करता था लेकिन आज वह गेंहू पिसाने गया था। किशोर की मजदूरी से ही परिवार पलता था कमाऊ घर के मुखिया की मौत से जहां जीवन यापन का सहारा चला छिन गया। पारिवारिक गहरे सदमे में है।

किसानों को समितियों पर नहीं मिल रही है खाद

निन्दूरा बाराबंकी, कैनविज टाइम्स संवाददाता। सरकारी समितियों पर खाद होने के बावजूद भी किसान समितियों से खाद नहीं पा रहे हैं जिसके चलते किसान प्राइवेट दुकानों से खाद खरीदने को मजबूर है किसानों का कहना है कि कस्बा कुर्सी स्थित सहकारी समिति के बाहर महमूदाबाद मार्ग के चौड़ीकरण में क़स्बों में रोड के दोनों ओर नाला बनना है जिसे खोदा गया है जोकि अधूरा पड़ा है जिसके चलते जाने का कोई रास्ता न होने के चलते समिति से किसान खाद नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे है। एडीओ कोऑपरेटिव प्रेम प्रकाश अभिनेत्री ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई से शिकायत करने के बाद भी नाला निर्माण कार्य में तेजी नहीं लाई गई है, जिसके चलते किसानों को समिति से खाद लेने में दिक्कत हो रही है।इस संबंध में पीडब्ल्यूडी जेई आरबी सरोज ने बताया कि कल एक तरफ की दीवार बन गई है कल दूसरी तरफ की भी दीवार बन जाएगी।

जातिवादी राजनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा: जयवीर सिंह

कैनविज टाइम्स संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि इटावा की घटना में अब तक 15 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। किसी भी आरोपी को जाति के आधार पर नहीं, अपराध के आधार पर पकड़ा गया। चारों आरोपियों की गिरफ्तारी कर निष्पक्ष जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। जयवीर सिंह गुरूवार को लखनऊ में प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है, शांति व्यवस्था बहाल कर दी गई है। बिना सच्चाई सामने आए, अखिलेश यादव ने इस मामले को सीधे जातीय रंग देने की कोशिश की। ब्राह्मण समुदाय पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उन्होंने जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने जाति देखकर अपराध पर प्रतिक्रिया दी, न कि तथ्यों को जांचकर। सरकार सभी संगठनों को भरोसा दिलाती है कि न्याय होगा और दोषी बचेंगे नहीं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जातीय संघर्ष को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। यह संघर्ष स्वाभाविक नहीं, बल्कि सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है।

जयवीर सिंह ने कहा कि कुछ दल जनसमर्थन न मिलने के कारण अब समाज में जातीय टकराव पैदाकर अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहें है। उनका उद्देश्य देश को गुलामी के उस कालखंड में फिर से ले जाना है जहां जाति, धर्म और क्षेत्र के नाम पर देश को बांटकर विदेशी ताकतों ने शासन किया था। सीएम का स्पष्ट निर्देश है कि जातीय हिंसा फैलाने वालों की सार्वजनिक रूप से पहचान की जाए। ऐसे लोगों को समाज को तोड़ने वाला और देश के लिए खतरा बताया जाए।

सामाजिक न्याय, नारी उत्थान एवं कल्याण के नायक थे छत्रपति : राकेश

कैनविज टाइम्स संवाददाता

बाराबंकी। छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर आज विविध आयोजन हुए। नगर पालिका परिषद मेंधूमधाम से जयंती मनाई गई। इसी क्रम में मौली क्षेत्र के ग्राम चक स्थित देवश्री मैरिज लान में कुर्मी स्वाभिमान महासंघ के तत्वावधान में कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षा में 90 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले 30 मेधावियों को सम्मानित किया गया। छत्रपति साहूजी महराज जयंती को सम्बोधित करते हुए पूर्व कारागार मंत्री राकेश कुमार वर्मा ने कहा कि साहू जी महाराज सामाजिक न्याय, नारी उत्थान और समाज कल्याण के नायक थे जो शोषित, वंचितों के महानायक, महान समाज सुधारक, दार्शनिक आदर्श पुरुष थे जिन्होंने आरक्षण की नींव रखी और समाज में व्याप्त अनेकों बुराइयों को समाप्त किया था। पूर्व ब्लाक प्रमुख एवं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह वर्मा ने कहा कि शाहूजी महाराज ने दलित और शोषित वर्ग के दुख दर्द को बहुत करीब से समझा और उनसे निकटता बनाकर उनके मान-सम्मान को ऊपर उठाया । वरिष्ठ नेत्र सर्जन डा. विवेक कुमार वर्मा ने कहा कि शाहूजी महाराज गैरबराबरी की व्यवस्था को खत्म करने के लिए देश में पहली बार अपने राज्य में पिछड़ों के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू की। कुर्मी स्वाभिमान महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक इंजीनियर एस पी वर्मा ने कहा कि शाहूजी महाराज सामाजिक न्याय, नारी उत्थान, और समाज के कल्याण के नायक थे उन्होंने ज्योतिबा फुले के सिद्धांतो को मानते हुए डा0 भीम राव अम्बेडकर जैसे सामाजिक क्रांति करियो का अनुशरण किया इसीलिए उन्हे ज्योतिबा और बाबा साहब के बींच कड़ी मना गया है।

कुर्मी स्वाभिमान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष इजी. त्रिभुवन सिंह की अध्यक्षता एव वीरेंद्र वर्मा के संचालन मे आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए जिला संयोजक मास्टर ओमप्रकाश वर्मा ने कुर्मी समाज के लोगो का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शाहू जी महराज के बताये हुए रास्ते पर चल कर समाज को उचाईयो तक पहुंचाया जा सकता है। कार्यक्रम हाई स्कूल एव इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाले 30 बच्चो को शील्ड एव प्रशस्ती पत्र देकर सम्मानित किया गया।

इस मौक़े पर राम मनोहर वर्मा, भुकांत वर्मा,अरुण कुमार वर्मा, डा0 प्रीति वर्मा, देशराज वर्मा, सत्यवान सिंह, वीरेंद्र वर्मा, उत्तम वर्मा, श्यामलाल वर्मा, जयकिशन वर्मा, विजय बहादुर वर्मा, संजीव कुमार वर्मा सहित भारी संख्या मे कुर्मी समाज के लोग मौजूद रहे।

सरकारी स्कूलों को खत्म नहीं होने देंगे: संजय सिंह

लखनऊ। आम आदमी पार्टी (आप) सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में 27 हजार सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और गांव-गांव में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। श्री सिंह ने यहां एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि पिछले चार सालों में 42 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा छोड़ी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार एक साल में यूपी में आठ लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा छोड़ी है और प्रदेश की सरकार विद्यालय के ऊपर ही बुलडोजर चला रही है। उन्होंने कहा कि 5695 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक है, केवल अलीगढ़ में ही 58000 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ दी।

उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां-जहां भी स्कूल बंद किए जाएंगे वहां आम आदमी पार्टी उन गांव के अंदर और जिला मुख्यालयों पर आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि हम विद्यालयों को कतई बंद नहीं होने देंगे, आम आदमी पार्टी इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेगी।

समाजवाद का विरोध करने वाले संविधान के विरोधी: अखिलेश

कैनविज टाइम्स संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का विरोध करने वाले संविधान, सामाजिक न्याय, आरक्षण के विरोधी है।

श्री यादव ने यहां एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि भाजपा सत्ता में पहुंचने के लिए तो संविधान की बात करती है। संविधान को मानने और उस पर चलने की चर्चा करती है लेकिन जब सत्ता में आ जाती है तब संविधान नहीं मानती है। भाजपा के लोग शपथ तो लेते है लेकिन उनके काम करने के तरीके से लगता है शपथ की निष्ठा का पूर्ण अभाव होता है।

उन्होने कहा कि इधर हम देख रहे है कि मुख्यमंत्री जी सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म के बारे में बहुत बोलते है। सच्चाई तो यह है कि जो सोशलिस्टों के खिलाफ है, वही सेकुलर के खिलाफ है। समाज के निर्माण के लिए अपनी वैयक्तिता का विलय करना पड़ता है। जो लोग अपने स्वार्थ सिद्धि में लिप्त रहते है और हर समय अपने बारे में सोचते है वे केवल अपने दंभ और अहंकार में रहते हैं उन्हें समाज से कुछ लेना देना नही रहता है। ये खुदगर्ज लोग समाज और समाज से जुड़े हर विचार और शब्द के खिलाफ रहते है फिर वो शब्द चाहे सामाजिकता का हो या समाजवादी हो। श्री यादव ने कहा कि इसीलिए चाहे सदन में हो या सदन के बाहर हो, कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उनके इसी तरह के विचार सुनने को मिलते है। ये समाजवाद के खिलाफ है। ऐसे नकारात्मक लोग अपनी ताकत बनाये रखने के लिए समाज को कमजोर करते रहते हैं। उनकी शक्ति का प्रदर्शन तभी होता है जब समाज कमजोर दिखाई दे। ऐसे लोग मूल रूप से सांप्रदायिक होते है। पंथनिरपेक्ष और सेकुलरिज्म के धुर विरोधी होते हैं। उन्होने कहा कि पंथ निरपेक्षता और सेकुलरिज्म लोगों को करीब लाती हे। सहनशीलता बनाती है जियो और जीने दो का सिद्धान्त सिखाती है। सबके बीच मेलजोल और सौहार्द बनाती है। देश की गंगा-जमुनी तहजीब को मजबूत करती है। दिलों को एक-दूसरे से जोड़ती है। सोशलिस्ट और सेकुलरिस्ट होने के लिए बड़े दिलवाला होना चाहिए। हार्टलेस लोग इसका हमेशा विरोध करते है।

श्री यादव ने कहा कि पीडीए की पाजिटिव पालटिक्स निगेटिव लोगों को स्वीकार नही होती है, पीडीए पाजिटिव और विकास की राजनीति करती हैं। पीडीए जनाधिकार का ऐलान है, एकाधिकार के मुकाबले जनाधिकार जीतेगा। पीडीए पॉजिटिव लोगों का नारा है और एनडीए निगेटिव लोगों का समूह। एक सवाल के जवाब में श्री यादव ने कहा कि भाजपा बिहार में बहुत बुरी तरह से हार रही है। बिहार के लोग समझ गये है कि भाजपा महाराष्ट्र के फार्मूले पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और श्री तेजस्वी यादव के साथ है। उनकी पूरी मदद करेगी और पूरी तरह से लालू यादव के साथ खड़ी रहेगी।

एमडीए ने विभिन्न स्थानों पर 345 वर्गमी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण किया सील

एजेंसी

मुरादाबाद। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुभव सिंह के निर्देश पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जोन-4 के विभिन्न स्थलों पर अवैध निर्माणों के विरुद्ध विधिसम्मत सील की कार्रवाई की गई। प्रवर्तन टीम ने अलग-अलग स्थानों पर 345 वर्गमीटर जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को सील किया।

नगर क्षेत्र एवं अधिसूचित क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमण के विरुद्ध मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सघन प्रवर्तन अभियान निरंतर संचालित किया जा रहा है। गुरुवार को मझोला रोड, सलेमपुर बाईपास, गजरौला जोन-4, सब-जोन-23 में अजय कुमार गोस्वामी द्वारा लगभग 100 वर्ग मीटर में एमडीए स्वीकृति के बिना किए जा रहे अवैध निर्माण को सील किया गया।

गजरौला में स्वागत होटल के पास इंद्रजीत सिंह पुत्र महावीर सिंह के लगभग 85 वर्ग मीटर पर, जोन-4, सब-जोन-22 महेन्द्रा शोरूम के पास देवेंद्र सिंह के 80 वर्ग मीटर पर, सत्संग भवन के पास गली में ओम चौधरी द्वारा लगभग 80 वर्ग मीटर जमीन पर बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के अवैध निर्माण कार्य किए जा रहे थे। आज प्रवर्तन टीम के पहुंचने पर उपरोक्त व्यक्तियों ने प्राधिकरण की स्वीकृति पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अनधिकृत निर्माण पाए जाने पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा नियमानुसार उक्त भवनों को सील कर दिया गया।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने अपील करते हुए कहा कि प्राधिकरण पुनः कड़ी चेतावनी देता है कि कोई भी व्यक्ति बिना विधिवत स्वीकृति के भूमि उपविभाजन, प्लाटिंग अथवा निर्माण कार्य न करें। अन्यथा सीलिंग, ध्वस्तीकरण एवं विधिक कार्यवाही तत्काल प्रभाव से अमल में लाई जाएगी। अतः सभी नागरिक नगर विकास नियमों का पालन करें एवं किसी भी प्रकार की अवैध प्लाटिंग अथवा निर्माण की सूचना तत्काल प्राधिकरण को उपलब्ध कराएं। प्राधिकरण का प्रवर्तन अभियान भविष्य में भी इसी सख्ती एवं गंभीरता के साथ जारी रहेगा।

आपातकाल के दौरान न्यायपालिका की भूमिका पर परिचर्चा का आयोजन

आपातकाल के दौरान भी अडिग रही न्यायपालिका : अशोक

कैनविज टाइम्स संवाददाता

प्रयागराज। देश में आपातकाल के दौरान भी भारत की न्यायपालिका न सिर्फ अडिग रही बल्कि उसने संविधान के मौलिक स्वरूप को बचाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। इसके फलस्वरूप ही आज हम अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग कर पा रहे हैं। यह विचार उत्तर प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक मेहता ने गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में आयोजित एक परिचर्चा में व्यक्त किए।

आपातकाल में न्यायपालिका की भूमिका विषय पर परिचर्चा का आयोजन भारतीय भाषा अभियान काशी प्रांत द्वारा किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक मेहता ने कहा कि आपातकाल के दौरान 39वां संविधान संशोधन लाया गया। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को सीमित कर दिया गया। इस संशोधन की वैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को कम करना संविधान के मौलिक ढांचे में परिवर्तन करना है, इसलिए इस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अपर महाधिवक्ता अशोक मेहता ने कहा आपातकाल भारत के लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय है। इस दौरान मीसा जैसे कानून में हजारों भारतीयों को नजरबंद किया गया और न्यायपालिका से ऐसे मामलों की सुनवाई का अधिकार छीन लिया गया। लेकिन देश के दस उच्च न्यायालयों ने इसके बावजूद जमानतें मंजूर की। मीसा बंदियों की कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची। जिस पर पांच जजों की पीठ ने बहुमत से फैसला दिया कि मीसा बंदियों की याचिकाएं स्वीकार नहीं हो सकती। लेकिन जस्टिस एच आर खन्ना ने इसके विपरीत निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि संविधान हो या न हो नैसर्गिक अधिकार फिर भी रहेंगे। क्योंकि यह सनातन है। परिचर्चा का संचालन भारतीय भाषा अभियान के काशी प्रांत संयोजक अजय कुमार मिश्रा ने किया। इसमें हाइकोर्ट इकाई के संयोजक पवन कुमार राव, सह संयोजक अनूप कुमार मिश्र, ए पी मिश्रा, नरसिंह दीक्षित, सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी, अभिषेक, अमन, अनीता परिहार, सीमा वर्मा, लब्ध प्रतिष्ठ मिश्र, शिव पूजन राय, दिनेश सिंह, संजय राय, मनीष द्विवेदी, अरविन्द सिंह, सलीम खान, भूपेंद्र, अंकित गौर, धर्मेंद्र सिंह, स्मृति शुक्ला, अनुज त्रिपाठी आदि शामिल रहे।

'ताश के पत्तो की तरह बिखर गए कंगारू'

टेस्ट क्रिकेटर में वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया पर बरपाया कहर, 180 रन पर निपटाया

एजेंसी

ब्रिजटाउन। वेस्टइंडीज ने पहले क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन आस्ट्रेलिया को 180 रन पर आउट करने के बाद चार विकेट जल्दी गंवा दिये। पहले दिन का खेल समाप्त होने पर वेस्टइंडीज ने चार विकेट पर 57 रन बनाये थे। ब्रेंडन किंग पदार्पण करते हुए 23 रन बनाकर खेल रहे थे। इससे पहले आस्ट्रेलियाई टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 57 ओवर में 180 रन पर आउट हो गई जो वेस्टइंडीज में उसका न्यूनतम स्कोर है।

एक के बाद एक विकेट से कंगारू पस्त वेस्टइंडीज के लिये जेडेन सील्स ने 60 रन देकर पांच विकेट लिये लेकिन शामार जोसेफ सबसे प्रभावी गेंदबाज रहे जिन्होंने 46 रन देकर चार विकेट चटकाये। आस्ट्रेलिया के लिये सिर्फ उस्मान ख्वाजा (47), ट्रेविस हेड (59) और कप्तान पैट कमिंस (28) ही दोहरे अंक तक पहुंच सके। दो सप्ताह पहले विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आस्ट्रेलियाई टीम पहले दिन 212 रन पर आउट हो गई थी। एक घंटे के खेल के बाद आस्ट्रेलिया का स्कोर तीन विकेट पर 22 रन था। मार्नस लाबुशेन की जगह खेल रहे सैम कोंस्टास चौथे ओवर में जोसेफ की गेंद पर पगबाधा आउट हो गए। कैमरन ग्रीन को आते ही गली में किंग ने जीवनदान दिया। वह तीन रन बनाकर जोसेफ की गेंद पर दूसरी स्लिप में कैच दे बैठे। चोटिल स्टीव स्मिथ की जगह चौथे नंबर पर उतरे जोश इंगलिस ने सील्स की गेंद पर विकेटकीपर शाइ होप को कैच थमाया। ख्वाजा ने ट्रेविस हेड के साथ 89 रन की साझेदारी की जो आस्ट्रेलियाई पारी की सबसे बड़ी साझेदारी थी। हेड चाय के बाद अपना विकेट गंवा बैठे। आखिरी तीन विकेट सील्स ने लिये।

सूर्यकुमार यादव की जर्मनी में सफल स्पोर्ट्स हर्निया सर्जरी, जल्द शुरू करेंगे रिहैबिलिटेशन

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने जर्मनी के म्यूनिख शहर में अपने निचले दाहिने पेट में स्पोर्ट्स हर्निया की सफल सर्जरी करवाई है। यह जानकारी खुद सूर्यकुमार ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया के ज़रिए साझा की। सूर्या ने अपने पोस्ट में लिखा, ''लाइफ अपडेटः निचले दाहिने पेट में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी करवाई है। सर्जरी सफल रही और अब मैं रिकवरी की राह पर हूं। जल्द वापसी करने के लिए उत्साहित हूं,। स्पोर्ट्स हर्निया एक प्रकार की मांसपेशीय चोट होती है, जो ग्रोइन या निचले पेट के आसपास के मांसपेशियों, टेंडन या लिगामेंट्स को प्रभावित करती है। बीसीसीआई से मिली जानकारी के अनुसार, सर्जरी के करीब दो सप्ताह बाद सूर्यकुमार बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना रिहैबिलिटेशन शुरू करेंगे। यह सूर्यकुमार की पिछले तीन सालों में तीसरी सर्जरी है।

इससे पहले 2023 में उनके टखने की सर्जरी हुई थी और 2024 में उन्होंने इसी स्पोर्ट्स हर्निया का इलाज करवाया था। बावजूद इसके, उन्होंने हाल ही में आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए जबरदस्त प्रदर्शन किया और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया। सूर्यकुमार ने इस सीज़न में 717 रन बनाए, जो केवल ऑरेंज कैप विजेता साई सुदर्शन (759 रन) से पीछे थे। मुंबई इंडियंस प्लेऑफ तक पहुंची, लेकिन क्वालिफायर 2 में पंजाब किंग्स से हार गई। इसके बाद खेले गए टी20 मुंबई लीग में उन्होंने ट्रायम्फ नाइट्स मुंबई नॉर्थ ईस्ट की कप्तानी की और पांच पारियों में 122 रन बनाए। भारत का अगला सीमित ओवरों का दौरा अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ है, जिसमें तीन वनडे और तीन टी20 मुकाबले खेले जाएंगे। सूर्यकुमार के 26 अगस्त को चटगांव में होने वाले पहले टी20 मैच से टीम की अगुवाई करते हुए वापसी की उम्मीद है।

एफसी बार्सिलोना की कैंप नू में वापसी की तारीख तय, 10 अगस्त को होगा पहला मैच

एजेंसी

मैड्रिड। एफसी बार्सिलोना ने बुधवार को पुष्टि की कि क्लब दो वर्षों के लंबे इंतजार के बाद 10 अगस्त को अपने ऐतिहासिक स्टेडियम कैंप नू में वापसी करेगा। क्लब की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, बार्सिलोना पारंपरिक जोआन गैम्पर प्री-सीजन ओपनर इसी दिन कैंप नू में खेलेगा। पिछले दो वर्षों से कैंप नू में व्यापक पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण बार्सिलोना को अस्थायी रूप से लुईस कंपनी ओलंपिक स्टेडियम, मोंटजुइक में अपने घरेलू मुकाबले खेलने पड़े। हालांकि यह स्टेडियम प्रशंसकों के बीच ज्यादा लोकप्रिय नहीं रहा और लगभग 57,000 दर्शकों की क्षमता के बावजूद अक्सर खाली नजर आया। बार्सिलोना अब अपने पारंपरिक घर में लौट रहा है, हालांकि निर्माण कार्य अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं

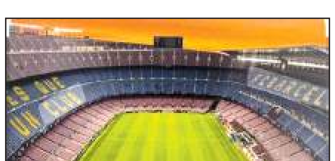

हुआ है। क्लब ने जानकारी दी कि, ''जिन हिस्सों पर अभी काम बाकी है उनमें शामिल हैं ऽ नया तीसरा स्टैंड, डबल वीआईपी रिंग, छत की स्थापना, कुछ आंतरिक हिस्सों की तैयारी और स्टेडियम के आसपास के क्षेत्र का पुनर्निर्माण। निर्माण कार्य जारी रहने के कारण 10 अगस्त को स्टेडियम की क्षमता लगभग 60,000 दर्शकों की होगी, जो कि 99,354 की अंतिम क्षमता से काफी कम है, लेकिन फिर भी जोआन गैम्पर मैच के लिए पहले अनुमानित 25,000 दर्शकों से कहीं अधिक है।

जिम्बाब्वे महिला टीम पहली बार खेलेगी आईसीसी महिला चैंपियनशिप, न्यूज़ीलैंड दौरे से होगा आगाज़

एजेंसी

हरारे। जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम इतिहास रचने के लिए तैयार है। पहली बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रही जिम्बाब्वे की टीम अगले साल फरवरी-मार्च 2026 में न्यूज़ीलैंड दौरे पर जाएगी, जहां वह तीन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी। यह मुकाबले जिम्बाब्वे की महिला चैंपियनशिप में आधिकारिक शुरुआत होंगे।

तीन वनडे मैच 5, 8 और 11 मार्च को डुनेडिन में खेले जाएंगे। इससे पहले दोनों टीमों के बीच तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच 25 फरवरी, 27 फरवरी और 1 मार्च को हैमिल्टन में होंगे। यह टी20 मुकाबले भी दोनों टीमों के बीच पहले आधिकारिक महिला टी20 मुकाबले होंगे। आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2025-29 चक्र में

जिम्बाब्वे की टीम को कुल आठ श्रृंखलाएं खेलनी हैं–चार घर में और चार विदेश में। जिम्बाब्वे घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी, जबकि विदेशी दौरे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूज़ीलैंड के होंगे। यह चैंपियनशिप 2029 में होने वाले महिला वनडे विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने का मुख्य रास्ता है। 2025-29 का यह चक्र आईसीसी महिला चैंपियनशिप का चौथा संस्करण है। जिम्बाब्वे की इस प्रतियोगिता में एंट्री के बाद अब इसमें 11 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अब तक जिम्बाब्वे महिला टीम ने छह टीमों के खिलाफ वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें से बांग्लादेश, आयरलैंड और पाकिस्तान आईसीसी के पूर्ण सदस्य हैं। जिम्बाब्वे क्रिकेट (जेडसी) के प्रबंध निदेशक गिवेमोर माकोनी ने एक आधिकारिक बयान में कहा, ''यह हमारे लिए गर्व और रोमांच का क्षण है कि जिम्बाब्वे महिला टीम अब वैश्विक स्तर पर शीर्ष क्रिकेट में कदम रख रही है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी महिला क्रिकेट कितनी आगे बढ़ी है और यह हमारे विजन और निवेश की भी पुष्टि करता है। जिम्बाब्वे के शामिल होने के साथ ही महिला चैंपियनशिप में अब आईसीसी के 12 में से 11 पूर्ण सदस्य देश हिस्सा ले रहे हैं। केवल अफगानिस्तान इस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं है, जहां अगस्त 2021 में तालिबान शासन के आने के बाद महिला क्रिकेट कार्यक्रम को बंद कर दिया गया था।

बोटाफोगो के अनुभवी डिफेंडर बास्टोस फीफा क्लब वर्ल्ड कप से बाहर

फिलाडेल्फिया। अनुभवी डिफेंडर बास्टोस को घुटने की पुरानी चोट दोबारा उभरने के कारण बोटाफोगो की फीफा क्लब वर्ल्ड कप टीम से बाहर कर दिया गया है। ब्राज़ीलियन क्लब ने बुधवार को यह जानकारी दी। 34 वर्षीय अंगोला अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बास्टोस ने सोमवार को एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ 1-0 से मिली हार में बतौर अनयूज़्ड सब्स्टीट्यूट टीम में जगह बनाई थी। वह फरवरी से चोट के कारण बाहर थे, लेकिन हाल ही में फिट होकर टीम में लौटे थे। हालांकि मैच के बाद उन्होंने घुटने में फिर से तकलीफ की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए ब्राज़ील भेजा जा रहा है। बोटाफोगो ने ग्रुप बी में दूसरा स्थान हासिल किया है और अब वह शनिवार को फिलाडेल्फिया में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अपने ब्राज़ीलियन प्रतिद्वंदी पल्मेरास से भिड़ेगा। बास्टोस, जिन्हें अंगोला के लिए 58 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का अनुभव है, ने 2023 में अल-अहली से बोटाफोगो में शामिल होने के बाद क्लब के लिए सभी प्रतियोगिताओं में 60 मैच खेले हैं।

डीपीआईआईटी ने पांच राज्यों में 11 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों की समीक्षा की

एजेंसी

नई दिल्ली। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने पांच राज्यों झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और नगालैंड में 11 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्रभावित करने वाले 18 मुद्दों की समीक्षा की है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने गुरुवार को जारी बयान में बताया कि डीपीआईआईटी के सचिव अमरदीप भाटिया की अध्यक्षता में 24 जून को हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और परियोजना प्रस्तावकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस समीक्षा बैठक में झारखंड राज्य में 11 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के 18 मुद्दों की समीक्षा की गई, जिसमें सभी परियोजनाओं की कुल लागत 34,213 करोड़ रुपये से अधिक है। मंत्रालय के मुताबिक बैठक में सिक्किम राज्य में 02 परियोजनाओं के 02 मुद्दों की समीक्षा की गई, जिसमें कुल 943.04 करोड़ रुपये की लागत है। नागालैंड राज्य में 02 परियोजनाओं के 03 मुद्दों की समीक्षा की गई, जिसमें कुल 544.65 करोड़ रुपये की लागत है। वहीं, असम राज्य में 01 मुद्दे और 01 परियोजना की समीक्षा की गई, जिसमें कुल 6,700 करोड़ रुपये की लागत है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश राज्?य में 01 निजी परियोजना सहित 03 परियोजनाओं के 07 मुद्दों की समीक्षा की गई, जिसमें कुल 33,469 करोड़ रुपये की लागत है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक झारखंड राज्य से संबंधित पतरातू थर्मल पावर स्टेशन विस्तार परियोजना के पहले चरण की व्यापक समीक्षा की गई। इसमें कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश में जियोएनप्रो पेट्रोलियम लिमिटेड की 1,000 करोड़ रुपये की लागत वाली निजी क्षेत्र की परियोजना से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा की गई। डीपीआईआईटी सचिव ने राज्य सरकार को मामले को उच्च प्राथमिकता देने तथा परियोजना से संबंधित मुद्दों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए जियोएनप्रो को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने की सलाह दी है। इसके अलावा बैठक में परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) द्वारा सुगमतापूर्वक केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य प्राधिकरणों और परियोजना समर्थकों के बीच घनिष्ठ सहयोग के जरिए महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने और परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिये आर्चर को लाने की हड़बड़ी नहीं करनी चाहिये : वॉन

एजेंसी

लंदन। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन का मानना है कि चोट से उबर रहे जोफ्रा आर्चर को भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में उतारने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये। आर्चर ने चार साल में पहला प्रथम श्रेणी मैच खेला जब वह डरहम के खिलाफ काउंटी चैम्पियनशिप में रविवार को ससेक्स के लिये उतरे। उन्होंने 18 ओवर में 32 रन देकर एक विकेट लिया। तीस वर्ष के आर्चर ने 2021 से कोई टेस्ट नहीं खेला है। इंग्लैंड के चयनकर्ता ल्यूक राइट ने इस महीने की शुरूआत में कहा था कि अगर आर्चर ससेक्स के लिये चार दिवसीय मैच खेलते हैं तो दो जुलाई से भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिये उपलब्ध होंगे। वॉन ने हालांकि 'बीबीसी टेस्ट मैच स्पेशल' में कहा,'' अच्छी बात यह है कि जोफ्रा ने वापसी की है लेकिन मैं उसे एक और चार दिवसीय मैच खेलते देखना चाहूंगा। उन्होंने कहा,'' उसने चार साल से इस प्रारूप में नहीं खेला है। इसलिये सिर्फ एक मैच के बाद उसकी वापसी कराना जल्दबाजी होगी। टेस्ट मैच काउंटी क्रिकेट से अलग होता है। मैं पहले टेस्ट की टीम में बदलाव नहीं करना चाहूंगा। ससेक्स के मुख्य कोच पॉल फारब्रास ने भी कहा कि आर्चर को लेकर इंग्लैंड को सावधानी बरतनी होगी। फारब्रास ने 'द गार्डियन' से कहा,'' अगर मैं चयनकर्ताओं की जगह होता तो ईमानदारी से कहूं तो आर्चर को तीसरे टेस्ट के लिये बचाता। आपको उसके मामले में सावधानी बरतनी होगी क्योंकि उसने लाल गेंद के प्रारूप में सिर्फ 18 ओवर डाले हैं। उन्होंने कहा,'' टीम में बदलाव की क्या जरूरत है। अभी हेडिंग्ले में पहला टेस्ट जीता है और श्रृंखला की शानदार शुरूआत की है।''

संक्षिप्त समाचार

शिखर धवन बने लेखक, अपने संस्मरण लिखे

नयी दिल्ली। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने अपने जीवन के संस्मरणों को कलमबद्ध किया है जिसमें रिश्तों से लेकर दोस्ती तक और मैदान के भीतर तथा बाहर के विवादों पर भी खुलकर बात की है। धवन ने अपनी किताब 'द वन : क्रिकेट, माय लाइफ एंड मोर' के बारे में कहा,'' क्रिकेट ने मुझे जीने का मकसद दिया लेकिन इस सफर में उतार चढाव और खामोश पल भी रहे। इसने मुझे वह इंसान बनाया जो आज मैं हूं। मैं दिल से अपनी कहानी कह रहा हूं जो ईमानदार और किसी फिल्टर के बिना है। प्रकाशक हार्पर कोलिंस इंडिया ने कहा,'' पूरी स्पष्टवादिता और ईमानदारी के साथ लिखी गई 'द वन' शिखर धवन के आंतरिक संवाद और उन सभी कमजोरियों की अभूतपूर्व झलक पेश करती है जिन्होंने उन्हें एक चैंपियन क्रिकेटर और संवेदनशील इंसान बनाया है। कंपनी के प्रकाशक सचिन शर्मा ने कहा,'' शिखर धवन का मैदान के भीतर और बाहर जीवन शानदार रहा है। इस संस्मरण में शिखर ने अपने जीवन, रिश्तों और हर उस अनुभव के बारे में बात की है जिसका उन्होंने सामना किया और मजबूत होकर निकले हैं। दिल्ली में पले बढे धवन ने बतौर विकेटकीपर शुरूआत की थी लेकिन बाद में सलामी बल्लेबाज बने। भारत के लिये 34 टेस्ट में उन्होंने 2315 रन, 167 वनडे में 6793 रन और 68 टी20 मैचों में 1759 रन बनाये हैं। उन्होंने किताब में लिखा,'' जब मैं भारतीय टीम में अपने की कोशिश कर रहा था तब सोशल मीडिया नया था और क्रिकेटरों पर इतनी नजर नहीं रखी जाती थी। लेकिन प्रिंट और प्रसारण मीडिया चरम पर था। उन्होंने लिखा,'' टीम चयन और व्यक्तिगत प्रदर्शन पर चर्चा होती थी और लोग पढते थे। आजकल की तरह नहीं जब सोशल मीडिया रातोरात क्रिकेटर को हीरो से जीरो बना देता है। धवन ने महेंद्र सिंह धोनी से पहली मुलाकात के बारे में लिखा है,'' मैं उसे एक बॉलीवुड मूवी में देखना चाहता था। वह फिल्म स्टार की तरह दिखता था। लंबे बाल और आकर्षक मुस्कान। हम आपस में बात कर रहे थे और मैने उससे कहा कि मैं भारत के लिये खेलना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम बॉलीवुड हीरो बनो। वह बहुत हंसने लगा।

विपुल ऑर्गेनिक्स जल उपचार के लिए 'मेमबरेन' निर्माण के क्षेत्र में उतरी

नयी दिल्ली। विशेष रसायन कंपनी विपुल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने वैश्विक जल उपचार बाजार का लाभ उठाने के लिए 'मेमबरेन' निर्माण में विस्तार करने की बृहस्पतिवार को घोषणा की। कंपनी ने कहा कि यह कदम टिकाऊ प्रौद्योगिकियों में रणनीतिक विविधीकरण को दर्शाता है। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनी मुख्य रूप से पिगमेंट और रंगों का काम करती है। कंपनी के प्रबंध निदेशक विपुल पी. शाह ने बयान में कहा, '' यह कदम विशेष रसायनों में हमारी मुख्य ताकत एवं शून्य-तरल निर्वहन प्रौद्योगिकियों के साथ हमारे अनुभव पर आधारित है। इस उद्यम की अगुवाई डॉ. वत्सल शाह करेंगे, जो प्रबंध निदेशक के पुत्र हैं। विपुल ऑर्गेनिक्स गुजरात के सैखा में अपनी नई परियोजना में एक अलग इकाई स्थापित कर रही है। यह 'मेमबरेन' विकास तथा उत्पादन पर केंद्रित एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करेगी।

शेल ने बीपी का अधिग्रहण करने के लिए बातचीत की खबरों का किया खंडन

लंदन। ब्रिटेन की तेल कंपनी शेल ने मीडिया की उन खबरों का बृहस्पतिवार को खंडन किया जिनमें उसके अपनी प्रतिद्वंद्वी कंपनी बीपी को खरीदने के लिए बातचीत करने का दावा किया गया था। अमेरिकी समाचार पत्र 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' ने बुधवार को मामले से परिचित लोगों के हवाले से कहा कि शेल, बीपी को खरीदने के लिए ''प्रारंभिक चरण की बातचीत'' कर रही है। शेल ने लंदन शेयर बाजार को भेजे बयान में कहा, '' हाल ही में मीडिया में जारी अटकलों के जवाब में शेल यह स्पष्ट करना चाहता है कि वह बीपी के लिए कोई प्रस्ताव देने पर सक्रिय रूप से विचार नहीं कर रहा है। यह भी पुष्टि करता है कि उसने बीपी से कोई संपर्क नहीं किया है और संभावित प्रस्ताव के संबंध में उसके साथ कोई बातचीत भी नहीं हुई है। शेल ने बार-बार इन अटकलों का खंडन किया है कि वह अपनी छोटी प्रतिद्वंद्वी कंपनी बीपी के अधिग्रहण पर विचार कर रही है। उसका कहना है कि वह अपने कारोबार को सुव्यवस्थित और सरल बनाने पर ध्यान दे रही है। गौरलतब है कि बीपी 2010 के 'डीपवाटर होराइजन' हादसे से अब भी उबरने की कोशिश कर रही है। इसमें 17 मजदूरों की मौत हो गई थी और कंपनी को इससे मेक्सिको की खाड़ी में हुए पर्यावरणीय नुकसान के लिए अरबों डॉलर का भुगतान करना पड़ा था।

देश के शीर्ष सात आवासीय बाजारों में अप्रैल-जून में कीमते 11 प्रतिशत बढ़ी, बिक्री 20 प्रतिशत घटी: एनारॉक

एजेंसी

नयी दिल्ली। देश के शीर्ष सात शहरों में अप्रैल-जून तिमाही में आवास की कीमते सालाना आधार पर 11 प्रतिशत बढ़ीं, जिससे बिक्री में 20 प्रतिशत की गिरावट आई है। रियल एस्टेट सलाहकार एनारॉक ने भारत के सात प्रमुख आवासीय बाजारों के आंकड़े बृहस्पतिवार को जारी किए। आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जून तिमाही में मकानों की बिक्री में 20 प्रतिशत की गिरावट आई। अप्रैल-जून तिमाही में इस साल 96,285 मकान बेचे गए जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 1,20,335 इकाइयों की बिक्री की गई थी। दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर), बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और कोलकाता में मकानों की बिक्री में गिरावट आई। चेन्नई में मांग में वृद्धि दर्ज की गई। एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा, '' 2025 की दूसरी (अप्रैल-जून) तिमाही भारतीय आवास बाजार के लिए उतार-चढ़ाव भरी रही। देश और विदेश में सैन्य कार्रवाइयां भी इसकी मुख्य वजह रही। युद्ध जैसे माहौल ने मकान खरीदने वालों को स्थिति आंकने और फिर फैसले करने की स्थिति में धकेल दिया, जिससे पिछले दो वर्ष में संपत्ति की कीमतों में उछाल का असर और बढ़ गया। उन्होंने कहा कि अब घरेलू तनाव कम होने और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की नीतिगत दर में कटौती से नए सिरे से उम्मीदें जगी हैं जिससे खरीदारों की धारणा में सुधार हो रहा है। एनारॉक के आंकड़ों के अनुसार, इस साल अप्रैल-जून में शीर्ष सात शहरों में औसत आवासीय कीमतों में सालाना 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एनसीआर में सबसे अधिक 27 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि देखी गई। इसके बाद बेंगलुरु में 12 प्रतिशत और हैदराबाद में 11 प्रतिशत की औसत मूल्य वृद्धि दर्ज की गई।

सर्राफा बाजार में गिरावट जारी सोना और चांदी की घटी कीमत

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में आज लगातार तीसरे दिन गिरावट का रुख बना हुआ है। सोने के भाव में आज 240 रुपये से लेकर 260 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की गिरावट आ गई। इसी तरह चांदी भी आज 900 रुपये प्रति किलोग्राम तक सस्ता हो गया है। भाव में कमजोरी आने के कारण आज देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 98,950 रुपये से लेकर 99,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 90,700 रुपये से लेकर 90,850 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। सोना की तरह ही चांदी के भाव में भी गिरावट आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 1,08,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बनी हुई है।

दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 99,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 90,850 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 98,950 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 90,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 99,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 90,750 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 98,950 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 90,700 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 98,950 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 90,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 99,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 90,850 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 99,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 90,750 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 99,100 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 90,850 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

सत्ता के मद के आगे प्रेस, न्यायपालिका को नहीं झुकना चाहिए : होसबाले

एजेंसी

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने आज कहा कि आपातकाल की 50 वर्षगांठ के मौके पर नयी पीढ़ी को यह सिखाने की जरूरत है कि सत्ता के मद और अहंकार में डूबे लोगों के समक्ष स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र पत्रकारिता को ना झुकना चाहिए और ना ही अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का समर्पण करना चाहिए।

श्री होसबाले ने गुरुवार को यहां डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केन्द्र में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर ओल्ड ब्वाॅज़ क्लब या एल्युमनी मीट बनाने से बचना चाहिए जहां लोग अपनी यादें ताज़ा करके लौट जाते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान पीढ़ी को अलग तरीके से बताना होगा कि मौलिक अधिकारों का हनन किस तरह से हुआ था। इसका विश्लेषण करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी तीन मोर्चों पर हारी थीं। अदालत में राजनारायण के केस में उनकी हार हुई थी। गुजरात विधानसभा चुनावों में जनता फ्रंट से कांग्रेस चुनाव हार गयी थी और तीसरी हार देश के विभिन्न भागों में जयप्रकाश नारायण के भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, चुनाव सुधार आदि मांगों के आंदोलन के कारण विपरीत जनमत बनना थी।

श्री होसबाले ने कहा कि इस लड़ाई को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ाया था। उन्होंने यह भी कहा कि आपातकाल को याद करने के साथ ही हमें यह भी याद करना चाहिए कि जनता के आंदोलन के कौन से मुद्दों को लेकर आपातकाल की नौबत आयी थी। उन्होंने कहा कि 50 साल के दौरान उन मुद्दों पर काम हुआ है। प्रशासनिक सुधार, चुनाव सुधार, शिक्षा नीति में बदलाव आदि ऐसे ही कुछ मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर आगे काम करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि देश में 1950 में गणतंत्र आया और संविधान लागू हुआ लेकिन 25 साल बाद ही इसे परीक्षा देनी पड़ी। गुलामी के कालखंड में एक बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि भारतीय लोग आज़ादी के हक़दार नहीं है। लेकिन आपातकाल में हमारे संघर्ष ने दिखा दिया कि हम लोकतंत्र और स्वतंत्रता की परीक्षा में जनसामान्य की चेतना और नौजवानों की ऊर्ज़ा के कारण विजयी रहे।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने उद्बोधन में आपातकाल के अपने संस्मरणों को साझा करते हुए कहा कि आपातकाल की लड़ाई को और उसमें बलिदान देने वालों को कभी भूलना नहीं चाहिए। उन्हीं के बलिदानों के कारण आज हमारा देश, देश की आजादी और लोकतंत्र बरकरार है। कुर्सी बचाने की जैसी निर्लज्जता आपातकाल में हुई वैसी आज की पीढ़ी कल्पना नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि उस समय विचार भिन्नता नहीं बल्कि विचार शून्यता उत्पन्न हो गयी थी। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला, चिंतक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आपातकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्री के एन गोविंदाचार्य, जाने माने पत्रकार पद्म भूषण डॉ. रामबहादुर राय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के सचिव डॉ सच्चिदानंद जोशी ने भी अपने विचार साझा किये। हिन्दुस्तान समाचार न्यूज़ एजेंसी के अध्यक्ष अरविंद मार्डीकर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

आपातकाल के दौरान अपनी सक्रिय भूमिका की स्मृतियों को साझा करते हुए पद्म भूषण डॉ. रामबहादुर राय ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ल्लहायरार्कीङ्क को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ल्लहोरीज़ोन्टल नेटवर्क' ने तोड़ दिया था तभी आपातकाल समाप्त हुआ था। इसके दो ही महानायक थे, एक- लोकनायक जय प्रकाश नारायण और दूसरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक बालासाहेब देवरस।

जल जीवन मिशन से 15 करोड़ घरों में पहुंचा नल से जल : पाटिल

एजेंसी

नयी दिल्ली। जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने गुरुवार को कहा कि जल जीवन मिशन के तहत अब तक 15 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है और शेष चार करोड़ घरों में इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए मिशन के तहत तेजी से काम चल रहा है और निर्धारित समय तक इसे पूरा कर लिया जाएगा।

श्री पाटिल ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नागरिकों को जल उपलब्ध कराना राज्य सरकारों का दायित्व है लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सबको जल उपलब्ध कराने के लिए मिशन के तहत काम कर रही है। इस मिशन के तहत अब तक 15 करोड़ घरों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है। शेष चार करोड घरों तक यह सुविधा पहुंचाने का काम चल रहा है और वर्ष 2028 तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय को 501 करोड़ रुपए से ज्यादा अनुदान मिला है जो अब तक का सबसे ज्यादा अनुदान है और उनका मंत्रालय इसके तहत सबको जल उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। उनका कहना था कि जो पैसा मंत्रालय को अनुदान के रूप में मिला है उसमें 67 करोड़ जल जीवन मिशन के लिए है। 'नमामी गंगे' योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके तहत मोदी सरकार ने जो काम किया है उसी का परिणाम है कि गंगा का पानी आज नहाने के लिए लायक हुआ है। प्रयागराज में जो महाकुंभ आयोजित किया गया उसमें श्रद्धालुओं को जो साफ पानी मिला उससे जाहिर है कि 'नमामी गंगे' के तहत गंगा को स्वच्छ बनाने का काम सफलतापूर्वक चल रहा है। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय जल संचय पर जोर दे रहा है और इसके लिए श्री मोदी ने लोगों से जनभागीदारी के तहत जल संचय का जो आह्वान किया था उसके परिणाम चौंकाने वाले हैं। सरकार ने कोई पैसा इस पर खर्च नहीं किया है लेकिन जल संचयन के लिए जो काम हुआ है वह असाधरण है। उन्होंने कहा कि इस काम में किस तेजी से जनता ने अपना योगदान दिया है।

शहरों में घर खरीदना गरीबों के बजट से कोसों दूर : राहुल

एजेंसी

नयी दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि महंगाई चरम पर है और शहरी अर्थव्यवस्था में गरीब तथा मध्यम वर्ग के लोगों के लिए घर खरीदना सपना बनकर रह गया है।

श्री गांधी ने सोशल मीडिया 'फ़ेसबुक' पर एक पोस्ट में आज कहा, हां, आपने सही पढ़ा - और अगर यकीन नहीं हो रहा तो दोहरा देता हूं-मुंबई में घर लेने के लिए भारत के सबसे अमीर पांच प्रतिशत लोगों को भी 109 साल तक अपनी आमदनी का 30 प्रतिशत बचाना पड़ेगा। यही हाल ज़्यादातर बड़े शहरों का है, जहां आप अवसर और सफलता की तलाश में एड़ियां घिस देते हैं। कहां से आएगी इतनी बचत। उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग की विरासत दौलत नहीं, जिम्मेदारियां होती हैं। बच्चों की महंगी शिक्षा,महंगे इलाज की चिंता, माता-पिता की ज़िम्मेदारी या परिवार के लिए छोटी-सी गाड़ी। फिर भी दिलों में रहता है एक सपना - 'एक दिन' एक घर होगा अपना। मगर जब वो 'एक दिन' अमीरों के लिए भी 109 साल दूर हो तो समझिए गरीबों से सपनों का भी हक़ छीन लिया गया है। श्री गांधी ने कहा कि हर परिवार की ज़रूरत है, सुकून वाली चारदीवारी और सर ढ़कने वाली छत- मगर अफसोस आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत और बचत से भी ज़्यादा है उसकी कीमत। अगली बार जब कोई आपको सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े सुनाए, तो उन्हें अपने घरेलू बजट की सच्चाई' दिखाएं - और पूछें, ये अर्थव्यवस्था किसके लिए है।

कांग्रेस ने महाराष्ट्र, हरियाणा की वोटर लिस्ट, वीडियो रिकार्डिंग मांगी

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदाताओं की सूची, मतदान के दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग तथा मशीन रीडेबल कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग सचिवालय के सचिव अश्विनी कुमार मोहल को 25 जून को लिखे दो पेज के पत्र में कहा है कि महाराष्ट्र तथा हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जिन सवालों को उठाया है उन्हें लेकर आयोग ने 12 जून को जो जवाब दिया है ,उसके मद्देनजर पार्टी मांग करती है कि उसे मतदाता सूची और मतदान के दिन के वीडियो फुटेज एक सप्ताह में उपलब्ध कराएं जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेजों के रखरखाव संबंधी दिशा-निर्देश किए जारी

एजेंसी

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने प्रशासनिक प्रबंधन खामियों को दूर किए जाने की दिशा में कदम उठाते हुए दस्तावेजों के रखरखाव और निपटान से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश गुरुवार को जारी किए। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने अपने संदेश में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने कई शाखाओं में आने वाले प्रशासनिक रिकॉर्ड की संख्या और विविधता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। उन्होंने कहा, ल्लजबकि मामले की कार्यवाही से संबंधित न्यायिक रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट रूल्स, 2013 के आदेश एलवीआई (56) में निहित स्पष्ट प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। भारत के शीर्ष न्यायालय के अभ्यास और कार्यालय प्रक्रिया की पुस्तिका, 2017 के अध्याय 21 में और विस्तार से बताया गया है। इसमें प्रशासनिक रिकॉर्ड के प्रबंधन के संबंध में एक कमी बनी हुई है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने जोर देकर कहा कि यह असमानता शाखाओं में असंगत प्रथाओं की ओर ले जाती है, जिससे अभिलेखीय स्पष्टता और दक्षता प्रभावित होती है। उन्होंने बताया कि 'रिकॉर्ड्स के संरक्षण और नष्ट के लिए दिशा-निर्देश 2025' का उद्देश्य संस्थागत निर्णयों, नीति कार्यान्वयन, अंतर-विभागीय पत्राचार, लेखा परीक्षा और बाहरी हितधारकों के साथ जुड़ाव सहित प्रशासनिक रिकॉर्ड के प्रबंधन में सुसंगतता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावा देकर इसे ठीक करना है।

उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए इन रिकॉर्डों को ठीक से प्रबंधित करने और एक तर्कसंगत ढांचा स्थापित करने के लिए दिशा-निर्देशों के महत्व को रेखांकित किया। दिशा-निर्देशों के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हस्ताक्षर वाले मूल सबमिशन नोट या पेपर बुक को स्थायी रूप से संरक्षित किया जाना शामिल है। इसके अलावा, नीति फाइलें, कार्यालय आदेश और परिपत्र फाइलें स्थायी रूप से संरक्षित की जानी थीं। उन्होंने कहा ल्लरिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की अवधि मध्यस्थता, मुकदमेबाजी, जांच या लेखा परीक्षा (जैसी भी स्थिति हो) की अंतिम कार्रवाई या निपटान के बाद शुरू होगी। संबंधित सभी शाखाएं फाइलों/मामलों/रिकॉर्ड को नष्ट करने से पहले यह सुनिश्चित करेंगी कि नष्ट/हटाई जा रही फाइलों/मामलों/रिकॉर्ड के विषय-वस्तु के संबंध में कोई अदालती मामला लंबित न हो। यदि किसी शाखा या विंग के रिकॉर्ड किसी दूसरी शाखा या गोपनीय शाखा से संबंधित रिकॉर्ड से सह-संबंधित हैं, तो ल्लअनुभाग में अदालती मामला प्राप्त होते ही अदालती मामले के लंबित होने की सूचना उन्हें भेजी जानी चाहिए। दिशा-निर्देश में कहा गया है कि संबंधित शाखाओं द्वारा रिकॉर्ड को नष्ट करना और रखना संबंधित रजिस्ट्रार से उचित अनुमोदन के बाद किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है, ल्लरिकॉर्ड को नष्ट करने की प्रक्रिया सामान्यतः गर्मी की छुट्टियों/आंशिक न्यायालय कार्य दिवसों के दौरान की जाती है। यदि दस्तावेजों/रिकॉर्ड की स्कैन की गई प्रति को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से विचार अवधि से परे संरक्षित किया जाना है।

अमरनाथ यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या में गिरावट : मनोज सिन्हा

एजेंसी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज कहा कि वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकृत तीर्थयात्रियों की संख्या में पिछले साल की तुलना में मामूली गिरावट देखी गई है। हालांकि अब स्थिति में सुधार के संकेत दिख रहे हैं।

उन्होंने यहां आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि तीर्थयात्रा के लिए सभी मार्गों और आधार शिविरों में जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। श्री सिन्हा ने कहा कि यात्रा के लिये 22 अप्रैल से पहले पंजीकरण में उछाल आया था लेकिन आतंकवादियों ने पहलगाम में इस दिन पर्यटकों को निशाना बनाया जिसमें 26 लोग मारे गए। श्री सिन्हा ने कहा कि 22 अप्रैल के बाद पंजीकरण में थोड़ी गिरावट देखी गई। इस साल के आंकड़ों की तुलना 2024 से करते हुए उपराज्यपाल ने खुलासा किया कि इस बार अब तक 35,000 से 40,000 कम तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा ''मेरा मानना है कि कुल संख्या पिछले साल की तुलना में 10.19% कम है।'' उन्होंने कहा कि गिरावट के बावजूद प्रशासन इस बाबत 'आशावादी' है क्योंकि स्थिति में सुधार है।उन्होंने कहा ''22 अप्रैल तक यात्रा के लिये 2,36,801 पंजीकरण किए गए थे। हमने 22 अप्रैल से पहले पंजीकरण कराने वाले सभी लोगों से संपर्क किया और उनसे यात्रा में भाग लेने की पुष्टि करने के लिए कहा। अब तक 85,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने आने की पुष्टि की है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है।''

सुरक्षा के मसले पर उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया कि इस बाबत व्यापक व्यवस्था की गई है और पिछले वर्षों की तुलना में सुरक्षा कर्मियों का संख्याबल भी अधिक है। उन्होंने कहा ''सुरक्षा के दृष्टिकोण से जम्मू- कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और केन्द्रीय सुरक्षा बलों ने सभी यात्रा मार्गों और आधार शिविरों में सुरक्षित और शांतिपूर्ण तीर्थयात्रा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं।''

श्री सिन्हा ने कहा कि अमरनाथ यात्रा 2025 के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए मजबूत और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा ''चाहे वह क्षेत्र वर्चस्व हो, माउंटेन रेस्क्यू पेट्रोल (एमआरपी) की तैनाती हो, या आधार शिविरों पर तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था हो, सब कुछ पुख्ता तौर पर मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में पुलिस अधिकारियों और केन्द्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, ''मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सुरक्षाबलों ने अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने बताया कि यात्रा के मद्देनजर प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा ''यात्रा से जुड़े हर व्यक्ति-खासकर सेवा प्रदाताओं-का पूरी तरह से सत्यापन किया गया है।'' उन्होंने बताया कि तीन साल पहले शुरू की गई आरएफआईडी आधारित ट्रैकिंग प्रणाली सभी तीर्थयात्रियों और सेवा प्रदाताओं के लिए है। उन्होंने कहा ''ईकेवाईसी सत्यापन के बाद आरएफआईडी कार्ड जारी किए जाते हैं। हाई-डेफिनिशन कैमरे और अत्याधुनिक कमांड और कंट्रोल सेंटर यात्रा की 24़7 निगरानी कर रहे हैं।'' उन्होंने बताया कि बालटाल और चंदनवारी-पहलगाम मार्गों को चार-पांच फीट से बढ़ाकर 12 फीट कर दिया गया है जिससे तीर्थयात्रियों के लिए मार्ग सुरक्षित हो गए हैं। श्री सिन्हा ने कहा कि इस साल अमरनाथ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं संचालित नहीं होंगी। उन्होंने कि इस निर्णय के पीछे कई मूलभूत कारण हैं। उन्होंने कहा ''विभिन्न कारणों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि इस साल हेलीकाप्टर सेवाएं निलंबित रहेंगी।'' तीर्थयात्रा में शामिल सभी हितधारकों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि तीर्थयात्रियों, टट्टू मालिकों और कुलियों के लिए बीमा कवरेज की व्यवस्था श्राइन बोर्ड और प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। उन्होंने कहा ''इस साल सभी तीर्थयात्रियों और सेवा प्रदाताओं की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उनका बीमा किया गया है।'' स्थानीय लोगों की भूमिका की सराहना करते हुए उन्होंने कहा '' यात्रियों के प्रति कश्मीर के लोगों की गर्मजोशी और उनका आतिथ्य पूरे देश में बेजोड़ है

नीट-यूजी 2025 : सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली हाई कोर्ट से मामला स्थानांतरित करने से इनकार

एजेंसी

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2025 को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर विचार करने से गुरुवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एन के सिंह की पीठ ने असद खत्री की गुहार ठुकराते हुए कहा कि यह याचिका सार्वजनिक हित के तथ्यों पर आधारित नहीं है और इसलिए इस विवाद का शीर्ष अदालत की बजाय उच्च न्यायालय में ही निपटारा किया जाना चाहिए। पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई इस चिंता पर विचार करते हुए कि जुलाई के मध्य तक सीटें (मेडिकल स्नातक की) भर जाएंगी,उन्हें सुनवाई आगे बढ़ाने की अनुमति दी। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मामले को 31 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है।पीठ ने याचिकाकर्ता की चिंता और तात्कालिक महत्व को देखते हुए संभावित शीघ्र सुनवाई के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इसका उल्लेख करने की याचिकाकर्ता को अनुमति दी।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता सुभाष झा ने इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित याचिका को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। इस पर न्यायमूर्ति विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वर्तमान याचिका? व्यक्तिगत तथ्यों पर आधारित है। इसमें किसी कानून की वैधता को चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए यह मामला शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने योग्य नहीं है।

पेज एक का शेष

शांति-समृद्धि और...

कार्रवाई की आवश्यकता है और हमें अपनी सामूहिक सुरक्षा के लिए इन बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि अपने संकीर्ण एवं स्वार्थी उद्देश्यों के लिए आतंकवाद को प्रायोजित, पोषित व इस्तेमाल करने वालों को इसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने में दोहरे मानदंडों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सिंह ने कहा कि एससीओ को इस खतरे से निपटने में दोहरे मानदंड अपनाने वाले देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए। सिंह ने यह भी कहा कि पहलगाम आतंकी हमले का तरीका भारत में लश्कर-ए-तैयबा के पिछले आतंकी हमलों जैसा था। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपना रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भारत अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के समर्थन में अपनी नीति पर अडिग रहा है।

हिंदी भारतीय...

में अंकित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा होती है। हमारी जड़ें, परंपराएं, इतिहास, पहचान और जीवन संस्कृति भाषा से कटकर आगे नहीं बढ़ सकते इसलिए भाषाओं को जीवंत रखना और समृद्ध करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हमें आने वाले दिनों में सभी भारतीय भाषाओं और विशेषकर राजभाषा के लिए ये सभी प्रयास करने चाहिएं। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विगत 11 साल में एक भारत, श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरूआत की है और इसके तहत काशी-तमिल संगमम, काशी-तेलुगू संगमम, सौराष्ट्र-तमिल संगमम, शाश्वत मिथिला महोत्सव और भाषा संगम ने देश की एकता को मज़बूत करने का एक बहुत अच्छा मंच प्रदान किया है। भाषा संगमम की पहल पर हर स्कूल में छात्रों को बोलचाल के 100 वाक्य संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में सिखाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और यह पहल आने वाले दिनों में भारतीय भाषाओं की संजीवनी बन कर एक वट वृक्ष के रूप में आगे बढ़ेगी।

वैवाहिक मामलों में मध्यस्थता...

कि वे साथ रहें...। उच्चतम न्यायालय ने वाणिज्यिक अदालतें अधिनियम, 2015 का उल्लेख किया, जिसमें मुकदमा दायर करने से पहले मध्यस्थता और समाधान की प्रक्रिया का प्रावधान है। पीठ ने कहा, ''वाणिज्यिक अदालतें अधिनियम में भी आपको इस प्रक्रिया से गुजरना होता है।

चुनाव आयोग ने 345...

कि कोई भी पार्टी अनुचित रूप से सूची से बाहर न हो जाए, संबंधित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव अधिकारियों को ऐसे दलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा गया है और ऐसे दलों को सुनवाई के लिए एक मौका दिया जाएगा। आयोग ने कहा है कि उसने यह कदम ऐसी पार्टियों को सूची से हटाने के उद्देश्य से किया है, जिन्होंने 2019 के बाद से कोई भी लोकसभा या राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा या उपचुनाव नहीं लड़ा है और जिन्हें भौतिक रूप से भी नहीं पहचाना जा सका है। इस प्रक्रिया में पहले चरण में इन 345 दलों की पहचान की गई है।

सीवीआर-एफडीआर...

इस तरह की जांच के लिए आवश्यक निर्माण और डिजाइन राज्य (यूएसए) से सरकारी जांच एजेंसी है। बयान के अनुसार दुर्घटनास्थल से सीवीआर और एफडीआर क्रमशः 13 जून को दुर्घटना स्थल पर इमारत की छत से और 16 जून को मलबे से बरामद किया गया था। उनके सुरक्षित संचालन, भंडारण और परिवहन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं पूरी की गईं। इन उपकरणों को अहमदाबाद में कड़ी पुलिस सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी में रखा गया था। इसके बाद, 24 जून को पूरी सुरक्षा के साथ वायुसेना के विमानों द्वारा ब्लैक बॉक्स को अहमदाबाद से दिल्ली लाया गया। फ्रंट ब्लैक बॉक्स 24 जून को दो बजे एएआईबी महानिदेशक के साथ दिल्ली के एएआईबी लैब पहुंचाया गया। रियर ब्लैक बॉक्स को दूसरी एएआईबी टीम द्वारा लाया गया था और 24 जून को शाम 1715 बजे एएआईबी लैब, दिल्ली लाया गया था। बयान में कहा गया कि 24 जून की शाम को, एएआईबी के महानिदेशक के नेतृत्व में एएआईबी और एनटीएसबी के तकनीकी सदस्यों के साथ टीम ने डेटा निष्कर्षण प्रक्रिया शुरू की। सामने के ब्लैक बॉक्स से क्रैश प्रोटेक्शन मॉड्यूल (सीपीएम) को सुरक्षित रूप से पुनर्प्राप्त किया गया और 25 जून को मेमोरी मॉड्यूल को सफलतापूर्वक एक्सेस किया गया था और इसका डाटा एएआईबी लैब में डाउनलोड किया गया था। नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार सीवीआर और एफडीआर डाटा का विश्लेषण जारी है। इन प्रयासों का उद्देश्य दुर्घटना की ओर ले जाने वाली घटनाओं के क्रम को फिर से समझना और विमानन सुरक्षा को बढ़ाने और भविष्य की घटनाओं को रोकने में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करना है। मंत्रालय ने कहा कि सभी कार्रवाई घरेलू कानूनों और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के पूर्ण अनुपालन में समयबद्ध तरीके से की गई हैं।

डाटा सेंटर और ग्रीन...

बन रहे हैं। कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइल का उपयोग हाल ही में पाकिस्तान पर किया गया। हम कह सकते हैं कि इन दोनों मिसाइलों की क्षमता को पाकिस्तान में टेस्टेड और दुनिया में ट्रस्टेड किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने सीईएल के विकास को उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर से जोड़ा। उन्होंने बताया कि पिछले 8 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था ढाई गुना बढ़ी है, 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है और अब निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि 2017 में प्रदेश बीमारू की छवि से जूझ रहा था, लेकिन आज यह देश का ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों में से 15 लाख करोड़ के निवेश को ग्राउंड ब्रेकिंग के जरिए प्रोडक्शन से जोड़ा गया है। सीईएल की यात्रा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, आपका बचपन अच्छा था, जवानी में कुछ भटकाव आया, लेकिन अब आपका अमृत काल शुरू हो चुका है। यह आने वाले 25 वर्ष भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए समर्पण का समय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बार-बार यह संदेश देते हैं कि इंस्टीट्यूट्स को इंडस्ट्री से जोड़ना चाहिए और उत्तर प्रदेश के पास इसके लिए आईआईटी, आईआईएम, विश्वविद्यालय और केंद्रीय प्रयोगशालाओं के रूप में उत्कृष्ट संस्थान मौजूद हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीईएल का अपना एक इतिहास है। इस संस्थान ने 1970 में पहले सोलर सेल को ईजाद किया था। आज 50 साल बाद अब यह ग्रीन डाटा सेंटर भी शुरू करने जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए आपका नाम इतिहास में दर्ज हो गया और मुझे खुशी है कि मेरे मंत्रालय के दो संस्थाओं ने भी उसमें अपना योगदान किया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम नोएडा में आईआईटी के अंदर देश का पहला क्वांटम यूनिट स्थापित करेंगे। इसके साथ ही, लखनऊ के नजदीक बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करेंगे और अगस्त में दो या तीन दिवसीय एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव आयोजित करने की भी योजना बना रहे हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) एक मिनी रत्न सीपीएसई है, जो भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) के अंतर्गत कार्य करता है। सीईए के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक चेतन प्रकाश जैन ने बताया कि इस ग्रीन डेटा सेंटर को ऊर्जा की कम खपत करने वाला, पूरी तरह सुरक्षित और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए तैयार डिजाइन किया गया है। ईएसडीएस के साथ साझेदारी के माध्यम से सीईएल आधुनिक क्लाउड और डेटा सेंटर टेक्नोलॉजी को संवहनीयता के साथ जोड़ रहा है। यह केंद्र मॉड्यूलर घ्क्म, स्मार्ट कूलिंग, रिफ्लेक्टिव रूफिंग, वर्षा जल संचयन और मल्टी-आईएसपी सपोर्ट जैसी सुविधाओं से युक्त होगा, जिसकी कुल क्षमता 30 मेगावाट है और प्रत्येक मंजिल पर 200 रैक तक विस्तार संभव होगा। ईएसडीएस की पेटेंट टेक्नोलॉजी और प्रबंधित सेवाएं इस केंद्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने में सहायक रही हैं। कंपनी के सीएमडी एवं सीईओ पीयूष सोमानी ने बताया कि यह डेटा सेंटर टियर ऋऋ/ढ्ढ/अपटाइम मानकों के अनुरूप है और इसे हर फ्लोर पर 200 हाई-डेंसिटी रैक, 30 मेगावाट की क्षमता और 40 क्वध्य कनेक्टिविटी के लिए तैयार किया गया है। यह परियोजना डिजिटल इंडिया और ग्रीन इंडिया जैसे राष्ट्रीय अभियानों को मजबूती प्रदान करेगी।

पंजाब कैबिनेट ने दी औद्योगिक प्लॉट हस्तांतरण नीति को मंजूरी

■ औद्योगिक प्लॉटों को अस्पतालों, होटलों, औद्योगिक पार्कों के लिए उपयोग की अनुमति

कैनविज टाइम्स संवाददाता

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने औद्योगिक प्लॉटों को अस्पतालों, होटलों, औद्योगिक पार्कों और अन्य स्वीकृत मदों के लिए उपयोग की अनुमति देने वाली पंजाब की हस्तांतरण नीति में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दे दी। इस संबंध में फैसला गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि पहले हस्तांतरण नीति 2008, 2016 और 2021 में लाई गई थी। औद्योगिक संगठनों ने 2021 में लाई गई नीति की कुछ प्रतिबंधात्मक शर्तों पर आपत्ति जताई थी। इसके जवाब में एक कमेटी ने उद्यमियों की मांगों की समीक्षा की और फ्री होल्ड प्लॉटों पर लागू होने वाले परिवर्तनों का प्रस्ताव दिया। संशोधित नीति के अनुसार औद्योगिक प्लॉट की आरक्षित कीमत का 12.5 प्रतिशत हस्तांतरण शुल्क लागू होगा। कैबिनेट ने विशेष रूप से पीएसआईईसी के प्रबंधन वाले लीजहोल्ड औद्योगिक प्लॉटों और शेड्स को फ्री होल्ड में बदलने की नीति को भी मंजूरी दे दी। ये प्लॉट और शेड मूल रूप से लीजहोल्ड आधार पर आवंटित किए गए थे, जिनमें परिवर्तन संबंधी जटिल धाराएँ शामिल थीं, जिसके कारण संपत्ति के लेन-देन में कठिनाइयां आ रही थी। इस नई नीति का उद्देश्य औद्योगिक प्लॉटों के प्रबंधन को सुचारू करना, कारोबार में सुगमता बढ़ाना, आवंटियों के बीच मुकदमेबाजी और अनिश्चितता को कम करना है। इसके अलावा, इस हस्तांतरण से राज्य के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है। कैबिनेट ने एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट, 2006 के तहत एमएसई फैसिलिटेशन काउंसिल नियम-2021 में संशोधनों को मंजूरी दे दी। वर्तमान में जिला स्तर पर माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल संबंधित डिप्टी कमिश्नरों के नेतृत्व में काम कर रही हैं। हालांकि, इस एक्ट के तहत अवार्ड्स से संबंधित भुगतानों में देरी हो रही है।

भगवंत मान का ऐलान- नशा तस्करों पर तेज होगी कार्रवाई, किसी को बख्शा नहीं जाएगा

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नशा तस्करों के खिलाफ चल रही कार्रवाई को और तेज करने का ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चाहे कितनी भी बड़ी पहुंच हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने परोक्ष रूप से कहा कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े तस्कर जेल जाएंगे और अवैध संपत्तियां ध्वस्त की जाएंगी। अकाली नेता बिक्रमजीत मजीठिया की गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को पंजाब में अकाली कार्यकर्ताओं ने दिन भर हंगामा किया गया।इस बीच चंडीगढ़ में गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में भगवंत मान ने कहा कि कई महीनों से युद्ध स्तर पर नशा विरोधी अभियान चल रहा है। पंचायतें फतवे जारी कर रही हैं कि नशे के साथ पकड़े जाने वालों का साथ नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बुरी संगत में पड़े लोगों का री-हैब सेंटर में इलाज कराया जाएगा। मान ने कहा कि जो लोग दूसरों के घर उजाडक़र अपने महल बना रहे थे, उन पर बुलडोजर चलाया गया है। सीएम ने कहा कि हम पहले ही कह रहे थे कि सबूत आने दो, बड़ों की बारी भी आएगी। कोई आपने दिल में गलतफहमी ना रखें। सीएम भगवंत मान ने कहा कि समय थोड़ा लग गया, क्योंकि प्लानिंग को टाइम लगता है। अगर सप्लाई लाइन तो तोड़ देंगे, लेकिन जो आदी है उनका क्या करेंगे। उनके लिए रिहैब बनाए गए। सीएम ने कहा कि पुलिस वालों के कारण हमारे छापे फ़ेल हुए हैं। वह फोन कर तस्करों को पहले बता देते थे। इसलिए उनकी ट्रांसफर की गईं। लोगों से सहयोग मांगा गया। इसलिए ये जो मुहिम है, अब पूरा जोर पकड़ चुकी है। सीएम ने कहा कि अब बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है, अब फोन आते हैं। अब जब पुलिस गई तो पता चलता है कि वे अपने घर छोड़ भाग चुके हैं। हम कहते रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो कितना भी स्ट्रांग है, बड़ा अधिकारी को वो जानता है। सीएम ने कहा कि पंजाब को नशा मुक्त बनाना है। कोई अपने दिल में गलतफहमी न रखें कि किसी की बहुत चलती है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें कोई डर नहीं है।

दान की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर निगम ने 'दान उत्सव' का आयोजन किया

कैनिवज टाइम्स संवाददाता

फगवाड़ा। पंजाब के फगवाडा में नागरिक एकजुटता और सामाजिक जिम्मेदारी के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में नगर निगम फगवाड़ा ने गुरुवार को दान उत्सव के दो दिवसीय समारोह का समापन किया। यह उत्सव दान देने की भावना को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। महापौर रामपाल उप्पल और नगर निगम फगवाड़ा की आयुक्त डॉ. अक्षिता गुप्ता के दूरदर्शी नेतृत्व में स्थानीय कल्याण संगठनों और सार्वजनिक सेवा विभागों के सक्रिय सहयोग से आयोजित किया गया था। नगर निगम पुस्तकालय, हरगोबिंद नगर में ब्लड बैंक और हाकुपुरा (हदियाबाद) में आरआरआर (रिड्यूस-रीयूज-रीसाइकिल) केंद्रों सहित प्रमुख स्थानों पर आयोजित इस समारोह में निवासियों और स्वयंसेवकों ने समान रूप से उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस पहल का उद्देश्य न केवल नागरिकों के बीच धर्मार्थ कार्यों को प्रोत्साहित करना था, बल्कि फगवाड़ा में उदारता, स्थिरता और सामुदायिक सेवा की दीर्घकालिक संस्कृति को बढ़ावा देना भी था। श्री उप्पल ने एक दयालु और लचीले समाज के निर्माण में सामुदायिक भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ल्दान उत्सव जैसे कार्यक्रम हमें याद दिलाते हैं कि सामाजिक जिम्मेदारी नागरिक जीवन के मूल में है। समुदाय को वापस देने से हमें एक साथ बढ़ने में मदद मिलती है। आयुक्त डॉ. अक्षिता गुप्ता ने अभियान के व्यापक उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा की और समावेशिता तथा स्थिरता पर इसके फोकस पर जोर दिया। उन्होंने कहा, दान उत्सव केवल एक त्यौहार नहीं है, बल्कि नागरिक चेतना को फिर से जगाने का एक आंदोलन है। आरआरआर केंद्रों जैसी पहलों के माध्यम से, हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अप्रयुक्त लेकिन उपयोगी संसाधन उन लोगों तक पहुँचें जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है, जिससे अपव्यय कम हो और सहानुभूति को बढ़ावा मिले।

समस्तीपुर में आम उत्पादन परम्परागत रूप से बहुत पहले से ही किया जाता रहा है: डॉ आर के तिवारी

कैनविज टाइम्स संवाददाता

समस्तीपुर। डॉ राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र बिरौली के द्वारा आम उत्पादकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन आम उत्पादन की उन्नत पद्धति विषय पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कृषि विज्ञान केन्द्र बिरौली के वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान डॉ आरके तिवारी तथा सहायक निदेशक उद्यान प्रशांत कुमार के द्वारा किया गया। डॉ तिवारी ने मौके पर कहा कि समस्तीपुर में आम उत्पादन परम्परागत रूप से बहुत पहले से ही किया जाता रहा है। किसानों को आधुनिक तरीके से बाग प्रबंधन करते हुए अधिक आय प्राप्त किया जा सकता है। सहायक निदेशक उद्यान ने उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आम उत्पादक किसान पैक हाउस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान उद्यानिकी विशेषज्ञ डॉ धीरु कुमार तिवारी ने विस्तार पूर्वक आम के बाग में छत्रक प्रबंधन, पोषक तत्व प्रबंधन तथा बाग की मिट्टी का स्वास्थ्य प्रबंधन पर चर्चा किया। डॉ धीरु ने कहा कि आम के फल की तुड़ाई हो जाने के पश्चात पेड़ की बीच वाली ऊपरी टहनी को काटकर हटा देना चाहिए जिससे कि छत्रक खुल जाए। ऐसा करने से सूर्य की रौशनी तथा हवा का संचार पूरे पेड़ में होने लगता है। सूखी हुई या रोगग्रस्त तथा अधिक घनी टहनियों की भी कटाई छंटाई करनी चाहिए। फसल सुरक्षा विशेषज्ञ सुमित कुमार सिंह ने आम में लगने वाली बिमारियों एवं कीटों के नियंत्रण हेतु समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। डॉ राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कृषि व्यवसाय एवं प्रबंधन के सहायक प्राध्यापक डॉ रमनदीप सिंह ने आम की फसल से अच्छी आमदनी लेने हेतु रणनीतियों के बारे में चर्चा किया। उन्होंने बताया कि आम उत्पादक किसान समूह बनाकर अपनी उपज का विपणन कर सकते हैं जिससे उन्हें अधिक लाभ मिल सकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान छत्रक प्रबंधन तथा पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में प्रायोगिक रुप से भी जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विपिन सिंह, अमर नाथ सिंह, प्रदीप महतो इत्यादि उपस्थित रहे।

प्रवासी बिहारियों के लिए नीतीश सरकार पर्व-त्योहार पर चलायेगी 299 बसें

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री लगातार जन सरोकार से जुड़े फैसले लेते जा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में तीन गुणा बढ़ोतरी के बाद, सीएम ने आज राज्यवासियों को एक और सौगात दी है। सरकार ने पर्व-त्योहारों के दौरान घर लौटने वाले प्रवासी बिहारियों की सुविधा के लिए 299 बस चलाने का निर्णय किया है। नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। मुख्यामंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा है कि ''बिहार के लोग विभिन्न पर्व-त्योहारों खासकर छठ, होली, दीपावली एवं दुर्गा पूजा के अवसर पर काफी संख्या में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल से घर आते हैं। पर्व-त्योहारों के अवसर पर बिहार आने में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिहार आने वाले लोगों की यात्रा को सुगम बनाने तथा उनकी सहूलियत के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है।

बिहार ग्रामीण बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों का महा धरना

कैनविज टाइम्स संवाददाता

नवादा। नवादा के मंगर बीघा मोड पर अवस्थित बिहार ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के निकट गुरुवार को बैंक के क्षेत्रीय पदाधिकारी के मनमानी तथा गुंडों जैसा व्यवहार से नाराज बैंक के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने एकदिवसीय धरना देकर कार्रवाई नहीं किए जाने के विरुद्ध अनिश्चित आंदोलन के भी चेतावनी दी है।

कर्मचारियों तथा अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्रीय अधिकारी बैंक बुलाकर अधिकारियों तथा कर्मचारियों को गालियां देते हुए सी आर बर्बाद कर देने की चेतावनी देते हैं। बार-बार नौकरी से भी बाहर निकालने की बात करते हैं जो उनके मनमानी तथा लाल फीताशाही रवैया का परिचायक है। नवादा तथा शेखपुरा जिले के बिहार ग्रामीण बैंक के सभी शाखों के प्रबंधक से लेकर सभी अधिकारी तथा कर्मचारियों ने धरना देकर क्षेत्रीय प्रबंधक के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए सर्वोच्च अधिकारी से कार्रवाई की मांग की। धरना पर बैंक अधिकारी शशि शेखर कुमार, अविनाश कुमार ,अक्षय कुमार ,राजेश कुमार ,भानु प्रताप के नेतृत्व में अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने क्षेत्रीय पदाधिकारी के विरोध में नारेबाजी की। धरना पर सेंट्रल कमिटी पटना के अधिकारी महासचिव नदीम अख्तर, सुमन कुमार ,लोकेश चंद्र सिंह, रवि रंजन कुमार ,कर्मचारी संघ के महासचिव कुंदन कुमार राय, बैंकर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह, महासचिव प्रमोद कुमार आदि ने कहा कि यह लड़ाई क्षेत्रीय पदाधिकारी को एक चेतावनी मात्र है। अगर इनके रवैया में सुधार नहीं हुआ तो बैंक की स्थिति विरोध के कारण खराब होगी।जिसके लिए वे ही जिम्मेदार होंगे। वेअधिकारी व कर्मचारी को प्रताड़ित करते रहते हैं जो एक गंभीर मामला है।

अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को 7 दिन की पुलिस रिमांड

चंडीगढ़। आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को विजिलेंस ब्यूरो ने गुरुवार को मोहाली की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। मजीठिया की अदालत में पेशी के दौरान अकाली दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मजीठिया के अदालत पहुंचने से पहले बड़ी संख्या में अकाली दल के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। इनमें कई पूर्व मंत्री भी शामिल थे। बुधवार रात मजीठिया के वकीलों ने कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद एक घंटे तक उनसे मुलाकात की थी। वकीलों ने कहा कि जिस रिपोर्ट को आधार बनाकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया, उसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। विजिलेंस ने मजीठिया पर आय से अधिक संपत्ति बनाने का केस दर्ज किया है। उन पर 540 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति का आरोप है। टीम इस मामले की पड़ताल कर रही है।

मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशा मुक्त दिल्ली व भारत के निर्माण का संकल्प दिलाया

कैनविज टाइम्स संवाददाता

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर युवाओं को नशे से दूर रहने, समाज को जागरूक करने और नशा मुक्त दिल्ली व भारत के निर्माण का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह, विधायक ओम प्रकाश शर्मा, संजय गोयल एवं डॉ. अनिल गोयल मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि परिवार की एकता और समाज की बुनियाद को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। हमारा उद्देश्य है कि दिल्ली की युवाशक्ति अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण, समाज सेवा और सकारात्मक परिवर्तन में लगाए, यही हमारी सरकार का मूल संकल्प है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिया गया ल्नशा मुक्त भारतङ्क का संकल्प आज पूरे देश में जन-आंदोलन बन चुका है। इस अभियान को मजबूती से आगे बढ़ाने में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का सक्रिय मार्गदर्शन और सशक्त प्रशासनिक नेतृत्व अत्यंत प्रेरणादायक है। दिल्ली सरकार इस राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्यरत है। दिल्ली पुलिस द्वारा संचालित यह जन-जागरूकता अभियान सराहनीय है और दिल्ली सरकार इसमें कंधे से कंधा मिलाकर संकल्पबद्ध रूप से सहभागी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर एक नशा मुक्त, जागरूक और सशक्त दिल्ली के निर्माण में सहभागी बनें।

नौ जुलाई को देशव्यापी हड़ताल के तहत संयुक्त रोष प्रदर्शन करने का एलान

कैनविज टाइम्स संवाददाता

लुधियाना। पंजाब की औद्योगिक नगरी लुधियाना के विभिन्न मजदूर-कर्मचारी संगठनों ने गुरुवार को घोषणा की कि वह केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संघों की आगामी नौ जुलाई की राष्ट्रीय हड़ताल में शामिल होंगे और लुधियाना के समराला चौक पर प्रदर्शन करेंगे। यह घोषणा पंजाबी भवन में विभिन्न मजदूर यूनियनों की बैठक के बाद आज की गई। बैठक में कारखाना मजदूर यूनियन के अध्यक्ष लखविंदर, इंकलाबी मजदूर केंद्र (मासा) के अध्यक्ष सुरिंदर सिंह, मोल्डर एंड स्टील वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह, टेक्सटाइल-हौजरी कामगार यूनियन के अध्यक्ष जगदीश सिंह और मोल्डर एंड स्टील वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष विजय नारायण मौजूद थे। बताया गया कि उनके अलावा रोष प्रदर्शन में क्रांतिकारी मजदूर केंद्र, लोक एकता संगठन, पेंडू मजदूर यूनियन (मशाल) और अन्य संगठन भी शामिल होंगे। टेक्सटाइल हौजरी कामगार यूनियन के अध्यक्ष जगदीश सिंह ने बाद में मीडिया को जारी बयान में आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकारों की 'जनविरोधी' और 'देशी-विदेशी पूंजीपतियों' की पक्षधर आर्थिक-राजनीतिक नीतियों ने मजदूरों और अन्य सभी मेहनतकशों की हालत बद से बदतर बना दी है। गरीबी-महंगाई ने लोगों का कचूमर निकाल दिया है। मामूली से कानूनी श्रम अधिकार भी मजदूर वर्ग को हासिल नहीं हो पा रहे थे, ऊपर से सरकारों ने श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन करके पूंजीपतियों को लूट की और खुली छूट दे दी है।

पूल्ड आवासों के रखरखाव में कोताही बर्दाश्त नहीं: सीडीओ

कैनविज टाइम्स संवाददाता

हरिद्वार। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे ने पूल्ड आवास कालोनी रोशनाबाद के आवासों एवं जिला मुख्यालय के रखरखाव के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये कि पूल्ड आवास कालोनी के आवासों के रखरखाव में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। पूल्ड आवासों के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा दिये जाने वाले प्रार्थना पत्रों, रजिस्टर में दर्ज शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि पूल्ड आवास कालोनी की सुरक्षा के दृष्टिगत सीसीटीवी कैमरा आदि लगवाये जायें। सीसीटीवी कैमरा का कन्ट्रोल रूम पूल्ड आवास कालोनी स्थित सहायक अभियन्ता कार्यालय लोक निर्माण विभाग रोशनाबाद में बनाया जाये। पूल्ड आवास कालोनी में निवासरत अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा दर्ज कराई जा रही आवास मरम्मत आदि शिकायतों के कार्यों को प्राथमिकता एवं रजिस्टर के क्रम के अनुसार पूर्ण कराये जायें। पूल्ड आवास कालोनी के रखरखाव एवं अधिकारी, कर्मचारियों के आवासों में कराये जाने वाले सभी कार्यो की प्रत्येक माह समीक्षा की जायेगी। बैठक में अधिशासी अभियंता दीपक कुमार, अपर सांख्यिकीय अधिकारी सुभाष सिंह शाक्य, सहायक अभियन्ता कीर्ति नेगी एवं कनिष्ठ अभियन्ता सुनील कुमार उपस्थित रहे।

बिहार में ही होगी दवाओं की जांच, पटना को मिली अत्याधुनिक औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला

कैनविज टाइम्स संवाददाता

पटना। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती देने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण पहल की गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पटना में आज पटना के अगमकुआं स्थित जीएनएम प्रशिक्षण संस्थान, एनएमसीएम में 30 करोड़ रुपये की लागत से औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। यह प्रयोगशाला अत्याधुनिक सुविधा से लैस की गई है। इस प्रयोगशाला में अब राज्य में ही दवाओं और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच की जा सकेगी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा कि इससे स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी। उन्होंने कहा कि अब दवाओं और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए सैंपल कोलकाता जैसे शहरों नहीं भेजा जायेगा। उन्होंने कहा कि सैंपल की रिपोर्ट आने में पहले कई महीने लग जाते थे। मगर अब समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर पाना आसान होगा। इस नई प्रयोगशाला के शुरू होने से अब जांच न केवल तुरंत होंगी, बल्कि गलत व नकली दवाओं की पहचान कर उन्हें बाजार से हटाने में भी तेजी आएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि यह प्रयोगशाला बिहार की 13 करोड़ जनता के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की मजबूत गारंटी है। अब सरकार न केवल इलाज की बेहतर सुविधा दे रही है, बल्कि यह सुनिश्चित कर रही है कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण दवाएं ही उपलब्ध कराई जाएं।'' उन्होंने कहा कि इस पहल से जनता का स्वास्थ्य अधिकार और अधिक सुरक्षित होगा और यह केंद्र सरकार की ''सुरक्षित भारत, स्वस्थ भारत'' की परिकल्पना को भी मजबूती देगा। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष नन्द किशोर यादव, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य प्रत्यय अमृत, बीएमएसआईसीएल के एमडी दिवेश रामचन्द्र देवरे सहित अन्य अधिकारी और नेता मौजूद रहे। इस प्रयोगशाला में 28 आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, जिनके जरिए दवाओं और खाद्य पदार्थों की सूक्ष्म स्तर पर जांच संभव हो सकेगी। यह सुविधा राज्य को स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी और तकनीकी रूप से भी स्वास्थ्य विभाग को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी।

चेयरमैन एवं प्रधान सम्पादक - राकेश कुमार पाण्डेय   कार्यकारी सम्पादक* - अरशद सईद खान   स्टेट हेड - संदीप मिश्रा
स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश कुमार पाण्डेय द्वारा सरस्वती प्रिंटर्स वाटर वर्क्स रोड ऐशबाग, लखनऊ से मुद्रित एवं सी-46, कृष टॉवर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, पिन-226010 से प्रकाशित। * इस अंक में प्रकाशित सभी समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी।
समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय क्षेत्र के ही अधीन होंगे।   फोन नं। 0522-4249333 फैक्स नं.- 4249333 e-mail : info@kanwhizztimes.com   RNI NO - UPHIN/2012/42063